



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 16, 1974/कार्तिक 25, 1896

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 16, 1974/KARTIKA 25, 1896

इस भाग में मिला पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह इलग संकलन के क्षेत्र में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य भेद्र प्रशासनों को छोड़कर)
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities
(other than the Administrations of Union Territories)

मन्त्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

गृहिन्यन्त्र

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 1974

भारत निर्वाचन प्रायोग

आदेश

नई दिल्ली, 5 मिस्रम्बर, 1974

का० घा० 2973—भारत सरकार, मन्त्रिमण्डल सचिवालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के का० आ० म० 2075, दिनांक 1 अगस्त, 1974 के हिन्दी पाठ में, जो भारत के राजपत्र, भाग-II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) के पृष्ठ 2253 पर, 17 अगस्त, 1974 को प्रकाशित हुआ है,

पृष्ठ 2253 पर

उक्त आदेश की गान्धी परिवर्तन में,

“गोलपूरी” शब्द के स्थान पर “गोलमुरी” पढ़।

[स० ०२२८/२१/७४-एसीडी-२]

बी०-सी० वजानी, अवर मंत्रिव

का० घा० 2974.—यत निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि मार्च 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 141 वरड़िट निर्वाचन थेल से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जे० बी० बेसरा, ग्राम धरमपुर, पो० पतना, जिना साधारणरगना, लाक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा नद्दीन अनांग गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचित व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने से अमाफल रहे हैं,

और, यत उक्त उम्मीदवार ने उसे गम्भीर गूचना दिये जाने पर भी अपनी इस अप्रकल्पता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस अप्रकल्पता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीचित्य नहीं है,

अतः, अब उक्त प्रधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचित प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री जै० शौ० बेमरा को समद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्वित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०-स०/141/72(102)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 5th September, 1974

ORDERS

S.O. 2974.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri J. B. Besra, Village Dharampur, P. O. Pathna, District Santhal Parganas who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 141-Barhait constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri J. B. Besra to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/141/72(102)]

का०प्रा० 2975.—यतः, निर्वाचित प्रायोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचित के लिए 141-बरहैट निर्वाचित शेष से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मोहन हेमरम, श्राम धरमपुर, पो० पतना, भाया बरहरदा, जिला संथालपरगना, सोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचित व्ययों का कोई भी लेक्का दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और; यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचित प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अतः यत, उक्त प्रधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचित प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री मोहन हेमरम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्वित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०-स०/141/72(103)]

S.O. 2975.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mohan Hemram, Village Dharampur, P.O. Pathna via Barharwa, Santhal Parganas who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly

from 141-Barhait constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mohan Hemram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/141/72(103)]

का०प्रा० 2976:—यतः, निर्वाचित प्रायोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचित के लिए 141-बरहैट निर्वाचित शेष से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मीसी मरणी, श्राम मनमनी, पो० बरहैट, जिला संथालपरगना, सोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचित व्ययों का कोई भी लेक्का दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचित प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अतः यत, उक्त प्रधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचित प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री मीसी मरणी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्वित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०-स०/141/72(104)]

S.O. 2976.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Misi Marandi, Village Sanmani, P.O. Barhait, District Santhal Parganas who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 141-Barhait constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Misi Marandi to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/141/72(104)]

तर्फ दिल्ली, 19 सितम्बर, 1974

का. आ. 2977.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए मध्य प्रदेश विधान नगर के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 69-जैतपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अमर सिंह, गाव तथा पा० मलगा, जिला गढ़डोल लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत्; उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस अमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अत् अब, उक्त प्रधिनियम का धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एवं बिहार उक्त श्री अमर मिह को सदन के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुन जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्वाचित धारण करना है।

[म० मंप्र०वि०म०/69/72(52)]

New Delhi, the 19th September, 1974

S.O. 2977.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Amar Singh, Gram and Post Malga, District Shandol who was a contesting candidate for election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 69-Jaitpur (ST) constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Amar Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/69/72(52)]

का. आ. 2978.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 161-पोपालपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री लखन जयमवाल, गाम परवाना, पा० यात्रु परवाना भाया नौगंधिया, जिला आगरा-पुर लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यत्; उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस अमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अतः अब, उक्त प्रधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एवं बिहार उक्त श्री लखन जयमवाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुन जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[स० बिहार-वि०स०/161/72(111)]

S. O. 2978.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Lakhan Jaiswal, Village Parvatta, P. O. Sahu Parvatta via Nawgachia, District Bhagalpur who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 161-Gopalpur constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Lakhan Jaiswal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. BR-LA/161/72(111)]

का. आ. 2979.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 220 आहंनिया निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री लखननंद राम, गाम मंविधान, पा० मुठानी, शाहाबाद, लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत्; उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस अमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अतः अब, उक्त प्रधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एवं बिहार उक्त श्री लखननंद राम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुन जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[म० बिहार-वि०स०/220/72(114)]

S. O. 2979.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Lakhi Chand Ram, Village Machiaon, P.O. Muthani, Shahabud (Bihar) who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 220-Mohania (SC) constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Lakhi Chand Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-I A/220/72(114)]

का. आ. 2980.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 158-काठनगाव निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अरविन्द नाथ सिंहा, सिद्धेश्वर मदन, नया जक्कनपुर, पटना-1 सोक प्रतिनिधित्व प्रथिनियम, 1951 तथा नदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा शाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सुचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के प्रनुसरण में निर्वाचन आयोग एन्डवारा उक्त श्री अरविन्द नाथ सिंहा का संमद के किसी भी मदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के मद्द्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्हित घोषित करता है।

[मं बिहार-वि. स०/158/72(110)]

S. O. 2980.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Arvind Nath Sinha, Sedheshwar Sadan, Naya Jakkandpur, Patna-1 who was contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 158-Colgong constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Arvind Nath Sinha to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-I A/158/72(110)]

का. आ. 2981.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 162-बिहपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गम देव शर्मा, ग्राम अमरपुर, पां० जिला बभनगामा (भावा बिहपुर), जिला भागलपुर लोक प्रतिनिधित्व प्रथिनियम, 1951 तथा नदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा शाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सुचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त उम्मीदवार ने, श्री राम देव शर्मा को संमद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश भी तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्हित घोषित करता है।

[मं बिहार-वि. स०/162/72(106)]

S.O. 2981.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Deo Sharma, Village Amarapur, P.O. Babhangama (via Bihpur) District Bhagalpur who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 162-Bihpur constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Deo Sharma to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/162/72(106)]

का. आ. 2982.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 148-मारठ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बालेश्वर प्र० राय, ग्राम गजियाडीह, पतालय भारठ, जिला मंथाल पश्चिम लोक प्रतिनिधित्व प्रथिनियम, 1951 तथा नदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा शाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सुचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के प्रनुसरण में निर्वाचन आयोग एन्डवारा उक्त श्री बालेश्वर प्र० राय को संमद के किसी

भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य ने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[स० बिहार-वि०स०/ 148/72(109)]

S. O. 2982—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Waleshwar Pro. Rai, Village Gajadih, P. O. Sarath, District Santhal Parganas who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 148-Sarath constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Waleshwar Pro. Rai to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/148/72(109)]

का० आ० 2983.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 151-जरमुनी निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सूर्योदेव मुरम्, ग्राम भरैया, प०० चुलिया (बर्मामा) धारमारा जिला संथाल परगना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तर्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित आवश्यकता निर्वाचन व्यवों का कोई भी लेख दाखिल करने में अगफन रहे हैं,

श्रीर, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्पर्क मूल्यना दिये जाने पर भी, अपनी इस अगफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस अगफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या लायीचित्य नहीं है,

प्रत अब उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एवं द्वारा उक्त श्री नगदी प्रसाद राय का संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य ने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[स० बिहार-वि०स०/ 151/72(118)]

S. O. 2983.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nagdi Prasad Rai, Village Khairwan, P.O. Sarwan, District Santhal Parganas who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 151-Jarmundi constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Noy, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nagdi Prasad Rai to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/151/72(118)]

का० आ० 2984.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 151-जरमुनी निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सूर्योदेव मुरम्, ग्राम भरैया, प०० चुलिया (बर्मामा) धारमारा जिला संथाल परगना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तर्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित आवश्यकता निर्वाचन व्यवों का कोई भी लेख दाखिल करने में अगफन रहे हैं;

श्रीर, यत्, उक्त उम्मीदवार, ने, उसे सम्पर्क मूल्यना दिये जाने पर भी, अपनी इस अगफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस अगफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या लायीचित्य नहीं है;

अन्. अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एवं द्वारा उक्त श्री सूर्योदेव मुरम् को संसद् के निर्वाचन भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य ने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[स० बिहार-वि०स०/ 151/72(119)]

S. O. 2984.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Suryadev Murmu, Village Saraiya, P. O. Chulia, at present Ghormata, Santhal Parganas who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 151-Jarmundi constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Suryadev Murmu to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/151/72(119)]

का० आ० 2985.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 155-गोड़ा निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री किंवदी भा ग्राम गोरमंडा प०० जपरी जिला संथाल परगना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित

अपने निर्बाचन व्ययों का कोई भी लेखा शाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस अमरकलता के लिए कोई कारण अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्बाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस अमरकलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीकिय नहीं है;

अत यदि, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुमति में निर्बाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री त्रिवेनी ज्ञा को समझ के किसी भी सदन के या नियमों राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और उन्हें के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. बिहार-वि० म०/155/72(107)]

S. O. 2985.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Triveni Jha, Village Gorsanda, P. O. Chapari, District Santhal Parganas who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 155-Goda constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Triveni Jha to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this

[No. BR-LA/155/72(107)]

का० शा० 2996.—यदि, निर्बाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्बाचन के लिए 155-गांधा निर्बाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हृदय नारायण भगत, याम तुलसी किना, यो पथरगामा, जिस संघाल पार्गना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदीन बनाए गए नियम द्वारा अप्रक्षित अपने निर्बाचन व्ययों का कोई भी लेखा शाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यत् उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस अमरकलता के लिए कोई कारण अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्बाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस अमरकलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीकिय नहीं है;

अत यदि, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुमति में निर्बाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री अलाउदीन अल्लारी का समझ के किसी भी सदन के या नियमों राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और हांते के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. बिहार-वि० म०/155/72(108)]

S. O. 2986.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hariday Narayan Bhagat, Village Tulsi Kitta, P.O. Pathargama, District Santhal Parganas who, was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 155-Goda constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Hariday Narayan Bhagat to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/155/72(108)]

का० शा० 2987.—यत्, निर्बाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्बाचन के लिए 266-बरही निर्बाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अलाउदीन अल्लारी, याम बरही, हारारीजाग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदीन बनाए गए नियमों द्वारा अप्रक्षित अपने निर्बाचन व्ययों का कोई भी लेखा शाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत्; उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस अमरकलता के लिए कोई कारण अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्बाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस अमरकलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीकिय नहीं है;

अत यदि, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुमति में निर्बाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री अलाउदीन अल्लारी का समझ के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और हांते के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. बिहार-वि० म०/266/72(112)]

S. O. 2987.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Alaudin Ansari, Village and P. O. Barhi, District Hazaribagh (Bihar) who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 266-Barhi constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Alaudin Ansari to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/266/72(112)]

का० आ० 2988.—यह, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुा बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन के लिए 266-बर्ही निर्वाचन-थेट्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री प्रहलाद मिह ग्राम-पा० कदमा, जिला हजारीबाग लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा नदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यह, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास हम इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है,

अब, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण के निर्वाचन आयोग एनद्वारा उक्त श्री प्रहलाद मिह का समर के किसी भी मदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद के मध्य चुने जाने और होने के लिए इस शास्त्र की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[म० बिहार-वि०म०/266/72(113)]

S. O. 2988.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Prehlad Singh, Village & P. O. Kadma District Hazaribagh, who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 266-Barhi constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Prehlad Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. BR-LA/266/72(113)]

नई दिल्ली, ना० 23 मितम्बर, 1974

का० आ० 2989.—यह, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन के लिए 170-जाता निर्वाचन-थेट्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कैलाश यादव, ग्राम बलियारीही, पो० रजला भाया जाता (मुरोर) लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा नदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यह, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उपरोक्त पास हम इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अब, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण से निर्वाचन आयोग एनद्वारा उक्त श्री कैलाश यादव को समर के किसी भी मदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद के मध्य चुने जाने और होने के लिए इस शास्त्र की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[म० बिहार-वि०म०/170/72(120)]

New Delhi, the 23rd September, 1974

S.O. 2989.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kailash Yadav, Village Baliaidih, P. O. Rajla via Jhajha, District Monghyr who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 170-Jhajha constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kailash Yadav to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/170/72(120)]

नई दिल्ली, ना० 24 मितम्बर, 1974

का० आ० 2990.—यह, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन के लिए 170-सूर्य-गढ़ा निर्वाचन-थेट्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गंगा यादव, ग्राम बलालय शिवकुण्ड, जिला मुरोर लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा नदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यह, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उपरोक्त पास हम इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अब, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण से निर्वाचन आयोग एनद्वारा उक्त श्री गंगा यादव को समर के किसी भी मदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद के मध्य चुने जाने और होने के लिए हम शास्त्र की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[म० बिहार-वि०म०/170/72(121)]

New Delhi, the 24th September, 1974

S. O. 2990.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ganga Prasad Singh, Village & P.O. Sheokund, District Monghyr who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 176-

Surajgarh constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ganga Prasad Singh Yadav to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/176/72(121)]

नई दिल्ली ना० 25 मिनम्बर, 1974

का० आ० 2991.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हाए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 6-दिम्नी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री तोता राम, ग्राम पोरमा, माजरा, मानमुण्डपुरा, पा० पोरमा, तहसील आमबाहू, जिला मुरेना सोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा नद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित आपने निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा वालिन करने में असफल रहे हैं,

और, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अपवास्तुकरण नहीं दिया है और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीकार्य नहीं है;

यत् अब, उक्त उम्मीदवार की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एनद्वारा उक्त श्री तोता राम को संसद् के किसी सदन के या किसी ग्रामीण की विधान-सभा अपवास विधान परिषद् के सदस्य जूने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि विधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[म० म० प्र०-वि० म०/6/72(56)]

New Delhi, the 25th September, 1974

S. O. 2991.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Tota Ram, Village Porsa, Majra, Mansoorpura, Post Porsa, Tahsil Ambah, District Morena who was a contesting candidate for election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 6-Dimni constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Tota Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/6/72(56)]

का० आ० 2992.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 6-दिम्नी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री छट्टईया, ग्राम बादोमार, पा० मुरेना, जिला मुरेना लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम 1951 तथा नद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रिति से निर्वाचन व्यर्थों का लेखा वालिन करने में असफल रहे हैं,

और, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अपवास्तुकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीकार्य नहीं है;

अब अब उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एनद्वारा उक्त श्री छट्टईया को संसद् के किसी भी सदन के या किसी ग्रामीण की विधान-सभा अपवास विधान परिषद् के मदस्य जूने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[म० म० प्र०-वि० म०/6/72(57)]

S. O. 2992.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chhotaiya, Village Badokhar, Post Morena, District Morena who was a contesting candidate for election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 6-Dimni constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chhotaiya to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/6/72(57)]

का० आ० 2993.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 124-ग्रामतारी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कन्दैया लाल गोविन्दराम, गंगा भवन, रेयायपारा, घामतारी, जिला रायपुर लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा नद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित आपने निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा वालिन करने में असफल रहे हैं;

और, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अपवास्तुकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीकार्य नहीं है;

प्रत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के प्रनुसरण में निर्वाचन आयोग एनडब्ल्यूआर उक्त श्री बन्हौरा नाम गांगन्दराम थो संग्रह के किसी भी मदन के गा किसी राज्य की विधान-सभा प्रथमा विधान परिषद के गदस्य चुने जाने प्रीर हांने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्वाचन घोषित करता है।

[सू. माप्र-विम०/124/72(55)]

S. O. 2993.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kanhaiyalal Govindram, Ganga Bhawan, Ressatpara, Dhamtari, District Raipur who was a contesting candidate for election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 124-Dhamtari constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kanhaiyalal Govindram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/124/72(55)]

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 1974

का० आ० 2994.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 मे हुए असम विधान सभा के निर्वाचन के लिए 58-गोहाटी पूर्व सभा निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जिनेन्द्र चन्द्र हजारिका, हजारिका भवन, कालीचरन मेन रोड, पलटन बाजार, गोहाटी-S (असम), स्थान प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तदीन बनाए गए नियमों द्वारा घोषित घोषने निर्वाचन व्यवों का कोई भी नेत्रा वादित करते में असफल रहे हैं;

प्रौर, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, प्रौर निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीकरण नहीं है;

यत श्रव, उक्त अधिनियम की धारा 10-के प्रनुसरण में निर्वाचन आयोग एनडब्ल्यूआर उक्त श्री जिनेन्द्र चन्द्र हजारिका को भंगक के किसी भी मदन के गा किसी राज्य की विधान सभा प्रथमा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने प्रीर हांने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषत करता है।

[सू. असम वि स०/58/72]

New Delhi, the 22nd October, 1974

S. O. 2994.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jitendra Chandra Hazarika, Hazarika Bhavan, Kalicharan Sen Road, Paltan Bazar, Gauhati—8 (Assam) a contesting candidate for general election to the Assam Legislative Assembly held in March, 1972 from 58-Gauhati East 97 GI/74.—2.

constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jitendra Chandra Hazarika to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AS-LA/58/72]

का० आ० 2995.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 ने हुए असम विधान सभा के निर्वाचन के लिए 74-उदालगुरी (अ०ग०जा०) सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मोहन चन्द्र मेक, ग्राम गोरेकी गाँवी पो० तेजपुर, जिना दारंग, असम, स्थान प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदीन बनाए गए नियमों द्वारा घोषित घोषने निर्वाचन व्यवों का कोई भी नेत्रा वादित करते में असफल रहे हैं;

प्रौर, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, प्रौर निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीकरण नहीं है;

यत. श्रव, उक्त अधिनियम की धारा 10-के प्रनुसरण में निर्वाचन आयोग एनडब्ल्यूआर उक्त श्री मोहन चन्द्र मेक को सदस्य के किसी भी सदन के गा किसी राज्य की विधान सभा प्रथमा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने प्रीर हांने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषत करता है।

[सू. असम वि स०/74/72]

ए० एन० मैच, सचिव

S. O. 2995.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mohan Chandra Mech, Village Gereki Basti, P.O. Tezpur, District Darrang, Assam, a contesting candidate for General election to the Assam Legislative Assembly held in March, 1972 from 74-Udalguri (ST) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mohan Chandra Mech to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AS-LA/74/72]

A. N. SEN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 1974

का० आ० 2996.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया कि गार्च, 1972 में द्युये राजस्थान विधान सभा के निर्वाचन के लिये 54-तिजारा निर्वाचन क्षेत्र से चूनाव महने वाले उम्मीदवार श्री श्योदयाल पुत्र रामप्रभाकर जैन, ग्राम भटकोल, पौ० भोड़का, तहसील किशनगढ़ बाग, जिला अलवर (राजस्थान), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी नेतृत्व वालिक करने में असफल रहे हैं।

और, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्मक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अधिकार स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या व्यायोचित नहीं है;

अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुमरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री श्योदयाल को संवद के किसी भी सबूत के या किसी राज्य की विधान सभा अवधार विधान परिषद के सम्बन्ध चुने जाने और होने के लिये हय आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निर्णीत घोषित करता है।

[स० राज०-बि० स०/54/72(44)]

वी० नागसुब्रामण्यन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th October, 1974

S. O. 2996.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sheo Dayal, S/o Shri Ram Prasad Sen, Village Bhatkol, P.O. Mothuka, Tehsil Kishangarh-Bas, District Alwar, Rajasthan, a contesting candidate for General election to the Rajasthan Legislative Assembly held in March, 1972 from 54-Tijara constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sheo Dayal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/54/72(44)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy

विधि, व्याय तथा कार्यालय

(न्याय विभाग)

नोटिस

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1974

का० आ० 2997.—इसके द्वारा, लेख्य प्रमाणक नियम (नोटे-रीज रूल्स), 1956 के नियम 6 के अनुसार, सम्म आधिकारी द्वारा सूचना दी जानी है कि उक्त आधिकारी को श्री ब्रह्मा नन्द नागपाल, एडवाकेट जी०-28/5 ए, राजी गार्डन, न्यू डेल्ली-27 ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन, श्री लॉर्ड कोट्टम, रिट्ज मिनेपा के पीछे काश्मीरी गेट, देहली में लेख्य प्रमाणक (नोटरी) का काम करने की नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र भेजा है।

उक्त अविक्त के लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियां हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के बाद ही दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जायें।

[स० एफ० 22/31/73-न्याय]

के० त्याग राजन, सम्म आधिकारी तथा उप-सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(Department of Justice)

NOTICE

New Delhi, the 28th October, 1974

S. O. 2997.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Brahma Nand Nagpal, Advocate, G, 28/S-A, Rajouri Garden, New Delhi-27 for appointment as a Notary to practice in the Old Courts, Behind Ritz Cinema, Kashmiri Gate, Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 22/31/73-JUS]

K. THYAGARAJAN, Competent Authority
and Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1974

का० आ० 2998.—सरकारी स्थान (प्राधिकारीयों की बेदब्बली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने द्युये, केंद्रीय सरकार, प्रश्नावाल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के अधर सचिव (विधि) को, सरकार का राजपत्रिन अधिकारी होने के नामे, उक्त प्रधिनियम के प्रयोजनों के लिये सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो अपम, मेवानय राज्यों में और अन्य अधिकारीय संघ राज्य क्षेत्र में उक्त प्रशासन के व्ययन के अधीन सरकारी स्थानों की बाबत उक्त प्रधिनियम द्वारा या के अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त ग्रन्तियों का प्रयोग करेगा और अधिरोपित करन्वयों का पालन करेगा।

[स० य० 14016/2/74-ए० पी०]

जी० के० मनोज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 28th October, 1974

S.O. 2998.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central Government hereby appoints the Under Secretary (Law) of the Administration of the Union Territory of Arunachal Pradesh, being a gazetted officer of the Government to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officer by or under the said Act, in respect of the public premises under the disposal of the said Administration in the States of Assam, Meghalaya and in the Union Territory of Arunachal Pradesh.

[No. U. 14016/2/74-AP]

G. K. BHANOT, Joint Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

प्रावेश

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1974

का० आ० 2999.—धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुये, केन्द्रीय सरकार, नीचे श्री गंगा सारणी के स्तरम् (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति एवं उक्त सारणी के स्तरम् (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट पदनाम महित मूल्याकान अधिकारी नियुक्त करती है:

सारणी

क्रम सं	व्यक्ति का नाम	पदनाम
1	2	3
1	श्री पी० सी० शर्मा	मूल्याकान अधिकारी

[स० 79/74/का० स० 328/201/74-ध०क०]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

ORDER

New Delhi, the 21st September, 1974

S. O. 2999.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12A of the W.T. Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby appoints the person specified in column (2) of the Table below as Valuation Officer with the designation specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:

TABLE

S. No.	Name of the person	Designation
1	2	3
1.	Shri P.C. Sharma	Valuation Officer

[No. 79/74/F. No 328/201/74-W.T.]

प्रावेश

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1974

का० आ० 3000.—धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुये, केन्द्रीय सरकार, भिन्नतिक्षिण व्यक्तियों का पन्नान अंग्रहारी के रूप में नियुक्त करती है ग्राहीत्—

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम
	नर्सीत्री
1.	श्री० पी० याज्जोई
2.	कै० क० गुप्ता
3.	पी० एन० पाठक
4.	ए० एस० त्रिपाठी

[स० 80/74/का० स० 328/208/74-ध० क० (गोदर)]

श्री० डॉ० बाबारकर, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th September, 1974

S. O. 3000.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby appoints the following persons as Valuation Officers, namely:—

S. No.	Name of the person
	S/Shri
1.	O. S. Bajpai
2.	K. K. Shukla
3.	P. N. Pathak
4.	A. S. Tripathi

[No. 80/74/F. N. 328/208/74-WT (SHARES)]

V. D. WAKHARKAR, Under Secy.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1974

का० आ० 3001.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुये केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक अफ इण्डिया की भिकारिया पर, एन्वेट्रांग लोगिन करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपर्यन्थ धननामी बैंक लिं, विचूर द्वारा पाहनकुनम गांव, तोजुपदन डाकखाना, चम्पकगढ़ के निकट, त्रिपुर जिला में धून अचल परियमानि (6.02 एकड़ जमीन) के सम्बन्ध में उक्त बैंक पर 4 अक्टूबर, 1975 तक लागू नहीं होगे।

[म० 15(31)श्री० श्री० III/73]

(Department of Banking)

New Delhi, the 26th October, 1974

S. O. 3001.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of

the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act shall not apply to the Dhanalakshmi Bank Ltd., Trichur, in respect of the immoveable property (6 02 acres of land) held by it at Pyn-Kulam Village, Thozupadam, P.O. near Chelakkara, Trichur District, till the 4th October, 1975.

[No. 15(34)-B O. III/73]

का० आ० 3002— बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक भारत इडिया की सिफारिश पर, एतत्प्रारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपर्यन्थ, इस अधिनियम की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक यूनाइटेड बैंक भारत इडिया, कम्पनी पर वहाँ तक जागू नहीं होगे जहाँ तक कि उनका मानन्ध उक्त बैंक द्वारा यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक नियो, कलकत्ता के अधीक्षों के धारण में है।

[मा० 15(20)बी० आ० III/74]
मे० भा० उमगांधकर, भवर सचिव

S. O. 3002.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of The Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply to United Bank of India, Calcutta, for a period of one year from the date of this notification, in so far as they relate to its holding shares in the United Industrial Bank Ltd., Calcutta.

[No. 15(20)-B.O. III/74]
M. B. USGAONKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1974

का० आ० 3003.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक भारत इडिया की सिफारिश पर, एतत्प्रारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के उपर्यन्थ 1 मार्च, 1971 से 28 फरवरी, 1975 तक की अवधि के लिये डिबूगढ़ सेंट्रल कॉऑपरेटिव बैंक चि०, डिबूगढ़ पर जागू नहीं होंगे।

[स० एफ० 8-5/71-ग० सी०]

क० भवानी, भवर सचिव

New Delhi, the 31st October, 1974

S. O. 3003.—In exercise of the powers conferred by section 53 read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (1) of section 11 of the said Act shall not apply to the Dibugarh Central Co-operative Bank Ltd., Dibugarh for the period from the 1st March, 1974 to 28th February, 1975

[No. F. 8-5/74-AC]

K. BAVANI, Under Secy

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1974

का० आ० 3004.— रिजर्व बैंक भारत इडिया अधिनियम, 1934 के प्रत्युत्तरण में अक्टूबर, 1974 की 25 तारीख को गमान हुए समान्तर के लिए

नेत्रा इण्डू विभाग

देयताएं	रप्ते	रप्ते	आस्तियां	रप्ते	रप्ते
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	42,14,60,000		सोने का मिक्का और बुलियन	—	
			(क) भारत में रखा हुआ	1,82,52,68,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ		
संचालन में नोट	5957,41,45,000		विवेकी प्रतिभूतियां	1,41,73,97,000	
जारी किये गए नुल नोट		5999,56,05,000	जोड़		3,24,26,65,000
			रप्ते का मिक्का		19,93,83,000
			भारत सरकार की रप्ता प्रतिभूतियां		5655,35,57,000
			बैंकी विनियम वित्त और दूसरे		
			वाणिज्य-पत्र		
कुल देयताएं		5999,56,05,000	कुल आस्तियां		5999,56,05,000

2.5 अक्टूबर 1974 को रिजल बैंक आफ इंडिया के बंकिंग विभाग के कार्यकालाप का विवरण

देयताएं	रुपये	प्रास्तियां	रुपये
चुकता पृष्ठी	5,00,00,000	नोट	42,14,60,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का तिक्का	2,65,000
गण्डीय कृषि ऋण		त्रोटा तिक्का	3,81,000
(दीर्घकालीन प्रबर्तन) निधि	28,10,00,000	जरीदे और भुताये गये बिल	
गण्डीय कृषि ऋण		(क) देशी	108,09,76,000
(स्थिरीकरण) निधि	95,00,00,000	(ख) विदेशी	..
गण्डीय भौत्योगिक ऋण		(ग) सरकारी बजाराना बिल	654,61,50,000
(दीर्घकालीन प्रबर्तन) निधि	265,00,00,000	विदेशी में रखा हुआ भकाया*	459,25,51,000
जमाराशिया—		निवेश**	324,74,71,000
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम—	
(i) केन्द्रीय सरकार	57,16,99,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(ii) राज्य सरकारों	9,02,18,000	(ii) राज्य सरकारों को (a)	94,35,78,000
(ख) बैंक		ऋण भोर अग्रिम—	
(i) अनुमूलिक वाणिज्य बैंक	615,05,01,000	(i) अनुमूलिक वाणिज्य बैंकों	63,33,20,000
(ii) अनुमूलिक राज्य		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	270,86,46,000
महकारी बैंक	15,12,49,000	(iii) दूसरों को	7,14,50,000
(iii) और अनुमूलिक राज्य		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रबर्तन) निधि से	
महकारी बैंक	1,47,19,000	ऋण, अग्रिम और निवेश	
(iv) अन्य बैंक	49,95,000	(क) ऋण भोर अग्रिम—	
		(i) राज्य सरकारों को	67,82,39,000
		(ii) राज्य महकारी बैंकों को	14,63,10,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिक्यधक बैंकों को	..
		(iv) कृषि पुनर्वित निगम को	63,80,00,000
(ग) अन्य	368,09,27,000	(ख) केन्द्रीय भूमिक्यधक बैंकों के बिंचरों में निवेश	11,16,98,000
देय विल		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	
प्रत्य देयताएं	102,79,85,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	47,59,06,000
	583,85,08,000	राष्ट्रीय भौत्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रबर्तन) निधि	
		से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	226,19,13,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बोर्ड/डिब्बेचरों में निवेश	..
		अन्य प्रास्तियां	96,74,87,000
रुपये	2552,58,01,000	रुपये	2552,58,01,000

*नकदी, भावशिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रबर्तन) निधि और गण्डीय भौत्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रबर्तन) निधि से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

(ले) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रबर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों का किये गये अस्थायी और अप्रत्यक्ष शामिल हैं।

†रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के प्रतीन अनुमूलिक वाणिज्य बैंकों को भीयावी बिलों पर अग्रिम किये गये 21,82,00,000 रुपये शामिल हैं।

‡राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रबर्तन) निधि और गण्डीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

1 Now Delhi, the 1st November, 1974

S.O. 3004.—An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 25th day of October, 1974
Issue Department

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	42,14,60,000		Gold Coin and Bullion:-		
Notes in circulation	5957,41,45,000		(a) Held in India	182,52,68,000	
Total Notes issued	5999,56,05,000		(b) Held outside India		
			Foreign Securities	141,73,97,000	
			Total		324,26,65,000
			Rupee Coin		19,93,83,000
			Government of India Rupee Securities		5655,35,57,000
			Internal Bills of Exchange and other Commercial paper		..
Total Liabilities	5999,56,05,000		Total Assets		5999,56,05,000

S. JAGANNATHAN, Governor.

Dated the 31st day of October, 1974.

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 25th October, 1974.

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	42,14,60,000
		Rupee Coin	2,65,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	3,81,000
		Bills Purchased and Discounted:-	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	284,00,00,000	(a) Internal	108,09,76,000
		(b) External	
		(c) Government Treasury Bills	654,61,50,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	95,00,00,000	Baances Held Abroad*	459,25,51,000
		Investments**	324,74,71,000
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	265,00,00,000	Loans and Advances to:-	
		(i) Central Government	
		(ii) State Governments@	94,35,78,000
Deposits:-		Loans and Advances to:-	
(a) Government		(i) Scheduled Commercial Banks†	63,33,20,000
(i) Central Government	57,16,99,000	(ii) State Co-operative Banks‡	270,86,46,000
(ii) State Governments	9,02,18,000	(iii) Others	7,14,50,000
(b) Banks		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(i) Scheduled Commercial Banks	615,05,01,000	(a) Loans and Advances to:-	
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	15,12,49,000	(i) State Governments	67,82,39,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,47,19,000	(ii) State Co-operative Banks	14,63,10,000
(iv) Other Banks	99,95,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	
		(iv) Agricultural Refinance Corporation	63,80,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	11,16,98,000
(c) Others	368,09,27,000	Loans and Advances to State Co-operative Banks	47,59,06,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
Bills Payable	102,79,85,000	(a) Loans and Advances to the Development Bank	
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	226,19,13,000
Other Liabilities	583,85,08,000	Other Assets	96,74,87,000
RUPEES	2552,58,01,000	RUPEES	2552,58,01,000

* Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

** Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

† Includes Rs. 21,82,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17 (4) (c) of the Reserve Bank of India Act.

‡ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

S. JAGANNATHAN Governor.
[No. F. 10(1)/74-B.O.I.]

Dated the 31st day of October, 1974.

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1974

कांग्रेस 3005.—रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 के गतुमरण में अक्टूबर 1974 की 18 तारीख को समाप्त हुए गताह के लिए लेखा
(इशु विभाग)

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे	31,38,48,000		सोने का सिक्का और चुलियनः—		
कुप्रांत नोट			(क) भारत में रक्षा हुआ	182,52,68,000	
संचलन में नोट	60,07,64,10,000		(ख) भारत के बाहर रक्षा हुआ		
जारी किये गए कुल नोट	6039,02,58,000		विदेशी प्रतिमूलियां	141,73,97,000	
			जोड़		324,26,65,000
			रुपये का सिक्का		19,40,78,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिमूलियां		5695,35,15,000
			देशी विनियम बिल और दूसरे वाणिज्य-पद्धति		
कुल देयताएं	6039,02,58,000		कुल आस्तियां		6039,02,58,000

तारीख 23, अक्टूबर, 1974

एमंजगशाधन, गवर्नर

18 अक्टूबर, 1974 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूँजी	5,00,00,000	नोट	31,38,48,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	5,00,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	284,00,00,000	खारीदे गये और भुनाये गये बिल	3,54,000
राष्ट्रीय कृषि (स्थिरीकरण) निधि	95,00,00,000	(क) देशी	116,96,50,00
राष्ट्रीय श्रीबोगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	265,00,00,000	(ख) विदेशी	
जमाराशियाः—		(ग) सरकारी खजाना बिल	868,90,95,000
(क) सरकारी		विदेशों में रखा हुआ बकाया*	450,34,59,000
(i) केन्द्रीय सरकार	121,80,92,000	निवेश**	134,41,60,000
(ii) राज्य सरकार	5,95,50,000	ऋण और अग्रिमः—	
(ख) बैंक		(i) केन्द्रीय सरकार को	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	567,95,71,000	(ii) राज्य सरकारों को	95,61,63,000
(ii) अनुसूचित राज्य महकारी बैंक	11,83,59,000	ऋण और अग्रिमः—	
(iii) गैर अनुसूचित राज्य महकारी बैंक	1,56,82,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को	67,57,50,00000
(iv) अन्य बैंक	1,19,41,000	(ii) राज्य महकारी बैंकों को ††	265,33,68,000
		(iii) दूसरों को	4,64,50,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण	
		अग्रिम और निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम	
		(i) राज्य सरकारों को	67,82,39,000
		(ii) राज्य महकारी बैंकों को	14,68,90,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिक्षणक बैंकों को	
		(iv) कृषि पुनर्वित नियम को	63,80,00,000
(ग) अन्य	364,60,54,000	(ख) केन्द्रीय भूमिक्षणक बैंकों से विवेचने से राष्ट्रीय कृषि	
देय विल	113,04,47,000	ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	11,16,98,000
अन्य देयताएं	571,13,39,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	47,61,08,000
		राष्ट्रीय श्रीबोगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	
		से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	223,60,27,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये शांदो/झिंडों चरों में निवेश	
रुपये	2561,10,35,000	रुपये अन्य आस्तियां	97,12,76,000
			2561,10,35,000

* नकदी आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

** राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

† राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त कृषि और अग्रिम शामिल नहीं हैं; परन्तु राज्य सरकारों द्वारा दिये गये प्रस्तावी श्रीबोगिक ऋण का शामिल है।

†† रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम अंतर्गत 17(4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सीधारी विलों पर अग्रिम दिये गये 20,55,00,000 रुपये शामिल हैं।

††† राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त कृषि और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

तारीख 23 अक्टूबर, 1974

एमंजगशाधन, गवर्नर

[सं. क्र. 10(1)/74-वी.प्र० १]

च० च० मीरजमदानी, अधर सचिव

New Delhi, the 29th October, 1974

S.O. 3005.—An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 18th day of October, 1974

(Issue Department)

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department					Gold Coin and Bullion :—
Department	31,38,48,000		(a) Held in India	182,52,68,000	
Notes in circulation	6007,64,10,000		(b) Held outside India	
Total Notes issued	6039,02,58,000		Foreign Securities	14,73,97,000	
			Total	324,26,65,000	
			Rupee Coin	19,40,78,000	
			Government of India Rupee Securities	5695,35,15,000	
			Internal Bills of Exchange and other Commercial paper	
Total Liabilities	6039,02,58,000		Total Assets	6039,02,58,000	

S. JAGANNATHAN, Governor

Dated the 23rd day of October, 1974

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 18th October, 1974

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	31,38,48,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	5,00,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	284,00,00,000	Small Coin	3,54,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	95,00,00,000	Bills Purchased and Discounted :— (a) Internal	116,96,50,000
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	265,00,00,000	(b) External	868,90,95,000
Deposits :— (a) Government (i) Central Government	121,80,92,000	(c) Government Treasury Bills	450,34,59,000
	5,95,50,000	Balances Held Abroad*	134,41,60,000
		Investments**	
		Loans and Advances to :— (i) Central Government	95,61,63,000
		(ii) State Governments@	
		(iii) Scheduled Commercial Banks†	67,57,50,000
		(iv) State Co-operative Banks††	265,33,68,000
		(v) Others	4,64,50,000
		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to :— (i) State Governments	67,82,39,000
		(ii) State Co-operative Banks	14,68,90,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks	
		(iv) Agricultural Refinance Corporation	63,80,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank	11,16,98,000
		Debentures	
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	47,61,08,00
Rupees	2561,10,35,000	Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	223,60,27,000
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	
		Other Assets	97,12,76,000
			2561,10,35,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 20,55,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

S. JAGANNATHAN, Governor.

Dated the 23rd day of October, 1974.

[No. F. 10(1)/74-B.O-II]

C.W. MIRCHANDANI, Under Secy.

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 3rd September, 1974.

S.O. 3006.—In pursuance of clause (3) of Article 77 of the Constitution and of all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Delegation of Financial Powers Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Delegation of Financial Powers (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In rule 10 of the Delegation of Financial Powers Rules, 1958, (hereinafter referred to as the said rules) in sub-rule (2-A), for the portion beginning with the words, "The Administrator" and ending with the words "mentioned in that order", the following shall be substituted, namely:—

"The Administrator or Head of a Department may, by order, authorise a Gazetted Officer serving under him to exercise to such extent as may be specified in that order, any of the powers conferred on such Administrator or Head of the Department under sub-rule (1) or sub-rule (2)".

3. In the proviso to rule 14 of the said rules, after the words "may not be referred", the words "by the Ministries/ Departments of the Central Government, shall be inserted.

4. For Schedule I to the said rules, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE I

List of Head of Departments as on 31st October, 1973

[See rule 2(e)]

I—MINISTRY OF AGRICULTURE

A. Department of Agriculture:

1. Plant Protection Adviser, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, New Delhi.
2. Economic and Statistical Adviser, Directorate of Economic and Statistics, New Delhi.
3. Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing and Inspection, Faridabad.
4. Director of Administration, Directorate of Extension Training, New Delhi.
5. Chief Engineer, Central Groundwater Board, Faridabad.
6. Chairman, Delhi Milk Scheme, New Delhi.
7. President, Forest Research Institute and College, Dehradun.
8. Director, Tractor, Training and Testing Station, Budni.
9. Member Secretary, Agricultural Prices Commission.
10. Chief Co-ordinator of Projects, Pre-investment Surveys of Forest Resources, New Delhi.
11. Inspector General of Forests and Ex-officio Director of the Project Logging Training Centres.
12. Director, Tractor Training Centre, Hissar.
13. Member Secretary of the National Commission of Agriculture, New Delhi.
14. Director, Pre-investment Survey of Fishing Harbour Project, Bangalore.
15. Director, Tractor Training Centre, Mysore.
16. Chairman, Agriculture Price Commission, New Delhi.

17. Superintending Engineer, Deep Sea Fishing Station, Bombay.
18. Director, Central Institute of Fisheries Education, Bombay.
19. Director, Central Institute of Fisheries Operations, Cochin.
20. Director, Integrated Fisheries Project, Cochin.
21. Director of Agricultural Aviation.

B. Department of Food:

1. Chief Director, Directorate of Sugar and Vanaspati, New Delhi.
2. Director, National Sugar Institute, Kanpur.

II—CABINET SECRETARIAT

A. Department of Personnel:

1. Director, Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie.
2. Director, Central Bureau of Investigation.
3. Director, Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi.
4. Central Vigilance Commissioner.
5. Director, Enforcement.
6. Director of Revenue Intelligence, New Delhi.

III—MINISTRY OF COMMERCE

Department of Foreign Trade:

1. Director General, Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta.
2. Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi.
3. Textile Commissioner, Bombay.
4. Jute Commissioner, Calcutta.
5. Chairman Tarriff Commission, Bombay.
6. Custodian of Enemy Firms, Bombay.
7. Development Commissioner, Kandla Free Trade Zone.
8. Development Commissioner for Handicrafts.

IV—MINISTRY OF COMMUNICATIONS

1. Director General, Overseas Communications Service.
2. Wireless Adviser to the Government of India.

V—MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

A. Department of Culture:

1. Director General, Archaeological Survey of India.
2. Librarian, National Library, Calcutta.
3. Director, National Museum, New Delhi.

B. Department of Education:

1. Director, National Archives of India, New Delhi.
2. Director of Central Hindi Directorate, New Delhi.
3. Director, Asian Institute of Educational Planning and Administration, Delhi.
4. Director Anthropological Survey of India, Calcutta.
5. Chairman, Standing Commission for Scientific and Technical Terminology, New Delhi.

6. Director, Directorate of Adult Education, New Delhi.

VI—MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

Chief Pass-port Officer.

VII—MINISTRY OF FINANCE

A. Department of Expenditure :

Controller General of Defence Accounts.

B. Department of Revenue and Insurance:

1. Central Board of Excise and Customs.

2. Central Board of Direct Taxes.

3. Commissioners of Income Tax.

4. Collectors of Customs Bombay, Calcutta and Madras.

5. Collectors of Central Excise, Allahabad, Bangalore, Baroda, Bombay, Calcutta and Orissa, Delhi, Hyderabad, Kanpur, Madras, Nagpur, Patna, Poona, Shillong and West Bengal.

6. Narcotics Commissioner.

7. Director of Inspection (Income Tax).

8. Director of Inspection (Customs and Central Excise).

9. Director of Inspection (Investigation).

10. Director Inspection (Research Statistics and Publication).

11. Collector of Customs and Central Excise, Cochin.

12. Collector of Customs and Central Excise, Goa.

13. Gold Control Administrator, Regional Office of the Gold Control Administration, Bombay.

14. Chief Chemist, Central Revenues Control Laboratory, New Delhi.

15. Director, Emergency Risks Insurance Schemes, New Delhi.

16. Collector, Central Excise, Chandigarh.

17. Additional Commissioners of Income Tax.

18. Collectors of Customs (Preventive), Bombay.

19. Collectors of Central Excise, Ahmedabad, Guntur and Madurai.

20. Controller of Insurance, Simla.

21. Director of Training I.R.S. (Direct Taxes) Staff College, Nagpur.

C. Department of Economic Affairs:

1. National Savings Commissioner for India.

2. Master, India Government Mint, Alipore, Calcutta.

3. Master, India Government Mint, Bombay.

4. General Manager, and Ex-officio Controller of stamps Nasik Road, in respect of India Security Press, Nasik Road (including the Stamp Press, Currency note Presses and Central Stamp Stores).

5. General Manager, Silver Refinery, Calcutta.

6. General Manager, Security Paper Mills Project Hoshangabad.

7. Master, India Government Mint, Hyderabad.

8. Officer on Special Duty, Intaglio Press.

D. Department of Banking:

Administrator, Rehabilitation Finance Administration Unit, New Delhi.

VIII.—MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

Department of Health:

Director General, Health Services.

IX—MINISTRY OF HOME AFFAIRS

1. Director, Intelligence Bureau.

2. Director, National Commandant, Central Police Academy, Mount Abu.

3. Registrar—General and Ex-Officio Census Commissioned for India.

4. Director General, Central Reserve Police.

5. Commissioner for Linguistic Minorities, Allahabad.

6. Director of Co-ordination (Police Wireless) New Delhi.

7. Director General, Directorate General of Civil Defence.

8. Joint Director, Intelligence Bureau and ex-officio Special Inspector-General of Police Indo-Tibetan Border Police, New Delhi.

9. Inspector General of Assam Rifles.

10. Director General, Border Security Force.

11. Sector Commanders of the Border Security Force.

12. Inspectors General, Central Reserve Police Sectors I, II and III.

13. Inspector-General, Central Industrial Security Force.

14. Director, Bureau of Police Research and Development.

15. Director, Central Translation Bureau, New Delhi.

16. Director General, Backward Classes Welfare.

17. Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, India.

X—MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMFNT

Department of Industrial Development:

1. Director General Technical Development.

2. Chief Inspector of Explosives India.

3. Controller General of Patents Designs and Trade Marks.

4. Developmnt Commissioner, Small Scale Industries.

5. Salt Commissioner.

6. Economic Adviser to the Government of India.

7. Director General, Research and Development Organisation for Electrical Industry, Bhopal.

8. Chairman, Bureau of Industrial Costs and Prices.

XI—MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

1. Chairman, Central Water and Power Commission.

2. General Manager, Farakka Barrage Project.

3. Chairman, Central Electricity Authority.

4. Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Farakka Barrage Project.

XII.—MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

1. Director General, All India Radio.

2. Principal Information Officer, Press Information Bureau.

3 Controller-cum Chief Producer, Films Division, Bom
bay

4 Director, Publications Division, Delhi

5 Director of Advertising and Visual Publicity

6 Director of Field Publicity

7 Registrar of News Papers for India

8 Director Song and Drama Division

9 Chairman, Central Board of Film Censors, Bombay-6

10 Director, Film and Television Institute of India,
Poona

**XIII—MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITA
TION**

A Department of Rehabilitation

1 Chief Administrator, Dandakanya Project

2 Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Dandakanya Project

3 Chief Settlement Commissioner
of Employment and Training

4 Chief Pay and Accounts Officer (Rehabilitation)

5 Chief Development cum Rehabilitation Commissioner

6 Chief Commandant Mana Group of Transit Centres,
Mana, Raipur (M P)

7 Chief Mechanical Engineer Rehabilitation, Jeypore, Dis-
trict Koraput (Orissa)

B Department of Labour and Employment

1 Director of Employment Exchanges, Directorate General

2 Director of Training

(i) Directorate General of Employment and Training
(in respect of the Central Training Institutes) Cal-
cutta Madras/Bihar/Hyderabad/Ludhiana/Kanpur
and New Delhi

(ii) Central Staff Training and Research Institute, Cal-
cutta

(iii) Advanced Training Institute, Madras

(iv) Foreman, Training Institute, Bangalore (under his
control)

3 Chief Labour Commissioner, New Delhi (Central).

4 Director General, Factory Advice Service and Labour
Institutes

5 Director, Labour Bureau, Simla

6 Director General of Mines Safety, Dhanbad.

7 Coal Mines Welfare Commissioner, Dhanbad

8 Welfare Commissioner, Mica Mines Labour Welfare
Fund Dhanbad

9 Welfare Commissioner, Mica Mines Labour Welfare
Fund Advisory Committee for Rajasthan in respect of the
Mica Mines Labour Welfare Fund Organisation in Rajas-
than.

10 Welfare Commissioner, Mica Mines Labour Welfare
Fund Advisory Committee for Andhra in respect of the
Office of the Mica Mines Labour Welfare Fund Organisa-
tion in Andhra Pradesh

11 Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore
Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee for the
State of Andhra Pradesh in respect of the Office of the
Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore Mines
Labour Welfare Fund Andhra Pradesh

12 Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore
Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee for the

State of Bihar in respect of the Office of the Iron Ore
Mines Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Labour Wel-
fare Fund Advisory Committee for Bihar

13 Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore
Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee for the
State of Orissa in respect of the Office of the Iron Ore Mines
Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Labour Welfare Fund
Advisory Committee, Orissa

14 Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore
Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee for the
State of Madhya Pradesh in respect of the Office of the
Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore Mines
Labour Welfare Fund Advisory Committee for Madhya Pra-
adesh

15 Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore
Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee for Goa,
Daman and Diu in respect of the Office of the Iron Ore
Mines Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Labour Wel-
fare Fund Advisory Committee for Goa, Daman and Diu

16 Director of Employment Exchanges, Directorate
General of Employment and Training in respect of Labour
Depot, Gorakhpur

17 Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore
Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee for the
State of Mysore in respect of the Office of the Iron ore Mines
Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Labour Welfare
Fund Advisory Committee, Mysore

18 Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Iron Ore Mines
Labour Welfare Fund Advisory Committee for the State
of Maharashtra in respect of the Office of the Iron Ore Mines
Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Labour Welfare Fund
Advisory Committee, Maharashtra

19 Director of Employment Exchanges, Directorate Gen-
eral of Employment and Training in respect of the following
offices —

(i) Vocational Rehabilitation Centre for Physically
Handicapped, Kurla-Bombay-70/Hyderabad-7

(ii) Office of the Employment Liaison Officer for Re-
habilitation of East Pakistan Migrants, Mana-
Camp, Raipur, Madhya Pradesh

(iii) Office of the Officer on Special Duty, Special Cell,
Farrakka Barrage Project, Calcutta (West Bengal)

(iv) Office of the Sub-Regional Employment Officer
Coaching-cum-Guidance Centre for Scheduled
Castes and Scheduled Tribes, Delhi/Kanpur (U P),
Jabalpur (M P), Madras (Tamil Nadu)

20 Member-Secretary of the Expert Committee on Un-
employment.

21 Director of Employment Exchange, Director General
of Employment and Training in respect of the following
office —

Central Institute for Research and Training in Emp-
loyment Service, Pusa, New Delhi

**XIV—MINISTRY OF LAW, JUSTICI AND COMPANY
AFFAIRS**

A Department of Legal Affairs

President, Income Tax Appellate Tribunal

B Legislative Department

Chief Selection Commissioner

C Department of Company Affairs

Chairman, Monopolies and Restrictive Trade Practices
Commission.

XV(a).—MINISTRY OF PLANNING

Department of Statistics:

1. Director, Field Operations Division, National Sample Survey Organisation, New Delhi.
2. Director, Central Statistical Organisation, New Delhi.
3. Director, Computer Centre, New Delhi.
4. Director-in-Charge, Data Processing and Survey Design and Research Division.

XV(b)—MINISTRY OF STEEL AND MINES

A. Department of Steel :

Iron and Steel Controller, Calcutta.

B. Department of Mines :

1. Coal Controller, Calcutta.
2. Director General, Geological Survey of India, Calcutta.
3. Controller, Indian Bureau of Mines, Nagpur.
4. Chairman and Managing Director, Kolar Gold Mining Undertaking.

XVI—DEPARTMENT OF SUPPLY

1. Director General Supplies and Disposals.
2. Chief Pay and Accounts Officer.
3. Director, National Test House, Calcutta.

XVII—MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(Transport Wing)

1. Director General of Shipping, Bombay.
2. Director General of Light Houses and Light Ships.
3. Government Director on the Board of Directors of Indian Shipping Companies, Bombay.
4. Chairman, Inter-States Transport Commission.
5. Principal Officers, Mercantile Marine Department, Bombay, Calcutta and Madras.
6. Chief Engineer, Andaman, Laccadive Harbour, Works.
7. Chief Engineer-cum-Administrator of the Directorate of Inland Water Transport.
8. Chief Engineer and Administrator, Mangalore Harbour Project.
9. Chief Engineer and Administrator, Tuticorin Harbour Project.

XVIII—DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. Surveyor General, Survey of India, Dehradun.
2. Director, Zoological Survey of India, Calcutta.
3. Director, Botanical Survey of India.
4. Director, National Atlas Organisation, Calcutta-19.

XIX—MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

1. Director General of Civil Aviation.
2. Director General of Observatories.
3. Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
4. Additional Commissioner of Railway Safety, Western Circle, Bombay.

5. Additional Commissioner of Railway Safety, North Eastern Circle, Calcutta.
6. Additional Commissioner of Railway Safety, Northern Circle, Lucknow.
7. Chairman, Town and Country Planning Organisation, Circle, Bangalore.
8. Director General of Tourism.

XX—MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

1. Engineer-in-Chief, Central Public Works Department.
2. Director of Printing.
3. Controller of Stationery.
4. Controller of Publications.
5. Director of Estates.
6. Director, National Building Organisation.
7. Chairman, Town and Country Planning Organisation.

XXI—UNION TERRITORIES

- (a) Delhi Administration :
Inspector-General of Police, Delhi State.
- (b) Pondicherry Administration :
Chief Secretary, Pondicherry Administration.
- (c) Andaman and Nicobar Islands Administration :
1. Chief Conservator of Forests, Andaman and Nicobar Islands.
2. Chief Secretary, Andaman and Nicobar Administration.
3. Development Commissioner-cum-Development Secretary, Andaman and Nicobar Administration.
4. Deputy Commissioner, Andaman and Nicobar Administration.
5. Principal Engineer, Andaman P.W.D.
- (d) Chandigarh Administration :
1. Chief Engineer, Capital Project, Chandigarh.
2. Director, Post Graduate Institute, Chandigarh.
3. The Principal, Punjab Engineering College, Chandigarh.
4. Controller of Printing and Stationery, Chandigarh.
5. Professor, Punjab Engineering College, Chandigarh and ex-officio Director, Technical Education, Chandigarh.
- (e) Dadra and Nagar Haveli Administration :
Collector of Dadra and Nagar Haveli.
- (f) Goa, Daman and Diu :
1. Chief Secretary.
2. Director of Accounts.
3. Collector of Daman.
4. Development Commissioner.
5. Collector of Goa.
6. Secretary, Industries and Labour, Goa, Daman and Diu.
7. Judicial Commissioner.
8. Secretary to the Lt. Governor of Goa, Daman and Diu.
9. Chief Electrical Engineer, Goa.
10. Principal Engineer P.W.D. Goa, Daman and Diu.
11. Director of Education, Goa, Daman and Diu.

(g) Arunachal Pradesh :
Chief Secretary.

(h) Mizoram :
Chief Secretary.

(i) North Eastern Council :
Secretary."

5. In the Annexure to Schedule V to the said rules, for item 16, the following item shall be substituted, namely:—

"16. Printing and Binding Full powers where the printing is executed through or with the approval of the Director of Printing.

1. The expenditure shall be incurred subject to the provisions of the rules for printing and binding and any other orders that the administrative Ministry of the Directorate of Printing may lay down from time to time. Normally, the entire printing and binding work is executed through the Director of Printing who will raise necessary debits against the budget head of account of the department concerned for the printing work done by him.

NOTE : Ordinarily a Government Press will not accept any order for printing of pamphlets, publications, booklets, reports, etc. if the number of copies required is less than 500. The requisite number of copies may be got cyclostyled by the Departments themselves. Printing at private presses may be resorted to only in exceptional cases. If desired, printed covers may be got made and the pamphlets etc., stapled or wire stitched and trimmed by local arrangements through private presses, if necessary. A Government Press will not accept any order for the printing of a Special Form if the number of copies required is less than 3,000 and in such cases, the Ministry/Department concerned should get the requisite copies cyclostyled or get them printed through private presses. In all these cases, the Ministries/Departments shall have full powers without any monetary limit for Printing/Binding, at private presses. Scrutiny of printers' bills and payment thereof shall be made direct by the Ministries/Departments themselves.

2. The following authorities may get their emergent and unforeseen petty printing and binding jobs executed locally through private agencies upto the monetary limits indicated against them, which shall include the cost of paper and other binding materials:—

- (i) Ministries Rs. 2,000 per annum.
- (ii) Heads of Rs 1,000 per annum. Departments
- (iii) Heads of Rs 500 per annum. Offices.

The cost of printing and binding job executed through private agencies shall be debited against the Head of Expenditure on Printing and Publications. No approval of rates by the Director of Printing is necessary.

3. Where in respect of emergent and special cases the cost printing and binding executed locally through private agencies exceeds the monetary limit specified in paragraph 2 and the Ministry/Department of the Government of India considers it essential to get such jobs executed through private agencies, such Ministry/Department may, if the rates to be paid to such private agencies do not exceed those admissible under the Schedule of Rates maintained for the time being by the Director of Printing, get the jobs executed through such private agencies without obtaining the approval of the Director of Printing. The scrutiny of bills and payment to printers will be made direct by the Ministry/Department and the Director of Printing shall, if so required, render assistance in drawing up specifications and conditions of contract:

Provided that where it is proposed to entrust jobs to private agencies in excess of the rates specified in the Schedule of Rates referred to above, the Ministry/Department may decide each case in consultation with its associated Finance."

6. In Schedule VII to the said rules, in the Table.—
(a) in the entry "Deficiencies and Depreciation in the

value of stores included in the stock on other accounts," after the words "value of stores", the brackets and words "(other than a motor vehicle or a motor cycle)" shall be inserted;

(b) after the entry as so amended, the following entry shall be inserted, namely:—

"Condemnation of motor vehicles and motor cycles of Central Government. Rs. 25,000—This power may be exercised subject to the following restrictions, namely:—

(a) the lives of various types of vehicles, in terms of distance run (in kilometers) and length of use (in years) whichever is reached later, have been fixed as under:—

	Kilo-meters	Year
(i) Heavy Commercial motor vehicles.	2,00,000	10
(ii) Motor vehicles fitted with less than 18 H.P. (R.A.C.)	1,20,000	6
(iii) Motor cycles fitted with engines of 3.5 H.P. (R.A.C.) or above.	80,000	5

	Kilometers years	
(iv) Motor cycles fitted with engines of less than 3.5 H.P. (R.A.C.)	48,000	5
(b) A vehicle in the Union territory of Delhi should be condemned only after a certificate has been obtained from the Electrical and Mechanical Officer, Civil Aviation Department through the Ministry of Tourism and Civil Aviation or the Delhi Transport Corporation through the Ministry of Shipping and Transport to the effect that the vehicle is not fit for any further economical use. At places outside the Union territory of Delhi, a certificate as aforesaid from a similar technical authority will be necessary for condemning a vehicle."		

[No. F. 1(9)-E.II(A)/72]

G.S. RATHIE, Under Secy.

New Delhi, the 9th October, 1974

S.O. 3007.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and of all other powers enabling him in this behalf, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in respect of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Contributory Provident Fund (India) Fifth Amendment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, in sub-rule (4) of rule 12, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that where a subscriber on deputation to a body corporate, owned or controlled by the Government, is subsequently absorbed in such body corporate with effect from a retrospective date, for the purpose of calculating the interest due on the Fund accumulations of the subscriber, the date of issue of the orders regarding absorption shall be deemed to be the date on which the amount to the credit of the subscriber became payable subject, however to the condition that the amount recovered as subscription during the period commencing from the date of absorption and ending with the date of issue of orders of absorption shall be deemed to be subscription to the Fund only for the purpose of awarding interest under this sub-rule".

[No. F. 16(2)-E.V.(B)/72]

New Delhi, the 14th October, 1974

S.O. 3008.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and of all other powers enabling him in this behalf the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in respect of persons employed in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Tenth Amendment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 34 of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, in sub-rule (3), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

"(i) To enable a subscriber to submit an application for withdrawal of the amount in the Fund, the Head of Office shall send to every subscriber necessary forms either one year in advance of the date on which the subscriber attains the age of superannuation, or before the date of his anticipated retirement if earlier, with instructions that they should be returned to him duly completed with a period of one month from the date of receipt of the forms by the subscriber. The subscriber shall submit the application to the Accounts Officer through the Head of Office or Department for payment of the amount in the Fund. The application shall be made—

(A) for the amount standing to his credit in the Fund as indicated in the Accounts Statement for the year ending one year prior to the date of his superannuation, or his anticipated date of retirement, or

(B) for the amount indicated in his ledger account in case the Accounts Statement has not been received by the subscriber."

[No. 2(62)(i)-E.V.(B)/71-GPF]

V. K. PANDIT, Dy. Secy.

बाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1974

(इलायची नियंत्रण)

का० आ० 3009—इलायची अधिनियम, 1965 (1965 का 42) की धारा 4 की उपधारा (4) के माध्यम से उपधारा 3 के खण्ड (क) धारा प्रदत्त विविधों का प्रयाग करने हुए भारत सरकार द्वारा दी० श्री० स्वामीनाथन के साथ पर श्री के० वा० जार्ज, निदेशक, इलायची विधायक इनायती द्वारा, एनकुलम को 14 जून, 1974 के प्रारंभ से 24 जून 1974 के पूर्वान्तर तक, जिसमें वह भी शामिल है, इलायची द्वारा के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है।

ध्याक्षात्मक ज्ञान

इलायची द्वारा, एनकुलम के अध्यक्ष का पद एक साधिकार पद है, जिसमें काफी उन्नतायित्र अन्वयन है और इसे आली नहीं रखा जा सकता। श्री दी० श्री० स्वामीनाथन, अध्यक्ष, इलायची द्वारा, एनकुलम को तबादला करके केवल सरकार को वापस भेज दिया गया था और नक्षमुक्त श्री के० वा० जार्ज, निदेशक, इलायची द्वारा को भूत्याकी अध्यक्ष के रूप में श्री स्वामीनाथन से इलायची द्वारा के अध्यक्ष के पद का कार्यभार सम्बालने के लिए तारांतारा कहा गया था। श्री जार्ज ने 14-6-74 (प्रारंभ) को अध्यक्ष पद का कार्यभार समाप्त नियमित किया। इस अधिसूचना को भूत्याकी प्रभाव से लागू करने के प्रसारा और कोई विकल्प नहीं है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि इस भूत्याकी प्रभाव से इसको लागू करने से इलायची द्वारा में किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[स० 29(5)/74-सांट (बी)]

(Cardamom Control)

New Delhi, the 4th November, 1974

S.O. 3009.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3), read with sub-section (4) of section 4 of the Cardamom Act, 1965 (42 of 1965), the Central Government appoints Shri K. V. George, Director of Cardamom Development, Cardamom Board, Ernakulam, as Chairman of the Cardamom Board for the period commencing from the afternoon of the 14th June, 1974 upto and inclusive of the forenoon of the 24th June, 1974, in place of Shri T. V. Swaminathan.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The post of Chairman, Cardamom Board, Ernakulam, is a statutory post involving considerable responsibilities and it cannot be kept vacant. Shri T. V. Swaminathan, the Chairman, Cardamom Board, Ernakulam, was transferred back to the Government of Kerala and accordingly Shri K. V. George, Director, Cardamom Board, was telegraphically asked to take over charge of the post of Chairman, Cardamom Board from Shri Swaminathan as a temporary arrangement. Shri George took over charge of the post of Chairman on 14-6-1974 (afternoon). This date was known to the Ministry only on receipt of the Charge Report on 20-6-1974. Thus it was not possible to issue the notification earlier without knowing the exact date of assumption of charge of the post of Chairman, Cardamom Board. There is, therefore, no alternative but to give effect to this notification retrospectively in order to regularise the statutory functions performed by him. It may also be stated that this giving of retrospective effect will not adversely affect anybody in the Cardamom Board.

[No. 29(5)/74-Plant(B).]

का० प्रा० 3010.—इलायची अधिनियम, 1965 (1965 का 42) की धारा 4 की उपधारा (4) के साथ पठित उपधारा (3) के बाईं (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए भारत सरकार श्री के० वी० जार्ज के स्थान पर प्रोफेसर के० एम० चांदी, अध्यक्ष, रबड़ बोर्ड, कोट्टयम को 24 जून, 1974 के पूर्वाह्न में उनके अपने कार्यभार के अतिरिक्त इलायची बाईं, एर्नाकुलम के प्रध्यक्ष के पद पर एतत द्वारा नियुक्त करती है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इलायची बोर्ड एर्नाकुलम के प्रध्यक्ष का पद एक मांविधिक पद है, जिसमें काफी उन्नरणायित्व अन्वर्गस्त है और इसे खाली नहीं रखा जा सकता।

श्री के० वी० जार्ज, निदेशक, इलायची बाईं को अस्थायी रूप में निदेशक के रूप में अपने कार्यभार के अतिरिक्त इलायची बाईं के प्रध्यक्ष का कार्यभार संभालने के लिए कहा गया था, बाद में यह विनिश्चय किया गया कि प्रोफेसर के० एम० चांदी, अध्यक्ष, रबड़ बोर्ड, कोट्टयम को प्रध्यक्ष रबड़ बोर्ड, कोट्टयम के रूप में अपने कार्यभार के अतिरिक्त श्री के० वी० जार्ज से इलायची बोर्ड के प्रध्यक्ष के पद का कार्यभार संभालने के लिए कहा गया और इस मंबंध में तार द्वारा ग्रावश्यक अनुदेश जारी कर दिए गये थे। प्रोफेसर के० एम० चांदी द्वारा इस पद का कार्यभार संभालने की तारीख मंत्रालय को केवल 29 जून, 1974 को जात की गई। प्रोफेसर के० एम० चांदी द्वारा इलायची बोर्ड के प्रध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण की तारीख पना न होने से, अधिसूचना पहले जारी न की

जा सकी। प्रतः प्रोफेसर के० एम० चांदी द्वारा इलायची बोर्ड के प्रध्यक्ष के रूप में पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से किये गये कार्यों को नियमित करने के लिए इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के अनावा और कोई विकल्प नहीं है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि भूतलक्षी प्रभाव से इसे लागू करने से इलायची बाईं में किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पहुँचेगा।

[मं० 29(5)/74-प्लाट(बी)]

प्रम० महादेव प्रायर, प्रब्र. सचिव

S.O. 3010.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3), read with sub-section (4), of section 4 of the Cardamom Act, 1965, (42 of 1965), the Central Government hereby appoints Prof. K. M. Chandy, Chairman, Rubber Board Kottayam, as chairman of the Cardamom Board, Ernakulam, in addition to his own duties as Chairman, Rubber Board, with effect from the forenoon of the 24th June, 1974, in place of Shri K. V. George.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The post of Chairman, Cardamom Board, Ernakulam is a statutory post involving considerable responsibilities and it cannot be kept vacant.

As Shri K. V. George, Director, Cardamom Board, was requested as a temporary measure to take charge of the post of Chairman, Cardamom Board, in addition to his own duties as Director, it was later decided that Prof. K. M. Chandy, Chairman, Rubber Board, Kottayam should be asked to take over charge of the post of Chairman, Cardamom Board, in addition to his own duties as Chairman, Rubber Board, Kottayam, from Shri K. V. George and necessary telegraphic instructions were issued to this effect. The date of taking over charge of this post by Prof. K. M. Chandy became known to the Ministry only on 29th June, 1974. In the absence of the date of assumption of charge of the post of Chairman, Cardamom Board, Ernakulam by Prof. K. M. Chandy, the notification could not be issued earlier. There is, therefore, no other alternative but to give this notification retrospective effect in order to regularise the statutory functions performed by Prof. K. M. Chandy as Chairman of the Cardamom Board from the date of assumption of charge of the post. It may also be stated that this giving of retrospective effect will not adversely affect anybody in the Cardamom Board.

[No. 29(5)/74-Plant(B).]

S. MAHADEVA IYER, Under Secy.

संपूर्ण-मुक्त नियंत्रक, प्रायान-नियंत्रि का कार्यालय,

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1974

आदेश

का०प्रा० 3011.—मर्वश्री चावला एंड कं० १९९६, बलवेल भवन, मराय लैसिला न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली को सामान्य श्रेष्ठ से अनुद्वा हाई मोलिक्यूलर बेट हाई डेस्ट्रीटी मोलिडग पाउडर प्रादि के आगाम के लिए ५०००/-०० का आयात नाइसेम संख्या पी/एस/ १८०३४५७/सी, दिनांक २-१२-७३ स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त नाइसेम की अनुलिपि सीमाशुल कार्य मंबंधी तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों के लिए इस आधार पर आदेश किया है कि उस की मूल प्रतिया बिल्कुल उपयोग किए जिना ही जो गई/अस्थायन्त्र हो गई है।

प्रावेदकों को अब आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रियाविधि 1973-74 की कंडिका 320(4) की व्यवस्था के अनुसार उक्त दोनों लाइसेंसों की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रतियां जारी की जा रही है।

[एफ० संवाद एन पी/सी-2/ए एम-74/एय०-नूटी/सी एल ए/1707]

के० आर० धीर, उप मुख्य नियंत्रक,

हाते संयुक्त मुद्र्य नियंत्रक

S.O. 3013.—M/s. Chawla & Co. 986, Baldeo Bhavan, Sarai Rohilla, New Rohtak Road, New Delhi were granted licence Nos. P/S/1801547 and 1801548 both dated 12-7-73 under Actual User Category for import of P.T.F.E. Resins.

They have applied for the issue of DUPLICATE EXCHANGE CONTROL COPIES OF BOTH THE LICENCES on the ground that the original copies thereof have been lost/misplaced having been fully utilised.

The applicants have filed affidavit in support of the above statement, as required under Para 320 of I.T.C. Hand Book of Rules & Procedure, 1973-74, I am satisfied that the original copies of the said licences have been lost/misplaced.

In exercise of the powers conferred on me, under Section 9(cc) of import Control Order, 1955 dated 7-12-1955. I order the cancellation of the said copies of the licences.

The applicants are now being issued DUPLICATE COPIES (EXCHANGE CONTROL COPIES OF BOTH LICENCES) in accordance with the provision of Para 320(4) of the I.T.C. Hand Book of Rules & Procedure, 1973-74.

[No. NP/C-2/AM. 74/AU. UT/CLA/1707]

K. R. DHEER, Dy. Chief Controller
for Jt. Chief Controller

समाहृती कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

गुरुरू, 18 जून, 1974

का० प्रा० 3014.—1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के 5वें नियम के सत्तर्वें प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं उन भारी अधिकारियों को जो सहायक समाहृती में नीचे के पश्च के नहीं हैं, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में, संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में बताए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अधीन स्तम्भ 4 में निर्दिष्ट सीमाओं तक, समाहृती की शक्ति के प्रयोग का प्राधिकार प्रदान करता हूँ।

अम सं० के० उत्पाद केन्द्रीय उत्पाद सीमाएं यदि कोई ही शुल्क नियम शुल्क के अधिकारी का पर

1 2 3 4

1. नियम 173 जी० (1) सहायक समा- निर्धारिती को चेक द्वारा शुल्क (चेक द्वारा शुल्क हर्ता तथा उनसे अदा करने की अनुमति की भवायगी) ऊंचे पद के अधिकारी। कुछ परिस्थितियों के अतिरिक्त जिनमें निर्धारिती को, चेक अस्वीकृत करने (या चेक

का बुश्ययोग करने) पर इस सुविधा का प्रयोग करने से वचित कर दिया है या तस्वीरात् उसे पुनः इसका प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई है, अत्यथा सहायक समाहृती या उससे ऊंचे पद वाले अधिकारी द्वारा दी जाएगी।

2. नियम 9 सहायक समाहृती तथा उनसे आलू खाता समाहृती के नाम ऊंचे पद के अधिकारी। से ग्राह जाएगा।

टिप्पणी—1. इस संबंध में सहायक समाहृती द्वारा अनुमति प्रदान की जानी चाहिए किन्तु प्रत्येक स्थिति में उन्हें इसकी सूचना समाहृती तथा शुल्क सेखा अधिकारी को देनी होती।

2. सहायक समाहृती वैक द्वारा शुल्क प्रदा करने की अनुमति नहीं देते तो ऐसी अवस्था में निर्धारिती इसके विरुद्ध समाहृती के समक्ष जो कि अधीकारी भी है, प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

3. इस समाहृती कार्यालय की विनाक 4-6-71 की अधिसूचना सं० 1/71 की क्रम सं० 2 के साथे स्तम्भ 4 में की गई प्रविष्ट ऊपरोक्त सीमा तक संशोधित की जाती है।

[अधिसूचना सं० 2/74 के० उत्पाद —फा० सी० सं०—IV/8/1/74-एम पी०-2 से जारी की गई] ए० एस० धाई० जाफर, समाहृती

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE

Guntur, 18th June, 1974

S.O. 3014.—In exercise of the powers conferred upon me under rule 5 of Central Excise Rules, 1944, I authorise all Officers not below the rank of Assistant Collectors to exercise within their respective jurisdictions the power of Collector under Central Excise rules mentioned in Column 2 of the table subject to the restriction mentioned in Column 4 thereof.

Sl. No.	Central Excise Rule No.	Rank of the Central Excise Officer	Restrictions, if any
1	2	3	4
1.	Rule 173G(1) (Payment of duty by Cheques).	All Officers of and above the rank of Asstt. Collector.	Payment of duty by cheque may be permitted by officers of and above the rank of Asstt. Collector except where the facility granted to the assessee is withdrawn as a result of dishonouring of cheques or where the facility is restored subsequently.

1	2	3	4
2. Rule 9	All officers of and above the rank of Asstt. Collectors	The account current shall be maintained in the name of the Collector.	

NOTES—1. In each case such permission should be granted by Asstt. Collector under intimation to the Collector and Chief Accounts Officer.

2. Collector is the appellate authority to whom the assessee could make a representation against refusal of Asstt. Collector to give permission to pay duty through cheques.
3. Column 4 against Sl. No. 2 in Collector's Notification No. 1/71 dt. 4-6-71 stands modified to the above extent.

[Notifn. No. 2/74/CE—Issued from file C. No. IV/8/1/74 MP. 2]
A. S. I. JAFFAR, Collector.

संयुक्त-मुच्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

बम्बई, 24 अगस्त, 1974

का० आ० 3015—सर्वेश्वी चौक्सी प्रदर्शन, काल्पी मेन्शन, 315 सरदार बी०पी० रोड, बम्बई-4 को सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड एवं सोडियम के डबल साइनाइड भार्दि के आयात के लिए 1250 रुपये (एक हजार बी रुपया सात रुपए मात्र) का एक लाइसेंस संख्या पी ई/0205356 विनांक 10-1-72 स्वीकृत किया गया था।

उन्होंने लाइसेंस की अनुलिपि प्रति (सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति मात्र) के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि वह बम्बई सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत कराने के बाद और उसका बिलकुल उपयोग किए बिना ही खो गया है। अपने दावों के समर्थन में आवेदक ने एक शपथपत्र बांधिल किया है।

मैं संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस संख्या पी ई/0205356, विनांक 10-1-72 खो गया है और निदेश देती हूँ कि आवेदक को लाइसेंस की अनुलिपि प्रति (सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति) जारी की जानी चाहिए।

लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति को रद्द किया गया समझा जाना चाहिए।

[का० स० 1280/22.31.V/578666/AM 72/EL.III से जारी]

कुमारी एस० श्री० मराठे, उप-मुच्य नियंत्रक

कृपा संयुक्त मुच्य नियंत्रक

OFFICE OF THE JT. CHIEF CONTROLLER OF
IMPORTS AND EXPORTS
ORDER

Bombay, the 24th August, 1974

S.O. 3015—M/s. Choksi Brothers, Kanji Mansion, 315 Sardar V. P. Road, Bombay-4 has been granted licence No. PE/0205356 dated 10-1-72 for Rs. 1250 (Rupces One thousand

sand two hundred and fifty only) for import of Sodium Cyanide, Potassium Cyanide and double cyanide of Sodium etc.

They have applied for the duplicate copies of the said licence (Custom Purpose copy only) on the ground that the same have been lost after having been registered with Bombay Custom House and unutilised. In support of their claim, applicant has filed an affidavit.

I am satisfied that the Custom copy of the licence No. PE/0205356 dated 10-1-72 has been lost and direct that the duplicate of the said licence (Custom Purpose copy) should be issued to the applicant firm.

The original Custom purpose copy of the licence should be treated as cancelled.

[Issued from file No. 1280/22. 31. V/578666/
AM. 72/EL. III]

KUM. S. D. MARATHE, Dy. Chief Controller
for Jt. Chief Controller

मुच्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई विल्ली, 3 ब्रह्मदूर्बर, 1974

का० आ० 3016—सर्वेश्वी इंडियन आयात कारपोरेशन लि०, नई विल्ली को 40,00,000 रुपये के लिए एक आयात लाइसेंस संख्या : जी/टी/2391598, विनांक 30-6-72 प्रदान किया गया था। उन्होंने आयात लाइसेंस (सीमा शुल्क निकासी प्रति) की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि विषयाधीन आयात लाइसेंस उनसे खो गया है।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी, महाराष्ट्र राज्य, बम्बई के सामने विधिवत शपथ लेकर एक शपथ पत्र बांधिल किया है। तबनुसार, मैं संतुष्ट हूँ कि मूल लाइसेंस खो गया है। इसलिए यथा मंशोधित आयात नियंत्रण आदेश, 1955, विनांक 7-12-1955 की धारा 9 (सीसी) धारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हुए तर्वशी इंडियन आयात कारपोरेशन लि०, नई विल्ली को जारी किए गए मूल आयात लाइसेंस संख्या : जी० टी० 2391598, विनांक 30-6-72 को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

3. उक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[मंध्या एस पी सी एस०/20/माई श्री सी/74-75]

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF
IMPORTS & EXPORTS

ORDER

New Delhi, the 3rd October, 1974

S.O. 3016—M/s. Indian Oil Corporation Ltd., New Delhi were granted import licence No. G/T/2391598 dated 30-6-1972 for Rs. 40,00,000. They have applied for the issue of duplicate import licence (Custom Copy) on the ground that import licence in question has been lost by them.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit duly sworn in before Notary Maharashtra State, Bombay. I am accordingly satisfied that the original licence has

been lost. Therefore, in exercise of the power conferred under sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Orders, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original licence No G/T/2391598 dated 30-6-1972 issued to M/s Indian Oil Corporation Ltd, New Delhi is hereby cancelled

3 A duplicate copy of said licence is being issued separately

[No SPCL/20/IOC/74 75]

प्रादेश

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 1974

का० आ० 3017 —मर्वेशी इडियन आयल कारपोरेशन लि० नई दिल्ली को 25,57,950/-रुपये मूल्य के लिए एक आयात लाइसेंस सज्या जी/टी/2500335/विनाक 11-5-73 प्रदान किया गया था। उन्होंने आयात लाइसेंस (सीमा शुल्क निकासी प्रति) की अनुलिपि जारी करते हैं लिए आधार पर आवेदन किया है कि विषयाधीन आयात लाइसेंस उनसे खो गया है।

2 इस तर्के के समर्थन में आवेदक ने नोटरी महाराष्ट्र गवर्नर्स के सामने विभिन्न शपथ लेकर एक शपथपत्र बांधिल किया है। तदनुमार में संसुष्ट है कि मूल लाइसेंस खो गया है। इसलिए यथासंशोधित आयात नियमण आवेदा 1955 विनाक 7-12-1955 की उप-धारा 9 (सीसी) द्वारा प्रदत्त प्रधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वेषी इडियन आयल कारपोरेशन लि० अम्बर्ह को जारी किए गए उक्त आयात लाइसेंस सज्या जी/टी/2500335 विनाक 11-5-73 को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

3 उक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[मज्दा आईप्रोसी/1/73-74/आरएम-सैल/स्प० सेल]

एस० के० उस्मानी, उप-मुख्य नियनक।

ORDER

New Delhi, the 5th October, 1974

S.O. 3017. -M/s Indian Oil Corporation Ltd, New Delhi were granted import licence No G/T/2500335 dated 11-5-73 for Rs. 25,57,950. They have applied for the issue of duplicate import licence (Custom Copy) on the ground that the import licence in question has been lost by them

2 In support of this contention the applicant has filed an affidavit duly sworn in before Notary Maharashtra State, Bombay. I am accordingly satisfied that the original licence has been lost. Therefore, in exercise of the power conferred under sub-clause 9(cc) of the Import Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said original licence No G/T/2500335 dated 11-5-73 issued to M/s Indian Oil Corporation Ltd, Bombay is hereby cancelled.

3 A duplicate copy of the said licence is being issued separately

[No IOC/1/73-74/RM-Cell/Sp Cell]

S K USMANI, Dy Chief Controller

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

गुरुपत्र

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1974

का० आ० 3018.—विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना स० 8-34/68 सर्वे० 2, दिनांक 4 सितम्बर, 1974 (14-9-1974 को एस० आ० स० 2362 के रूप में प्रकाशित) में नियम एस० आ० 317-ए एच-3 के उपनियम (1) के अधीन "टाइप V" के नीचे दिए गए "टाइप IV" शब्द के स्थान पर "टाइप VI" पढ़ा जाए।

[का० स० 8-34/68 सर्वे०-2]

टी० एस० विष्वनाथन, अवर सचिव

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th October, 1974

S.O. 3018.—In the Department of Science and Technology Notification No 8 34/68-Sur 2, dated the 4th September, 1974 (Published as S O No 2362 on 14-9-1974) the word "Type IV" appearing below "Type V" under Sub-rule (1) of Rule S R 317-AH-3 shall be substituted to read as "Type VI".

[F No 8-34/68-Sur 2]

T L VISWANATHAN, Under Secy

उद्योग एवं वागरिक आपूर्ति मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

प्रादेश

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1974

का० आ० 3019.—उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) को धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं विकास परिषद् (कार्यविधिक) नियम, 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पक्षे हुए देन्द्रीय सरकार एवं विधायिका श्री एस० एम० चक्रवर्ती, निवेशक (वस्त्र), भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली को 19-4-1976 तक के लिए वस्त्र मर्मानों के निर्माण अथवा उत्पादनरत अनुसूचित उद्योगों के लिए भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के आदेश का० आ० 1134 विनाक 20-4-74 द्वारा स्थापित वस्त्र मर्मान उद्योग की विकास परिषद का सदस्य नामित करती है और निवेश देती है कि उक्त आदेश में निम्ननिष्ठित जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

29 श्री एस० एम० चक्रवर्ती, निवेशक (वस्त्र), भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110001।

[स० 2-2/71-एम० (1)]

एस० कल्नन, अवर मंत्री

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Department of Heavy Industry)

New Delhi, the 26th October, 1974

ORDER

S.O. 3019.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with Rules 2, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules 1952, the Central Government hereby nominates till 19-4-1976, Shri S. M. Chakraborty, Director (Textile) Indian Standards Institute, New Delhi to be a member of the Development Council for Textile Machinery Industry established by the order of the Government

of India in the Ministry of Heavy Industry S.O. 1134 dated 20-4-74 for the scheduled industries engaged in the manufacture or production of Textile Machinery and directs that the following addition shall be made in the said order, namely—

29 Shri S. M. Chakraborty,

Director (Textiles)

Indian Standards Institute.

Manak Bhavan,

9, Bahadur Shah Zafar Marg,

New Delhi 110001

[No 2-2/71-HM(I)]

S KANNAN, Under Secy

शोधोगिक विभास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भंगालय

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर 1974

का० क्रा० 3020—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा प्रतिसूचित किया जाता है कि गोद लगे कागज के टेप की प्रति इकाई मूहर लगाने की फीस नीचे प्रनुसूची में दी गई घोरा के अनुसार निर्धारित की गई है। यह फीस 1 अगस्त, 1973 से लाग हो जाएगी।

ग्रन्ति

क्रम सं०	उत्पाद / उत्पाद की श्रेणी	सम्बद्ध भारतीय मानक की पद्धतिया और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मूहर लगाने की फीस
1	गोद लगे कागज के टेप	IS 4185--1967 गोद लगे कागज के टेप की 20 रोल की एक गांठ विशिष्ट	20 रोल की एक गांठ	35 पैसे

[स० सी०एम०डी० / 13 10]

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, SCIENCE AND TECHNOLOGY
(Indian Standards Institution)

New Delhi, the 29th October, 1974

S O 3020—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the marking fee per unit for gummed paper tapes, details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been determined and the fee shall come into force with effect from 1 August, 1973.

THE SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking fee per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gummed paper tapes	IS. 4185-1967 Specification for gummed paper tapes	One bale of 20 rolls	35 Paise

[No CMD/13 . 10]

का० क्रा० 3021.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा प्रतिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संक्षया सी०एम० / एल-1616, 1617 और 2089 जिसके घोरा नीचे दिए गए हैं, फैक्ट्री के बलों का उत्पादन बद कर देने के कारण 1 जुलाई 1974 से रद्द कर दिए गए हैं।

ग्रन्ति

क्रम संख्या	लाइसेंस संक्षया और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सी०एम०/एल-1616 11 जनवरी, 1968	मसरै ब्रजवारी इमुलेटेक केबल कम्पनी, 4/19, भूतेश्वर रोड, मथुरा (उ०प्र०)	रद्द रोधित केबल-मार्की 'सुपर ब्रजवासी'	(1) IS 434(भाग 1)-1964 रबड रोधित केबलों की विशिष्टि भाग 1 तांबे के चालकों वाले (पुरानीकृति) (2) IS 434(भाग 2)-1964 रबड रोधित केबलों की विशिष्टि भाग 2 एल्यूमिनियम चालकों वाले (पुनरीकृति)

[स० सी०एम०डी०/55 1616 (इटी)]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. सी०एम०/एल०-1617 11 जनवरी, 1968	मेसर्स ब्रजबासी इंसुलेटेड केबल कम्पनी, पी० बी० सी० रोधित केबल- 4/19, भूतेश्वर रोड, मथुरा (उ०प्र०)	मार्का : 'सुपर ब्रजबासी'	(1) IS 691 (भाग 1) — 1964 पी०बी०सी० रोधित केबलों की विशिष्ट (1100 वो० तक कार्यकारी बोल्टता के लिए) : भाग 1 तांबे के चालकों वाले (पुनरीक्षित) (2) IS:694 (भाग 2) — 1964 पी०बी०सी० रोधित केबलों की विशिष्ट (1100 वो० तक कार्यकारी बोल्टता के लिए) : भाग 2 एल्यूमिनियम चालकों वाले (पुनरीक्षित)	
3. सी०एम० / एल-2089 30-9-1969	"	ताप नम्बर रोधित कहुसह केबल-मार्का : 'सुपर ब्रजबासी'	(1) IS:3035 (भाग 2) — 1965 तापनम्बर रोधित कहुसह केबलों की विशिष्ट भाग 1 पी०बी०सी० रोधित और पी०बी०सी० बोल वाले; (2) IS:3035 (भाग 2) — 1965 ताप नम्बर रोधित कहुसह केबलों की विशिष्ट भाग 2 पोलीइथाइलीन रोधित टेप वाले अथवा रहित, ब्लेड और सहमिलित- (3) IS:3035 (भाग 3) — 1967 तापनम्बर रोधित कहुसह केबलों की विशिष्ट भाग 3 पोलीइथाइलीन रोधित और पोलीइथा- इलीन खोलवाले-	

[सी०एम०जी० / 55:1616 (टी)]

S. O. 3021. — In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licences No. CM/L-1616, 1617 and 2089 particulars of which are given below have been cancelled with effect from 1 July, 1974 as the firm has stopped the production of cables:-

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licences cancelled	Relevant Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. CM/L-1616	11 Jan, 1968	M/s Brijbasi Insulated Cable Company. 4/19 Bhuteshwar Road, MATHURA (U.P.)	Rubber-insulated cables- Brand: SUPER BRI- JBASI	(1) IS:434 (Part I) — 1964 Specification for rubber insulated cables Part I with copper conductors (Revised) (2) IS: 434 (Pt. II) — 1964 Specification for rubber insulated cables Part II with aluminium conductors (Revised)
2. CM/L-1617	11 Jan., 1968	-do-	PVC insulated cables Brand- SUPER-BRI- JBASI	(1) IS:694 (Part I—1964) Specification for PVC insulated cables (for voltages up to 1100 volts) Part I with copper conductors (Revised) (2) IS: 694 (Part II—1964) Specification for PVC insulated cables (for voltages up to 1100 volts (Part II with aluminium conductors (Revised)
3.CM/L-2089	30-9-1969	-do-	Thermoplastic insulated weatherproof cables Brand: 'SUPER-BRIJBASI'	(1) IS:3035 (Part I) - 1965 Specification for thermoplastic insulated weatherproof cables, Part I PVC insulated and PVC sheathed (2) IS: 3035 (Part II) — 1965 Specification for thermoplastic insulated weatherproof cables, Part II polythylene insulated, taped or untaped, braided and compounded (3) IS: 3035 (Part III) — 1967 Specification for thermoplastic insulated weather-proof cables Part III polyethylene insulated and polyethylene sheathed

[No. CMD/55—1616 (ET)]

क्रांतिकार 3022. समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी०ए०म० एल० 3617 जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, फैक्ट्री के श्रमिक लगांड़ों के कारण बंद हो जाने पर 1 दिसम्बर, 1973 से रद्द कर दिया गया है:

प्रान्तिकी

क्रम संख्या लाइसेंस संख्या और तिथि लाइसेंस धारी का नाम और पता

रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया तत्संबंधी भारतीय मानक

सी०ए०म०/एल० 3617 30-11-73

मैसर्सैं लायड बिट्यूमेन प्राइवेट्स० प्रा० लि० जलसह कार्यों के लिए बिट्यूमेन (प्लास्टिक) आई एस: 1580-1969
1, तारतला रोड, कलकत्ता-53 इनका मार्क-प्लास्टोलायड
कार्यालय : 4ए, रोड स्ट्रीट कलकत्ता-16 में है।

[मं० (सी०ए०डी०) 55:3617]

ए० कै० गुप्ता, उप महानिदेशक

New Delhi, the 29 October, 1974

S.O. 3022. In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-3617 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1 Dec. 1973 on account of/due to Closure of the factory due to labour trouble.

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Governed by the Licensee Cancelled	Relevant Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	CM/L-3617 30-11-73	M/s Lloyd Bitumen Products Pvt. Ltd., 1, Taratala Road, Calcutta-53 having their office at 4-A, Royd Street, Calcutta-16.	Bitumen (Plastic) for Water-proofing Purposes Brand 'PLASTOLOID'	IS : 1580-1969

[No. CMD/55 : 3617]

A.K. Gupta Deputy Director general

नई दिल्ली, रिनाक 1 दिसम्बर, 1974

क्रांतिकार 3023. -- समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 3 के उपविनियम (4) के अधीन प्राप्त अधिकारियों के अनुसार कुछ भारतीय मानकों के उपबंधों में जिनके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, मानक चिन्ह के उपयोग में गति जाने के उद्देश्य से परीकारात्मक रूप में संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के द्वारा भारतीय मानकों के अनुरूप बने माल की किस्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये संशोधन तुरन्त ही लागू हो जाएंगे ;

प्रान्तिकी

क्रम संख्या	भारतीय मानक की संबंधी और गोर्बक जिसने उपबंधों में संशोधन किए गए हैं	भारतीय मानकों के उपबंधों में किए गए संशोधनों का विवरण	(1)	(2)	(3)
1. आई एस: 1812-1973 लकड़ी पेंच बनाने के लिए मुद्रु इस्पात इस विशिष्ट में सिलिया तथा पिंड शामिल कर लेने की व्यवस्था की गई है। तार (पहला पुनरीक्षण)					
2. आई एस: 2255-1969 मणीनी पेंच बनाने के लिए मुद्रु इस्पात के तार (सिरे बनाने की शीत विधि द्वारा) (पहला पुनरीक्षण)		तारेव			
3. आई एस: 2589-1964 गडी बाली कमानियों के लिए सफ्ट लिंच इस्पात के तार		तारेव			
4. आई एस: 2879-1967 मेटल ग्राहक बैलिंग स्लेक्स्ट्रोड कोर के तार के लिए मुद्रु इस्पात (पहला पुनरीक्षण)		तारेव			
5. आई एस: 3195-1965 शंखावत तथा कुण्डलीवार कमानियों के लिए इस्पात (रेल के लिंबों के लिए)		तारेव			

1	2	3
6. आई० एस० 3431-1965 स्वचल गाड़ियों में निलम्बन के लिए संखात तथा कुण्डलीशार और परतदार कमानियों के बनाने के लिए इसात		इस विशिष्ट में सिलिंया तथा पिण्ड शामिल कर लेने की व्यवस्था की है।
7. आई० एस० 3885 (भाग 1)-1966 परतदार कमानियां बनाने के लिए इसात (रेल के छिप्पों के लिए) भाग 1-चपटे सेक्षण		"
8. आई० एस० 3885 (भाग 2)-1969 परतदार कमानियां बनाने के लिए इसात (रेल छिप्पों के लिए) भाग-2 फॉक (रिब) और खांच सेक्षण		"
9. आई० एस० 4072-1967 स्प्रिंग वाशरों के लिए इसात		"

[स० सी० एम० फी०/13:4]
एस० के० सेन, महानिवेशक

New Delhi, 1 November, 1974

S.O. 3023.--In exercise of the powers conferred on me under sub-regulation (4) of regulation 3 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, modifications to the provisions of various Indian standards, details of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have tentatively been made with a view to expediting the use of the Standard Mark, without anyway affecting the quality of goods covered by the relevant standard. These modifications shall come into force with immediate effect :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of Indian Standard Specification, the provision of which have been modified	Particulars of the modifications made to the Provisions
(1)	(2)	(3)
1.	IS : 1812-1973 Mild steel wire rods for the manufacture of wood screws (first revision).	Provision has been made to include ingots and billets in this specification.
2.	IS : 2255-1969 Mild steel wire rod for the manufacture of machine screws (by cold heading process) (first revision).	Do.
3.	IS : 2589-1964 Hard-drawn steel wire for upholstery springs	Do.
4.	IS : 2879-1967 Mild steel for metal arc welding electrode core wire (first revision).	Do.
5.	IS : 3195-1965 Steel for the manufacture of volute and helical spring (for railway rolling stock).	Do.
6.	IS : 3431-1965 Steel for the manufacture of volute, helical and laminated springs for automotive suspension.	Do.
7.	IS : 3885 (Part I)-1966 Steel for the manufacture of laminated springs (railway rolling stock) Part I-Flat Sections.	Do.
8.	IS : 3885 (Part II)-1969 Steel for the manufacture of laminated springs (railway rolling stock) Part II-Rib and groove sections.	Do.
9.	IS : 4072-1967 Steel for spring washers	Do.

[No. CMD/13 : 4]
S. K. SEN, Director General.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1974

का० आ० 3024.--यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया राज्य पन्थ से उत्तर प्रदेश में मधुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय नेत निगम लि० द्वारा बिल्ड जानी चाहिए।

ग्राह यतः ऐसी साइरों को विभाने के प्रयोजन के लिए एतत्पुरावद्ध मनुसूची में विभिन्न भूमि में उपयोग का अधिकार प्राप्ति करना आवश्यक है :

अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का प्राप्ति) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की घारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोजन करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार प्राप्ति करने का प्रपत्ता आशय एतद्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समाम प्राधिकारी भारतीय तेल निगम लिंग सलाया-कोयाली/मधुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट "डोली"-33-बी, हरिहर सोसाइटी, राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हुआ व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथम करेगा कि क्या वह यह जाह्नवा है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

ममुसूची

तालुका : ओटीला जिला : सुरेन्द्रनगर गुजरात : राज्य

ग्राम	सर्वेक्षण सं०	एवं			वर्ग मीटर
		३	४	५	
१	२				
जानीवाला	60	0	06	07	
	61	0	27	32	
	62	0	14	16	
	71	0	03	04	
	70	0	15	18	
	69	0	16	19	
	67	0	18	21	
	182	0	24	28	
	181	0	24	05	
	184	0	06	07	
	185	0	08	09	
	186	0	15	18	
	194	0	09	12	
	193	0	20	23	
	187	0	06	07	
	215	0	38	45	
	232	0	22	26	
	231	0	20	23	
	229	0	31	36	
	258	0	23	27	
	259	0	02	02	
	256	0	19	22	
	255	0	04	05	
	260	0	01	01	
	261	0	17	20	
	263	0	07	08	
	264	0	08	09	
	265	0	20	23	
चन्पा	17	0	41	48	
	18	0	11	13	
	15	0	11	13	
ओटीला	196	0	42	49	
	198	0	03	04	
	199	0	31	36	

	1	2	3	4	5
ओटीला					
	171	0	25	29	
	173	0	18	19	
	179	0	01	01	
	174	0	42	49	
	175 पी/1	0	06	07	
	175 पी/2	0	06	07	
तबायी (चो०)					
	65 पी	0	55	64	
	66 पी	0	43	50	
	67 पी	0	04	05	
पोत्तवाली					
	97	0	12	14	
	98	0	30	35	
	1	0	03	04	
	105	0	14	16	
	106/1	0	10	12	
	107	0	07	08	
	108	0	06	07	
	110	0	18	21	
	101 पी/1	0	02	02	
	101 पी/2	0	08	09	
	101 पी/4	0	04	05	
	101 पी/4	0	21	25	
	101 पी/5	0	25	29	
षष्ठीती (चो०)					
	47	0	04	05	
	54	0	28	33	
	57	0	32	57	
	68	0	07	08	
	87	0	87	01	
	94 पी/1	0	41	48	
	94 पी/2	0	21	25	
	95 पी	0	01	01	
	3	0	02	02	
नामा					
	10	0	30	35	
	11	0	01	01	
	137 पी/1	0	12	14	
	137 पी/2	0	39	46	
	135	0	24	28	
	134	0	22	26	
	137 पी/3	0	18	28	
	137 पी/4	0	31	36	
	137 पी/5	0	14	16	
	127	0	14	16	
	137 पी/6	0	13	15	
	128	0	13	15	
	130	0	43	50	
	137 पी/7	0	01	02	
	137 पी/8	0	28	33	
	137 पी/9	0	26	30	

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
દેવસર	83 પી/1	0	17	20		184	0	06	07
	66/1	0	17	20		185	0	08	09
	66/2	0	21	25		186	0	15	18
	83 પી/2	0	18	22		194	0	09	10
	70	0	19	22		193	0	20	23
	83 પી/3	0	10	12		187	0	06	07
	71	0	49	57		215	0	38	45
	75	0	45	53		232	0	22	26
	76	0	22	26		231	0	20	23
	77 પી/1	0	37	43		229	0	31	36
	83 પી/4	0	02	02		258	0	23	27
	77 પી/2	2	27	64		259	0	02	02
	77 પી/3	0	49	57		256	0	19	22
	78	0	58	68		255	0	04	05

(संख्या 12017/3/74-एल० तथा ए.ल०/IV]

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, 31st October, 1974

S. O. 3024.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B. Hatihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka :—Chotila. District :—Surendranagar, Gujarat State

Village	Survey No.	Extent		
		H	A.	Sq. M.
Janivadla	60	0	06	07
	61	0	27	32
	62	0	14	16
	71	0	03	04
	70	0	15	18
	69	0	16	19
	67	0	18	21
	182	0	24	28
	181	0	04	05

Chanpa	.	.	17	0	41	48
			16	0	11	13
			15	0	11	13
Chotila	.	.	196	0	42	49
			198	0	03	04
			199	0	31	36
			171	0	25	29
			173	0	16	19
			179	0	01	01
			174	0	42	49
			175 P/1	0	06	07
			175 P/2	0	06	07
Navagam (Cho.)	.	.	65 P.	0	55	64
			66 P.	0	43	50
			67 P.	0	04	05
Pojvali	.	.	97	0	12	14
			98	0	30	35
			1	0	03	04
			105	0	14	16
			106/1	0	10	12
			107	0	07	08
			108	0	06	07
			110	0	18	21
			101 P/1	0	02	02
			101 P/2	0	08	09
			101 P/3	0	04	05
			101 P/4	0	21	25
			101 P/5	0	25	29
Rupavati (Cho.)	.	.	47	0	04	05
			54	0	28	33
			57	0	32	57
			68	0	07	08
			87	0	87	01
			94 P/1	0	41	48
			94 P/2	0	21	25
			95 P.	0	01	01
			3	0	02	02

1	2	3	4	5	मनसूची		
					नामका वधाना	ज़िला: मुरोनगर	गुजरात: राज्य
Nava	10	0	30	35	प्राप्त	सर्वेभान सं०	क्षेत्र
	11	0	01	01			
	137 P/1	0	12	14	चमारगंज	167	0 28 23
	137 P/2	0	39	46		165	0 42 49
	135	0	24	28		164	0 30 35
	134	0	22	26		163	0 16 19
	137 P/3	0	16	28		162	0 15 18
	137 P/4	0	31	36		160	0 29 34
	137 P/5	0	14	16		161	0 04 05
	127	0	14	16		153/1	0 03 04
	137 P/6	0	13	15		152	0 31 36
	128	0	13	15		150/2	0 15 18
	130	0	43	50		150/3	0 05 06
	137 P/7	0	01	02		89/2	0 15 18
	137 P/8	0	28	33		89/1	0 09 11
	137 P/9	0	26	30		37/2	0 06 07
	83 P/1	0	17	20		39/1	0 21 25
	66/1	0	17	20		35/2	0 02 02
	66/2	0	21	25		35/1	0 14 17
	83 P/2	0	18	22		39/4	0 03 04
	70	0	19	22		33	0 29 34
	83 P/3	0	10	12		6/1	0 20 23
	71	0	49	57		357	0 18 21
	75	0	45	53		356	0 21 25
	76	0	22	26		355	0 00 10
	77 P/1	0	37	43		354	0 26 30
	83 P/4	0	02	02		353	0 13 15
	77 P/2	2	27	64		352	0 11 13
	77 P/3	0	49	57		351	0 10 12
	78	0	58	68		343	0 02 02

[No. 12017/3/74-L & L/IV

का ०३०३०२५.—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में मलाया पलन से उत्तर प्रदेश में मधुरा तथा पेंटोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय तेल नियम लिंग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एनडुपाबड़ अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है:

अतः, अब, पेंटोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त सक्षियों का प्रयोग न करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एनडुपाबड़ छोड़ा किया है।

उक्त भूमि में हिनबड़ कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आधेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल नियम लिंग, मलाया-कोयानी/मधुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "शोली"-33-बी, हरिहर सीमाइटी, गजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आधेप करने वाला हर व्यक्ति विनियिष्ट यह भी करन करेगा कि क्या वह यह जाहिता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

द्वारेजे	28	0	49	57
	32	0	00	36
	223	0	04	05
	210	0	00	06
	211	0	45	53
	212	0	35	41
	224	0	36	42

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
						331	0	36	42
	225	0	30	35		329	0	39	46
	226	0	10	12		321	0	40	47
	229/1/पी	0	05	06		243	0	15	18
	272	0	08	09		244	0	04	05
	276 पी	0	02	02		320	0	05	06
	273	0	34	40		319	0	09	11
	270	0	24	28		318	0	12	14
	265	0	22	26		317	0	22	26
	268	0	20	23		252	0	29	34
	269	0	11	13		253/1	0	12	14
	23	0	09	11		254	0	12	14
	972	0	22	25		255	0	26	30
	973	0	11	13		256/1	0	19	22
	885	0	14	16		256/2	0	01	01
	890	0	15	18		257	0	05	06
	889	0	15	18		260	0	00	10
	887	0	42	49		259	0	31	36
	888	0	11	13		258	0	32	37
	892	0	00	10		270	0	18	21
	874	0	18	21					
	875	0	27	32	पाला	262	0	05	06
	876	0	55	64		261	0	35	41
	860/2	0	23	27		260	0	01	01
बकरयाली	266	0	63	64		259	0	31	36
	269	0	04	05		257	0	14	16
	268	0	19	22		258	0	84	98
	267	0	03	04		251	0	33	39
	256	0	25	29		249	0	23	27
	280	0	44	52		248	0	25	29
	279	0	13	15		247	0	09	11
	288	0	32	37		246	0	01	01
	290	0	38	45		245	0	26	30
	291	0	41	48		440	0	06	07
	11	0	31	36		239	0	20	23
	18	0	24	28		215	0	35	41
	17	0	20	23		218	0	14	16
	19	0	29	34		219	0	30	35
	20	0	06	07		220	0	11	13
	23	0	01	01		173	0	59	69
	22	0	32	37		172	0	01	01
	21	0	03	04		169	0	13	15
	32	0	18	21					
	36	0	37	43	प्रतिशत	674	0	27	32
राजपात्र	24	0	05	06		675	0	24	28
	22	0	32	37		680	0	33	39
	395	0	26	30		679	0	21	25
	394	0	16	19		688	0	23	27
	378	0	03	04		687	0	27	32
	379	0	24	28		702	0	39	46
	332	0	25	29		701	0	23	27
						704	0	01	01

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
परिषदा-जारी	703	0	38	45		37/2	0	06	07
	33	0	27	32		39/1	0	21	25
	34	0	09	11		35/2	0	02	02
	50	0	33	39		35/1	0	14	17
	51	0	24	28		39/4	0	03	04
	57	0	22	26		33	0	29	34
	58	0	27	32		6/1	0	20	23
	66	0	01	01		357	0	18	21
	67	0	15	18		356	0	21	25
	68	0	23	27		355	0	00	10

[संख्या 12017/3/74-एस. तथा एस./०५]

S.O. 3025—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its Intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyal/ Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B, Harihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka : Wadhwan District :—Surendranagar Gujarat State

Village	Survey No.	Extent		
		H.	A.	Sq. M.
1	2	3	4	5
Chamaraj	167	0	28	23
	165	0	42	49
	164	0	30	35
	163	0	16	19
	162	0	15	18
	160	0	29	34
	161	0	04	05
	153/1	0	03	04
	152	0	31	36
	150/2	0	15	18
	150/3	0	05	06
	89/2	0	15	18
	89/1	0	09	11

Dudhrej	28	0	49	57
	32	0	00	36
	223	0	04	05
	210	0	00	06
	211	0	45	53
	212	0	35	41
	224	0	36	42
	225	0	30	35
	226	0	10	12
	229/1 P	0	05	06
	272	0	08	09
	276 P.	0	02	02
	273	0	34	40
	270	0	24	28
	265	0	22	36
	268	0	20	23
	269	0	11	13
	23	0	09	11
	972	0	22	25
	973	0	11	13
	885	0	14	16
	890	0	15	18
	889	0	15	18
	887	0	42	49
	888	0	11	13
	892	0	00	10
	874	0	18	21
	875	0	27	32
	876	0	55	64
	860/2	0	23	27
Bakarthali	266	0	63	64
	269	0	04	05
	268	0	19	22
	267	0	03	04
	256	0	25	29
	280	0	44	52
	279	0	13	15
	288	0	32	37
	290	0	38	45
	291	0	41	48
	11	0	31	36
	18	0	24	28
	17	0	20	23
	19	0	29	34
	20	0	06	07
	23	0	01	01
	22	0	32	37
	21	0	03	04
	32	0	18	21
	36	0	37	43
Rajpar	24	0	05	06
	22	0	32	37
	395	0	26	30
	394	0	16	19
	378	0	03	04

1	2	3	4	5
	379	0	24	28
	332	0	25	29
	331	0	36	42
	329	0	39	46
	321	0	40	47
	243	0	15	18
	244	0	04	05
	320	0	05	06
	319	0	09	11
	318	0	12	14
	317	0	22	26
	252	0	29	34
	253/1	0	12	14
	254	0	12	14
	255	0	26	30
	256/1	0	19	22
	256/2	0	01	01
	257	0	05	06
	260	0	00	10
	259	0	31	36
	258	0	32	37
	270	0	18	21
Bala	262	0	05	06
	261	0	35	41
	260	0	01	01
	259	0	31	36
	257	0	14	16
	258	0	84	98
	251	0	33	39
	249	0	23	27
	248	0	25	29
	247	0	09	11
	246	0	01	01
	245	0	26	30
	440	0	06	07
	239	0	20	23
	215	0	35	41
	218	0	14	16
	219	0	30	35
	220	0	11	13
	173	0	59	69
	172	0	01	01
	169	0	13	15
Anindra	674	0	27	32
	675	0	24	28
	680	0	33	39
	679	0	21	25
	688	0	23	27
	687	0	27	32
	702	0	39	46
	701	0	23	27
	704	0	01	01
	703	0	38	45
	33	0	27	32
	34	0	09	11
	50	0	33	39
	51	0	24	28
	57	0	22	26
	56	0	27	32
	66	0	01	01
	67	0	15	18
	68	0	23	27

प्रीर यतः ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपादाद्र
अनुसूची में बनित भूमि में उपयोग का अधिकार प्रदित करना आवश्यक
है:

अतः अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का
प्रज्ञन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा
(1) द्वारा प्रवल शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उप-
योग का अधिकार प्रदित करने का अपना आशय एतदुपादान प्रयित किया
है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कर्ता अक्षित उस भूमि के नीचे पाइपलाइन
बिछाने के लिए आवेदन मध्यम प्राधिकारी भारतीय निगम लि०
मलाया-कोयली/मधुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "डोली"-33-वी, हरिहर
सोसाइटी, राजकोट को इस अधिसूचना की नागरिक में 21 दिनों के भीतर
कर सकेगा।

ऐसा आवेदन करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट, यह भी कथन करेगा
कि क्या यह यह आहता है कि उसकी मुनवाई अविकल्प हो या किसी विधि
अवसायी की माफेन।

भूमूली		सालुका इमादा	जिला-सुरेन्द्रगढ़	गुजरात राज्य
ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	एवं	एवं	बगेर मीटर
हेबनपुर	440	0	12	14
	439	0	11	13
	435	0	01	01
	436	0	36	42
	429	0	12	14
	428	0	01	01
	427/1	0	11	13
	427/2	0	14	16
	427/3	0	01	01
	380	0	03	03
	381	0	50	59
	382	0	11	13
	329	0	32	37
	330	0	18	21
	326	0	37	43
	288	0	11	13
	287	0	15	18
	252	0	48	56
	247/1	0	12	14
	248	0	00	55
	244	0	00	25
	243	0	36	42
	230	0	08	09
	229	0	18	21
	152	0	25	29
	99	0	21	25
	151	0	10	12

[No 12017/3/74-L&L/V]

का० आ० 3026.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि
सोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पत्तम से उत्तर
प्रदेश में मधुरा तथा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय
नेशनल निगम लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	100 फी०	0	14	16		287	0	15	18
	102	0	40	47		252	0	48	56
	103	0.00	00	25		247/1	0	12	14
	81	1	70	98		248	0	00	55
						244	0	00	25
						243	0	36	42
						230	0	08	09
						229	0	18	21
						152	0	25	29
						99	0	21	25
						151	0	10	12
						100P.	0	14	16
						102	0	40	47
						103	00.0	00	25
						81	1	70	98

[संख्या 12017/3/74-एल तथा एल/VI]

[No. 12017/3/74-L&L/VI]

S.O. No. 3026.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And Wherers it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereeto;

Now, Thererfore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its Intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B, Harihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka : Dasada District : Surendranagar Gujarat State.

Village	Survey No.	Extent	q. M.	
1	2	3	4	5
Hebatpur	440	0	12	14
	439	0	11	13
	435	0	01	01
	436	0	36	42
	429	0	12	14
	428	0	01	01
	427/1	0	11	13
	427/2	0	14	16
	427/3	0	01	01
	380	0	03	03
	381	0	50	59
	382	0	11	13
	329	0	32	37
	330	0	18	21
	326	0	37	43
	288	0	11	13

का०ग्रा०सं० 3027—यत. केंद्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया परस्त उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय तेल निगम द्वारा बिलाई जानी आहिए;

प्रोर यत. ऐसी लालो को बिलाने के प्रयोजन के लिए एन्डुप्लाइन अनुसूची में विनियोग की भूमि में उपयोग का अधिकार अंजित करना आवश्यक है: ।

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार आ अंजेन अधिनियम 1962 (9162 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त सविनयों का प्रयोजन करने हुए केंद्रीय मरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अंजित करने का अपना आवश्यक द्वारा घोषित किया है । ।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिलाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकारी भारतीय तेल निगम द्वा० सलाया-कोयाली/मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "डोली"-33-बी, हारहर सोसाइटी राजकोट को इस अधिसूचना की सारीष से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । ।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उमकी मुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

तालुका : मोरदी	जिला : राजकोट	गुजरात राज्य
ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	एक लेख वर्ग
1	2	3 4 5
प्रामर्द्धपार	45	0 28 33
	47	0 46 54
	49	0 20 23
	76	0 24 28

SCHEDULE

75	0	44	52
76	0	01	01
77	0	33	39
81	0	28	33
82	0	24	28
83	0	49	57
93	0	17	20
2 पी/1	0	19	22
2 पी/2	0	11	13
2 पी/3	0	22	24
2 पी/4	0	15	18
2 पी/5	0	20	23
130	0	19	22
131	0	40	47
2 पी/6	0	18	21
2 पी/7	0	18	21
129	0	26	30
2 पी/8	0	18	21
2 पी/9	0	06	07
2 पी/10	0	19	22
161	0	12	14
162	0	08	09
156	0	24	16
158	0	06	08
157	0	15	19
153	0	02	02
152	0	52	61

[मंड्या 12017/3/74-पाल तथा एल/VII]

S.O. 3027.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

All Whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962); the Central Government hereby declare its Intention to acquire the right of user therein;

Provided That any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project, "Doll" 33-B, Harihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

Taluka : Morvi		District : Rajkot		Gujarat State		
Village		Survey No.		H	A.	Sq. M.
Anandpar	.	45		0	28	33
		47		0	46	54
		49		0	20	23
		76		0	24	28
		75		0	44	52
		73		0	01	01
		74		0	33	39
		81		0	28	33
		82		0	24	28
		83		0	49	57
		93		0	17	20
		2 P/1		0	19	22
		2 P/2		0	11	13
		2 P/3		0	22	24
		2 P/4		0	15	18
		2 P/5		0	20	23
		130		0	19	22
		131		0	40	47
		2 P/6		0	18	21
		2 P/7		0	18	21
		129		0	26	30
		2 P/8		0	18	21
		2 P/9		0	06	07
		2 P/10		0	19	22
		161		0	12	14
		162		0	08	09
		156		0	24	16
		158		0	06	08
		157		0	15	18
		153		0	02	02
		152		0	52	61

[No. 12017/3/74-L&L/VII]

S.O. 3028.—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह भावशक है कि गुजरात राज्य में सलामा पत्तन से उत्तर प्रदेश में सधुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाल्पलाइन भारतीय नेल निगम निं. द्वारा बिल्ड जानी चाहिए।

और यह ऐसी वाइनो को बिल्ड के प्रयोजन के लिए पाल्पलाइन अनुमति में विभिन्न भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है:

ग्रन्त, अब, पेट्रोलियम पाल्पलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) प्रधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपषासा (1) द्वारा प्रवल्ल शक्तियों का प्रयोग करने हुए केंद्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार प्राप्ति करने का अपना आशय एन्डव्हारा शोषित किया है।

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के भीचे पाइपलाइन बिल्डर के लिए आक्षेप सम्म प्राधिकारी, मारतीय तेल निगम लिं, मलाया-कोयाली/मधुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "होली"-33-वी, हरिहर सोमाइटी, राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकता ।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह आहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि अवसरायी की माफ़ान ।

अनुसूची

नामका . डरोल	जिला . जामनगर	गुजरात. राज्य		
		मर्वेक्षण सं०	एक	क्षेत्र वर्ग
			ए	मीटर
1	2	3	4	5
जालिया देवानी	109	0	17	00
	108/3	0	16	00
	108/2	0	10	00
	176 पी	0	02	00
	131	0	18	00
	126	0	15	00
	132	0	38	00
	133	0	33	00
	135	0	01	11
	162/1	0	94	14
	162/2	0	07	08
	161/1	0	01	01
	160/3	0	01	01
स्थितिविधा	8	0	66	00
	9	0	47	00
	10	0	35	41
	14	0	00	01
	31/2	0	00	01
	33/1	0	38	49
	32/1	0	38	45
	32/2	0	38	45
	35/1	0	57	67
	35/2	0	42	49
	36	0	60	70
	38	0	01	01
	40	0	24	28
	43	0	23	27
	37	0	39	46
	91/1	0	11	00
	91/2	0	09	11
	91/3	0	17	20
पीपारलोड	11	0	39	49
	14	0	36	43
	15	0	37	43
	18	0	56	66

1	2	3	4	5
जेनगरका	148	0	20	25
	149	0	15	18
	150	0	15	18
	151	0	21	25
	152	0	23	27
	170/1	0	22	26
	171	0	39	46
	175	0	03	04
	169	0	17	22
कटाका	2	0	17	20
	3	0	10	08
	4	0	41	48
	5	0	00	08
	6	0	23	27
	7	0	26	30
	35	0	23	27
	65	0	21	25
	67	0	07	08
	69	0	07	08
	70	0	03	04
	71	0	10	00
	72	0	06	07
	74	0	28	33
	75	0	23	27
	111	0	37	43
	120	0	04	05
	122	0	11	13
	123	0	11	13
	126	0	23	27
	127	0	38	45
	128	0	19	22
	14	0	09	11
	121	0	13	00

[संख्या 12017/3/74-एल तथा एल/VIII]

S.O. 3028.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its Intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyal/Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B, Harihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka : Dhrol	District : Jamnagar	Gujarat State		
Village	Survey No.	Extent		
		H.	A.	Sq. M.
1	2	3	4	5
Jalia Devani	109	0	17	00
	108/1	0	16	00
	108/2	0	10	00
	176 P	0	02	00
	131	0	18	00
	126	0	15	00
	132	0	38	00
	133	0	33	00
	135	0	01	11
	162/1	0	94	14
	162/2	0	07	08
	161/1	0	01	01
	160/3	0	01	01
Khijadia	8	0	66	00
	9	0	47	00
	10	0	35	41
	14	0	00	01
	31/2	0	00	01
	33/1	0	36	49
	32/1	0	38	45
	32/2	0	36	45
	35/1	0	57	67
	35/2	0	42	49
	36	0	60	70
	38	0	01	01
	40	0	24	28
	43	0	23	27
	37	0	39	46
	91/1	0	11	00
	91/2	0	09	11
	91/3	0	17	20
Pipartodu	11	0	39	49
	14	0	36	43
	15	0	37	43
	18	0	56	66
	19	0	20	23
	21	0	21	25
	26	0	26	30
	39	0	03	04

1	2	3	4	5
Khengarka	148	0	20	25
	149	0	15	18
	150	0	15	18
	151	0	21	25
	152	0	23	27
	170/1	0	22	26
	171	0	39	46
	175	0	03	04
	169	0	17	22
Katada	2	0	17	20
	3	0	10	08
	4	0	41	48
	5	0	00	08
	6	0	23	27
	7	0	26	30
	35	0	23	27
	65	0	21	25
	67	0	07	08
	69	0	07	08
	70	0	03	04
	71	0	10	00
	72	0	06	07
	74	0	28	33
	75	0	23	27
	111	0	37	43
	120	0	04	05
	122	0	11	13
	123	0	11	13
	126	0	23	27
	127	0	38	45
	128	0	19	22
	14	0	09	11
	121	0	13	00

[No. 12017/3/74-L&L/VIII]

का० आ० 3029.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पत्तन से उत्तर प्रदेश में मधुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय नेल निगम लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

मौर यतः ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

यतः भव पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिलियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितबढ़ कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाहपलाइन डिलाने के लिए आक्षेप मकाम प्राप्तिकारी, भारतीय तेल निगम लि० सलाया-कोयाली/ मधुग पाहपलाइन प्रोजेक्ट "डीली"- 33-वी हरिहर सोसाइटी राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्ट यह भी कथन करेगा कि व्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो गा किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

सालुका : सालपुर		जिला :—जामनगर		गुजरात राज्य
प्राम	मर्बेश्वर संख्या	क्षेत्र	वर्ग	जोगवद
1	2	3	4	5
सिंगाच	313	0	14 00	82
	316	0	42 00	81
	318	0	47 00	80
	320/3	0	13 00	76
	320/2	0	18 00	75
	320/1	0	00 02	211
	282	0	01 50	194
	283	0	32 00	212
	259	0	11 00	213
	258	0	08 00	215
	257	0	14 00	168
	256	0	19 00	167
	263	0	09 00	166
	236	0	33 00	147
	233	0	00 25	145
	147	0	25 00	144
	143	0	19 00	148
	137/ी	0	40 41	143
	139/ी	0	46 00	152
	133	0	23 00	141
	138/2	0	27 00	139
	138/3	0	02 00	138
कंकार	490	0	18 00	136
	489	0	21 00	135
	488	0	23 00	133
	81	0	22 00	132
	494	0	16 00	
	65	0	06 00	
	487	0	33 00	
	486	0	18 00	
	502	0	08 00	
	503	0	01 00	
	504	1	09 00	
	519	0	08 00	
	520	0	25 00	

[संख्या 12017/3/74—एल० तथा एल०/IX]

New Delhi, the 31st October 1974

S.O. No. 3029.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

AND WHEREAS it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyalji/Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B, Harihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka: Lalpur District: Jamnagar Gujarat State

Village	Survey No.	Extent		
		H.	A.	Sq. M.
1	2	5		
SINGACH	313	0	14	00
	316	0	42	00
	318	0	47	00
	320/3	0	13	00
	329/2	0	18	00
	320/1	0	00	02
	282	0	01	50
	283	0	32	00
	259	0	11	00
	258	0	08	00
	257	0	14	00
	256	0	19	00
	263	0	09	00
	236	0	33	00
	233	0	00	25
	147	0	25	00
	143	0	19	00
	137 P	0	40	41
	139 P	0	46	00
	135	0	23	00
	138/2	0	27	00
	138/3	0	02	00
ZANKHAR	490	0	18	00
	489	0	21	00
	488	0	23	00
	81	0	22	00
	494	0	16	00
	65	0	06	00
	487	0	33	00
	486	0	18	00
	502	0	08	00
	503	0	01	00
	504	1	09	00
	519	0	08	00
	520	0	25	00
	528	0	24	00
	526	0	01	00
	525	0	08	00
	176	0	09	00
	177	0	18	00
	179	0	02	00
	180	0	09	00
	158	1	00	00
	155	0	26	00
	156	0	37	00
	138	1	02	00

1	2	3
JOGVAD	82	0 28 00
	81	0 32 00
	80	0 27 00
	76	0 22 00
	75	0 14 00
	211	0 01 00
	194	0 07 00
	212	0 25 00
	213	0 14 00
	215	0 14 00
	168	0 58 62
	167	0 04 00
	166	0 31 00
	147	0 32 00
	145	0 22 00
	144	0 04 00
	148	0 22 00
	143	0 63 00
	152	0 13 00
	141	0 33 00
	139	0 18 00
	138	0 17 00
	136	0 33 00
	135	0 42 00
	133	0 28 00
	132	0 01 00

[No. 12017/3/74 L&L/IX]

का० घा० 3030.— यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पत्तन से उत्तर प्रदेश में मधुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय तेल निगम द्वा० द्वारा बिलाई जानी चाहिए।

और यतः ऐसी लाइनों को बिलाने के प्रयोजन के लिए एतत्पुरावर्त्त भ्रिसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना प्रावश्यक है:

यतः, भ्रव, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का प्राप्ति) प्रधिनियम, 1962 (1962 का 50 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एनव्हारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितदृढ़ कोई व्यक्ति, उस भूमि के भीत्रे पाइपलाइन बिलाने के लिए आक्षेप मध्यम व्याधिकारी, भारतीय तेल निगम द्वा०, सलाया-कोयाली/मधुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "डॉली" 33 बी, हरिहर सोसाइटी, राजकोट को इस भ्रिसूची की भारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विद्धः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी मार्फत।

प्रत्यक्षवी				(1)	(2)	(3)
तालुकः जामनगर	जिला : जामनगर	गुजरात : राज्य				
पास	सर्वेक्षण सं०	एक	क्षेत्र ए. बर्ग मीटर			
(1)	(2)	(3)				
मोरकोडा	231	0	15 00		275	0 28 00
	216	0	16 00		267	0 06 00
	213	0	35 00		208	0 27 00
	212	0	05 00		206	0 14 00
	142	0	26 00		164/1	0 23 00
	143/2	0	07 00		164/2	0 13 00
	144	0	09 00		164/3	0 15 00
	145/1	0	22 00		165/1	0 28 00
	145/2	0	18 00		165/2	0 22 00
	156	0	55 00		160	0 19 00
	157	0	00 08		159	0 34 00
	192	0	37 00		157	0 11 00
	193	0	14 00		156	0 09 00
	194	0	00 06		95	0 13 00
	191/1	0	30 00		103	0 16 00
	191/2	0	19 00		104	0 09 00
	185	0	72 00		105	0 28 00
	174/1	0	31 00		106	0 35 00
	179	0	27 00		132	0 33 00
	180	0	36 00		131	0 30 00
थेवा	181पी/1	0	31 36		130	0 29 00
	181पी/2	0	27 32		129	0 27 00
	180	0	44 52		126	0 18 00
	179	0	34 36			
	178	0	27 32	आलय	138	0 08 00
	108	0	21 25		138/1	0 17 00
	106	0	14 16		138/2	0 08 00
	94	0	59 69		171	0 26 00
	83	0	12 14		170	0 20 00
मोटा थारिया	335	0	14 00		169	0 39 00
	336	0	35 00		168	0 17 00
	342	0	23 00		187	0 21 00
	324	0	40 00		165	0 34 00
	323	0	32 00		188	0 34 00
मोटा थारिया	319	0	47 00		193	0 11 00
	312	0	01 00		191	0 47 55
	316	0	33 00		206	0 08 00
	315	0	61 00		258	0 01 00
	400पी	0	15 00		259	0 55 00
	305	0	39 00		284	0 59 64
	290	0	03 00		290	0 34 00
	291	0	31 00		291	0 27 33
	292	0	03 00		292	0 46 34

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
गंगाज ला	80	0 13 49		37 पी/1	0 29 90
मोडा	452	0 87 00		37 पी/2	0 30 54
	459	0 53 62		39/1	0 17 93
	465	0 03 36		39/2	0 30 00
	462	0 49 57	जामबनाथसी	75	0 16 00
	381/1	0 25 29		74 पी/1	0 03 00
	380	0 13 25		76	0 06 00
	379	0 20 00		77	0 18 00
	331/1	0 15 18		74 पी/2	0 15 00
	330	0 13 15	जामबनाथसी	81	0 17 00
	329	0 06 07		82	0 36 00
	332	0 02 02		83	0 38 00
	333	0 05 06		84	0 07 00
	328	0 25 29		108	0 19 00
	326/1	0 14 16		107	0 65 00
	324	0 04 05		106	0 19 00
	325	0 31 36		122	0 10 00
	321	0 46 54		121	0 19 00
	483/पी/1	0 18 21		132	0 34 00
मोडा	483/पी/2	0 22 26		136	0 08 00
	316	0 27 32		135	0 12 00
	317	0 44 52		138	0 27 00
	223	0 24 28		139	0 37 00
	221	0 30 35	त माथान	190	0 29 00
	220/पी/1	0 17 20	वीरपार	139	0 46 00
	220/पी/2	0 16 19		136	0 02 00
	215	0 32 37		138	0 25 00
	205	0 23 27		137	0 08 00
	206	0 46 54		134	0 16 00
	207	0 22 26		133	0 55 00
	201	0 27 32		88	0 20 00
	197	0 39 46		89	0 18 00
	194/पी/1	0 17 20		90	0 14 00
	194/पी/2	0 24 28		84	0 18 00
	193	0 20 23		91	0 08 00
	191	1 24 44		92	0 32 00
	147	0 27 32		81	0 21 00
	148	0 33 39		80	0 56 00
	150	0 38 45		79	0 15 00
	152	0 41 48		78	0 36 00
चावडा	73	0 28 62		76	0 32 00
	71	0 27 43		61	0 23 00
	70	0 06 22		62	0 37 00
	68	0 18 11		64	0 58 00
	66	0 25 24		65	0 45 00
	63/2	0 23 14		66	0 65 00
	48/2	0 29 54			
	49/2	0 37 03			

S. O. 3030.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from **Salaya Port** in **Gujarat** to Mathura in **Uttar Pradesh** Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation, Limited.

AND WHEREAS it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein;

PROVIDED THAT any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B, Harihar Society, Rajkot.

AND every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

[No 120 17/3/74/ L & L/X]

SCHEDULE

Taluka: Jamnagar District: Jamnagar
Gujarat State

Village	Survey No.	Extent		
		H.	A.	Sq. M.
MORKANDA	231	0	15	00
	216	0	16	00
	213	0	35	00
	212	0	05	00
	142	0	26	00
	143/2	0	07	00
	144	0	09	00
	145/1	0	22	00
	145/2	0	18	00
	156	0	55	00
	157	0	00	08
	192	0	37	00
	193	0	14	00
	194	0	00	06
	191/1	0	30	00
	191/2	0	19	00
	185	0	72	00
	174/1	0	31	00
	179	0	27	00
	180	0	36	00
THEBA	181 P/1	0	31	36
	181 P/2	0	27	32
	180	0	44	52
	179	0	34	36
	178	0	27	32
	108	0	21	25
	106	0	14	16
	94	0	59	69
	83	0	12	14

1	2	3
MOTA THAVARIA	335	0 14 00
	336	0 35 00
	342	0 23 00
	324	0 40 00
	323	0 32 00
	319	0 47 00
	312	0 01 00
	316	0 33 00
	315	0 61 00
	400 P	0 15 00
	305	0 39 00
	290	0 03 00
	291	0 31 00
	292	0 03 00
	293	0 11 00
	278	0 16 00
	265	0 27 00
	276	0 04 00
	277	0 16 00
	275	0 28 00
	267	0 06 00
	208	0 27 00
	206	0 14 00
	164/1	0 23 00
	164/2	0 13 00
	164/3	0 15 00
	165/1	0 28 00
	165/2	0 22 00
	160	0 19 00
	159	0 34 00
	157	0 11 00
	156	0 09 00
	95	0 13 00
	103	0 16 00
	104	0 09 00
	105	0 28 00
	106	0 35 00
	132	0 33 00
	131	0 30 00
	130	0 29 00
	129	0 27 00
	126	0 18 00
	138	0 08 00
	139/1	0 17 00
	139/2	0 08 00
	171	0 26 00
	170	0 20 00
	169	0 39 00
	168	0 17 00
	187	0 21 00
	165	0 34 00
	188	0 34 00
	193	0 11 00
	191	0 47 55
	206	0 08 00
	258	0 01 00

1	2	3	1	2	3
ALLIA (Contd.—)	259	0 55 00	JAMVANATHALI	75	0 16 00
	284	0 54 64		74 P/1	0 03 00
	290	0 34 40		76	0 06 00
	291	0 27 33		77	0 18 00
	292	0 54		74 P/2	0 15 00
GANGAJALA	80	0 13 49		81	0 17 00
NODA	452	0 87 00		82	0 36 00
	459	0 53 62		83	0 38 00
	465	0 03 36		84	0 07 00
	462	0 49 57		108	0 19 00
	381/1	0 25 29		107	0 65 00
	380	0 13 25		106	0 19 00
	379	0 20 00		122	0 10 00
	331/1	0 15 18		121	0 19 00
	330	0 13 15		132	0 34 00
	329	0 06 07		136	0 08 00
	332	0 02 02		135	0 12 00
	333	0 05 06		138	0 27 00
	328	0 25 29		139	0 37 00
	326/1	0 14 16	TAMACHAN	190	0 29 00
	324	0 04 05	VIRPAR	139	0 46 00
	325	0 31 36		136	0 02 00
	321	0 46 54		138	0 25 00
	483 P/1	0 18 21		137	0 08 00
	483 P/2	0 22 26		134	0 16 00
	316	0 27 32		133	0 55 00
	317	0 44 52		88	0 20 00
	223	0 24 28		89	0 18 00
	221	0 30 35		90	0 14 00
	220 P/1	0 17 20		84	0 18 00
	220 P/2	0 16 19		91	0 08 00
	215	0 32 37		92	0 32 00
	205	0 23 27		81	0 21 00
	206	0 46 54		80	0 56 00
	207	0 22 26		79	0 15 00
	201	0 27 32		78	0 36 00
	197	0 39 46		76	0 32 00
	194 P/1	0 17 20		61	0 23 00
	194 P/2	0 24 28		62	0 37 00
	193	0 20 23		64	0 58 00
	191	1 24 44		65	0 45 00
	147	0 27 32		66	0 65 00
	148	0 33 39			
	150	0 38 45			
	152	0 41 48			
CHAVDA	73	0 28 62			
	71	0 27 43			
	70	0 06 22			
	68	0 18 11			
	66	0 25 24			
	63/2	0 23 14			
	48/2	0 29 54			
	49/2	0 37 03			
	37 P/1	0 29 90			
	37 P/2	0 30 54			
	39/1	0 17 83			
	39/2	0 30 00			

[No. 12017/3/74-L&L/X]

का० आ० 3031.—यस् केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पन्न से उत्तर प्रवेश में मथुरा तक पैदलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय तेल निगम लिंग द्वारा बिलाई जानी चाहिए।

और यह: ऐसी साइनों को बिलाने के प्रयोजन के लिए एतदुपायम प्रनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार प्रदित्त करना प्राप्तव्यक है:

प्रतः, भूमि, पट्टोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के प्रधिकार का अंजेन) प्रश्नियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग न करते हुए केवल सरकार ने उसमें उपयोग का प्रधिकार प्रतित करने का मतना प्राप्त एवं द्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लिंग, सलाया-कोयाली/मधुग पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "डोली"-33 बी, हरिहर सोसाइटी, राजकोट को इस प्रधिकारण की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टः यह भी कथन करेगा कि वह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगतः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

मनुसूची

प्राप्ति वाचकी	तालुका : जामनगर	जिला : जामनगर	गुजरात-राज्य		
			प्राप्ति	सर्वेक्षण संख्या	लेन्ड
1	2	3	एच	ए	वर्ग मीटर
मोरी चावडी	29 फी	0	12	32	
	572	0	19	20	सापर
	25 फी/1	0	40	81	
	25 फी/2	0	28	01	
	21	0	16	67	
	20	0	13	70	
	19 फी/1	0	39	89	
	19 फी/2	0	15	97	
	46 फी	0	14	09	
	15	0	49	78	
	14	0	35	87	
	10	0	30	01	
	586	0	38	98	भ्रमरा
	602	0	31	66	
	176/2	0	16	19	
	176/1	0	26	33	
	179	0	22	33	
	249	0	29	51	
	248	0	10	80	
	250 फी	0	01	12	
	247/1	0	30	52	
	251/1	0	21	00	
	252	0	14	14	
	237	0	06	43	
	128	0	05	44	
	238	0	15	42	
	239	0	03	48	

1	2	3
240	0	08 21
256	0	14 70
257/1	0	33 12
268	0	03 45
269	0	42 83
270	0	12 65
371	0	05 03
272	0	05 30
277 फी	0	07 69
278	0	11 80
280	0	37 25
283	0	00 63
284	0	09 52
285	0	18 90
345	0	00 58
347	0	21 59
349/1	0	18 71
344/फी/1	0	04 32
344/फी/2	0	19 63
344/फी/3	0	19 40
344/फी/4	0	19 25
322/फी	0	25 92
342/फी	0	37 80
32	0	11 13
33	0	04 05
34	0	27 32
69	0	20 23
68	0	22 26
74	0	51 60
91/2	0	06 07
90	0	16 19
86	0	27 32
84	0	40 48
109	0	15 18
124/1	0	29 32
495	0	32 37
494	0	24 27
498	0	41 48
499	0	23 28
504	0	24 27
501	0	16 19
502	0	28 33
503	0	12 15
518	0	38 45
519	0	08 10
521	0	20 23
517	0	01 01
515	0	41 48
514	0	09 11
513	0	09 11

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
अमर-जारी	581	0	02	02		214	0	23	00
	582	0	09	11		226	0	59	66
	583	0	21	25		229	0	27	32
	602	0	20	23		246	0	20	26
	63/1	0	18	21	नथेश्वी	1 पी	0	31	35
	58	0	16	19		187/पी/1	0	10	00
	67	0	28	33		187/पी/2	0	14	00
	3	0	08	09		4	0	04	05
	8	0	08	09		5	0	19	25
	7	0	17	20		7	0	23	30
	6	0	24	28		8	0	32	40
	31	0	02	02		11	0	07	05
	32	0	16	19		12 पी/1	0	36	35
	33	0	11	13		12 पी/2	0	18	25
	34	0	23	27	कनसुमारा	295	0	63	75
	35	0	26	30		299	0	13	20
	61	0	44	52		298	0	18	20
प्रसार्दी	17	0	22	26		8	0	26	30
	25/1	0	16	18		6/2	0	16	20
	25/2	0	52	61		6/3	0	07	00
	27	0	70	82		39	0	54	80
	28/2	0	52	61	कनसुमारा	40/2/1	0	21	30
	35	0	70	82		40/2/2	0	21	30
	36	0	22	26		69	0	14	20
	37/1	0	28	34		82	0	08	10
	37/2	0	44	51		83	0	33	40
	39/3	0	72	84		68	0	17	20
	39/2	0	09	10		67	0	17	20
	39/1	0	01	01		66	0	15	20
राजस्थान	2	0	24	00		73	0	27	40
	3 पी	0	22	26		74/पी/1	0	27	30
	57	0	09	11		74/पी/2	0	22	25
	54	0	05	06	जामनगर	1327	0	35	25
	53	0	08	09		1303	0	23	99
	60	0	10	12		1302	0	30	94
	61	0	20	23		1295	0	52	00
	62	0	36	00		1199	0	15	75
	64	0	20	27		1227	0	11	17
लखा चाष्ठी	129/1	0	11	13		1200 पी/1	0	45	19
	129/2	0	08	09		1200 पी/2	0	16	01
	129/3	0	27	32		1211	0	04	41
	129/4	0	22	26		1210	0	04	16
	129/5	0	25	29		1207	0	02.	16
	129/6	0	63	74		1208	0	49	56
	128	0	21	00		1209	0	10	99
	143	0	29	43		1205	0	32	96
	146	0	34	40		1115	0	26	00
	148	0	39	46		1116	0	09	89
	168	0	58	68		1126	0	10	40
	172	0	04	05		1124	0	25	45
	213	0	37	42		973	0	06	41

1	2	3	4	5	1	2	3
जाम नगर-जारी	974	0	23	07	Moti Khavdi (Contd.)	247/1	0 30 52
	980	0	28	38		251/1	0 21 00
	981	0	28	38		252	0 14 14
	1014	0	39	18		237	0 06 43
	1016	0	36	07		128	0 05 44
	1017	0	18	49		238	0 15 42
	788/1	0	32	96		239	0 03 48
	753	0	79	47		240	0 08 21
	715	0	86	97		256	0 14 70
						257/1	0 33 12
						268	0 03 45
						269	0 42 85
						270	0 12 65
						271	0 05 03
						272	0 05 30
						277 P.	0 07 69
						278	0 11 80
						280	0 37 25
						283	0 00 63
						284	0 09 52
						285	0 18 90
						345	0 00 58
						347	0 21 59
						349/1	0 18 71
						344 P/1	0 04 32
						344 P/2	0 19 63
						344 P/3	0 19 40
						344 P/4	0 19 25
						322 P.	0 25 92
						342 P.	0 37 80
					Sapar	32	0 11 13
						33	0 04 05
						34	0 27 32
						69	0 20 23
						68	0 22 26
						74	0 51 60
						91/2	0 06 07
						90	0 16 19
						86	0 27 32
						84	0 40 48
						109	0 15 18
						124/1	0 29 32
Moti Khavdi	29 P.	0	12	32		495	0 32 37
	572	0	19	20		494	0 24 27
	25 P/1	0	40	81	Amra	498	0 41 48
	25 P/2	0	28	01		499	0 23 28
	21	0	16	67		504	0 24 27
	20	0	13	70		501	0 16 19
	19 P/1	0	39	89		502	0 28 33
	19 P/2	0	15	97		503	0 12 15
	46 P	0	14	09		518	0 38 45
	15	0	49	78		519	0 08 10
	14	0	35	27		521	0 20 23
	10	0	30	01		517	0 01 01
	586	0	38	98		515	0 41 48
	602	0	31	66		514	0 09 11
	176/2	0	16	19		513	0 09 11
	176/1	0	26	35		581	0 02 02
	179	0	22	33		582	0 09 11
	249	0	29	51		583	0 21 25
	248	0	10	80			
	250 P.	0	01	12			

[संख्या 12017/3/74-एन० तथा एन०/XI]

S.O. 3031.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its Intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali-Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B. Harihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka:Jamnagar	District:Jamnagar	Gujarat	State	
Village	Survey No.	Extent		
		H.	A.	
		Sq.	M.	
1	2	3		
Moti Khavdi	29 P.	0	12	32
	572	0	19	20
	25 P/1	0	40	81
	25 P/2	0	28	01
	21	0	16	67
	20	0	13	70
	19 P/1	0	39	89
	19 P/2	0	15	97
	46 P	0	14	09
	15	0	49	78
	14	0	35	27
	10	0	30	01
	586	0	38	98
	602	0	31	66
	176/2	0	16	19
	176/1	0	26	35
	179	0	22	33
	249	0	29	51
	248	0	10	80
	250 P.	0	01	12

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Amra (contd.)	602	0	20	23		11	0	07	05
	63/1	0	18	21		12P/1	0	36	35
	68	0	16	19		12P/2	0	18	25
	67	0	28	33	Kansumara	295	0	63	75
	3	0	08	09		299	0	13	20
	8	0	08	09		298	0	18	20
	7	0	17	20		8	0	26	30
	6	0	24	28		6/2	0	16	20
	31	0	02	02		6/3	0	07	00
	32	0	16	19		39	0	54	80
	33	0	11	13		40/2/1	0	21	30
	34	0	23	27		40/2/2	0	21	30
	35	0	26	30		69	0	14	20
	61	0	44	52		62	0	08	10
Vasai	17	0	22	26		63	0	33	40
	25/1	0	16	18		68	0	17	20
	25/2	0	52	61		67	0	17	20
	27	0	70	82		66	0	15	20
	28/2	0	52	61		73	0	27	40
	35	0	70	82		74P/1	0	27	30
	36	0	22	26		74P/2	0	22	25
	37/1	0	28	34	Jamnagar	1327	0	35	25
	37/2	0	44	51		1303	0	23	99
	39/3	0	72	84		1302	0	30	94
	39/2	0	09	10		1295	0	52	00
	93/1	0	01	01		1199	0	15	75
Ravalsar	2	0	24	00		1227	0	11	17
	3P.	0	22	26		1200P/1	0	45	19
	57	0	09	11		1200P/2	0	16	01
	54	0	05	06		1211	0	04	41
	53	0	08	09		1210	0	04	16
	60	0	10	12		1207	0	02	16
	61	0	20	23		1208	0	49	56
	62	0	36	00		1209	0	10	99
	64	0	20	27		1205	0	32	96
Lakha Baval	129/1	0	11	13		1115	0	26	00
	129/2	0	08	09		1116	0	09	89
	129/3	0	27	32		1126	0	10	40
	129/4	0	22	26		1124	0	25	45
	129/5	0	25	29		973	0	06	41
	129/6	0	63	74		974	0	23	07
	128	0	21	00		980	0	28	38
	143	0	29	43		981	0	28	38
	146	0	34	40		1014	0	39	18
	148	0	39	46		1016	0	36	07
	168	0	58	68		1017	0	18	49
	172	0	04	05		788/1	0	32	96
	213	0	37	42		753	0	79	47
	214	0	23	00		745	0	86	97
	226	0	59	66					
	229	0	27	32					
	246	0	20	26					
Naghedi	1P.	0	31	35					
	187P/1	1	10	00					
	187P2	0	14	00					
	4	0	04	05					
	5	0	19	25					
	7	0	23	30					
	8	0	32	40					

क्रा० अ० 3032--यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीक होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गृजगत राज्य में मलाया पनन से उत्तर प्रदेश में भवुरा तक पट्टोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय नेल निगम लि० द्वारा विधाई जानी जाहिये।

और यह ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोग के लिये एतदुपादेश अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का प्रधिनार भर्ति करना आवश्यक है।

मत: अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के प्रधिकार का प्राप्तन) प्रधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एवं व्यवहार घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिल्डिंग के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, मार्टीय तंत्र निगम लि० सलाया-कोयाली/मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "डोली" 33-बी०, हरिहर सोसाइटी, राजकोट को इन अधिकृतों की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

तालुका: सयाला	जिला: सुरेन्द्रनगर	गुजरात राज्य		
प्राम	सर्वेक्षण सं०	एक	भेट	वर्ग
1	2	3	4	5
धरादुंगरी	115	0	40	47
	114	0	04	05
	116	0	08	09
	117	0	22	26
	80	0	37	43
	78	0	35	41
	76	0	39	46
	74	0	24	28
	143	0	11	13
	178	0	35	42
	172	0	53	62
	161	0	59	69
हुडाला	35	4	44	14
	34	1	98	30
सितागढ़	18	0	17	20
सोरीमध्या	75	0	07	08
	76	0	17	20
	78	0	34	40
	82	0	03	04
	50	0	02	02
	48	0	25	29
	49	0	13	15
कानपुर	91	0	40	47
	92	0	72	84
	87	0	34	40
	66	0	16	19
	42	0	41	48
	41	0	02	03
	40	0	30	35
	20	0	42	49
	22	0	56	65
	24	0	09	11
	31	0	37	47

1	2	3	4	5
चोरखीर (चान०)	456 पी०/1	0	13	15
	456 पी०/2	0	18	21
	457	0	30	35
	458/1 पी०	0	18	21
	460 पी०/1	0	15	18
	460 पी०/2	0	08	09
	461	0	23	27

[मं० 12017/3/74-एस० तथा एस० /3]

S. O. 3032.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

AND WHEREAS it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of Use in the land described in the schedule annexed hereto;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its Intention to acquire the right of user therein;

PROVIDED THAT any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyal/ Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B, Harihar Society, Rajkot.

AND every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE.

Taluka:- Siyala District: Surendranagar Gujarat State.

Village.	Survey No.	Extent. H. A. Sq. M.		
1	2	3	4	5
DHARADUNGARI	115	0	40	47
	114	0	04	05
	116	0	08	09
	117	0	22	26
	80	0	37	43
	78	0	35	41
	76	0	39	46
	74	0	24	28
	143	0	11	13
	178	0	35	42
	172	0	53	62
	161	0	59	69
HADALA	35	4	44	14
	34	1	98	30
SITAGADH	18	0	17	20
SORIMBHADA	75	0	07	08
	76	0	17	20
	78	0	34	40
	82	0	03	04
	50	0	02	02
	48	0	25	29
	49	0	13	15

1	2	3	4	5
KANPUR	91	0	40	47
	92	0	72	84
	87	0	34	40
	66	0	16	19
	42	0	41	48
	41	0	02	03
	40	0	30	35
	20	0	42	49
	22	0	56	65
	24	0	09	11
	31	0	37	47
CHORVIRA (THAN.)	456 P/1	0	13	15
	456 P/2	0	18	21
	457	0	30	35
	458 /1 P	0	18	21
	460 P/1	0	15	18
	460 P/2	0	08	09
	461	0	23	27

[No. 12017/3/74-L&L/III]

का० प्रा० 3033.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पसन्त से उत्तर प्रदेश में मधुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय तेल निगम द्वा० बिलाई जानी चाहिये।

और यतः ऐसी लाइनों को बिलाने के प्रयोजन के लिये एतदुपावद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है:

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुये केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितवद्धु कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिलाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय तेल निगम द्वा० सलाया-कोयानी/मधुरा पाइपलाइन प्रैजैक्ट, "डोली" 33-वी, हरिहर सोमायडी राजकोट को इस प्रधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह आहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

तालुका : खांभालिया	जिला : जामनगर	गुजरात राज्य
प्राम	सर्वेक्षण सं०	एच अक्षेत्र बर्ग ए मीटर
वडिनार	68/1	0 54 04
	67	0 16 94
	66	0 00 52

[संख्या 12017/3/74-एस० संथा एस०/2]

S. O. 3033.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

AND WHEREAS it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its Intention to acquire the right of user therein;

PROVIDED THAT any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali-Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B. Harihar Society, Rajkot.

AND every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka: Khamhalia	District: Jamnagar	Gujarat State
Village	Survey No.	Extent H.A. Sq. M
VADINAR	68/1	0 54 04
	67	0 16 94
	66	0 00 52

[No. 12017/3/74-L&L/II]

का० प्रा० 3034.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पसन्त से उत्तर प्रदेश में मधुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय तेल निगम द्वा० द्वारा बिलाई जानी चाहिये।

और यतः ऐसी लाइन को बिलाने के प्रयोजन के लिये एतदुपावद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है:

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुये केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितवद्धु कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिलाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम द्वा० सलाया-कोयानी/मधुरा पाइपलाइन प्रैजैक्ट, "डोली" 33-वी, हरिहर सोमायडी, राजकोट को इस प्रधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह आहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

અનુષ્ઠાનિક		ગુજરાત રાજ્ય			1	2	3	4	5	
તાલુકા : માતાર	જિલ્લા : બેઢા	સર્વેક્ષણ સં.	એચ	કોન્ટ્ર	બર્ગ	સંખ્યા	845/8	0	00	32
પ્રામ			એ	કોન્ટ્ર	બર્ગ		845/7	0	06	88
1	2	3	4	5			845/6	0	08	48
સંખ્યા		541/1	0	01	76		845/9	0	00	08
		541/2	0	20	64		845/5	0	07	20
		542	0	06	72		845/1	0	01	73
		543/એ	0	05	12		849/4	0	13	30
		543/4	0	05	12		849/3	0	15	52
		543/3	0	11	52		848	0	16	80
		543/2	0	04	00		847/3	0	00	64
		562/1	0	16	00		857/2	0	06	72
		562/2	0	10	40		868/એ	0	01	92
		563	0	21	92		869	0	08	64
		569	0	00	32		870	0	16	74
		619	0	02	88		872	0	10	70
		618	0	13	60		873	0	12	48
		610	0	02	56		874	0	12	32
		616+617	0	11	36	હેવાગાંધીબ	3/3	0	15	20
		611	0	20	48		3/1	0	05	28
		679/1	0	14	40		16/1	0	00	32
		675/4	0	05	44		6/3	0	10	56
		678	0	07	84		6/2	0	00	16
		677/1	0	00	96		6/1	0	13	28
		677/2	0	11	36		5	0	01	60
		694/7	0	12	00		7/3	0	05	76
		694/6	0	08	80		7/2	0	04	00
		694/4	0	03	68		7/1	0	09	28
		695	0	13	76		8/1+2	0	01	92
		697	0	00	80		11	0	00	20
		696	0	10	44		9	0	11	84
		783	0	00	32		57/2	0	00	48
		782/8	0	02	88		57/1	0	10	88
		782/7	0	12	64		55/2	0	02	88
		782/6	0	03	52		56/2	0	00	80
		782/3	0	16	00		56/1	0	06	08
		782/2	0	00	08		51/1	0	09	60
		781/બીં-3	0	04	61		68	0	00	20
		781/બીં-2	0	10	56		69/5	0	00	16
		781	0	08	48		69/4	0	00	04
		794	0	00	80		70/1+2	0	01	92
		780	0	01	01		71/1	0	09	12
		779/1	0	18	56		71/2	0	06	88
		779 પદતાર	0	13	02		72/1+2	0	00	72
		779/3	0	08	00		74	0	02	24
		779/2	0	00	80		73	0	12	96
		843/4	0	01	76		76	0	15	04
		843/5	0	19	32		77/4	0	07	52
		844/5	0	24	00					
		853/1	0	02	56	અન્તરોલી	49	0	12	32
		852	0	17	60		47	0	00	20

	2	3	
	48	0 25	44
	29	0 02	40
	39	0 06	00
	38	0 08	80
	30	0 14	40
	27	0 04	80
	25/3	0 00	80
	26/2	0 12	00
	26/1	0 00	20
	22	0 15	00
	24/1	0 06	88
	23	0 15	00

[संख्या 12018/3/74-एन० तथा एन०/1]

S. O. 3034.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto:

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali-Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B, Harihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka: Matar	District: Kheda	Gujarat State	
Village	Survey No.	Extent	
		H.A.	Sq. M
1	2	3	
SANDHANA	541/1	0 01	76
	541/2	0 20	64
	542	0 06	72
	543/A	0 05	12
	543/4	0 05	12
	543/3	0 11	52
	543/2	0 04	00
	562/1	0 16	00
	562/2	0 10	40
	563	0 21	92
	569	0 00	32
	619	0 02	88
	618	0 13	60
	610	0 02	56
	616+617	0 11	36
	611	0 20	48
	679/1	0 14	40
	673/4	0 05	44
	678	0 07	84
	677/1	0 00	96

	1	2	3
		677/2	0 11 36
		694/7	0 12 00
		694/6	0 08 80
		694/4	0 03 68
		695	0 13 76
		697	0 00 80
		696	0 10 44
		783	0 00 32
		782/8	0 02 88
		782/7	0 12 64
		782/6	0 03 52
		782/3	0 16 00
		782/2	0 00 08
		781/B-3	0 04 61
		781/B-2	0 10 56
		781	0 08 48
		794	0 00 80
		780	0 01 01
		779/1	0 18 56
		779 Padtar	0 13 92
		779/3	0 08 00
		779/2	0 00 80
		843/4	0 01 76
		843/5	0 19 32
		844/5	0 24 00
		853/1	0 02 56
		852	17 60
		845/8	0 00 32
		845/7	0 06 88
		845/6	0 08 48
		845/9	0 00 08
		845/5	0 07 20
		845/1	0 01 73
		849/4	0 13 30
		849/3	0 15 52
		848	0 16 80
		847/3	0 00 64
		847/2	0 06 72
		868/A	0 01 92
		869	0 08 64
		870	0 16 74
		872	0 10 70
		873	0 12 48
		874	0 12 32
		875/1	0 14 26
		876/1	0 07 20
		HAIJARABAD	
		3/3	0 15 20
		3/1	0 05 28
		16/1	0 00 32
		6/3	0 10 56
		6/2	0 00 16
		6/1	0 13 28
		5	0 01 60
		7/3	0 05 76
		7/2	0 04 00
		7/1	0 09 28
		8/1+2	0 01 92
		11	0 00 20
		9	0 11 84
		57/2	0 00 48
		57/1	0 10 88

1	2	3	1	2	3
HAIJARABAD (contd.)	55/2	0 02 88		116	0 04 95
	56/2	0 00 80		115	0 04 20
	56/1	0 06 08		114	0 06 00
	51/1	0 09 60		113	0 05 85
	68	0 00 20	देवगढ़ा	96	0 08 40
	69/5	0 00 16		100	0 10 35
	69/4	0 00 04		101	0 01 20
	70/1+2	0 01 92	बैलगाड़ी का रास्ता	0 00 75	
	71/1	0 09 12		99	0 23 25
	71/2	0 06 88		106	0 12 00
	72/1+2	0 00 72	बैलगाड़ी का रास्ता	0 00 60	
	74	0 02 24		109	0 35 05
	73	0 12 96		112	0 03 60
	76	0 15 04		119	0 00 20
	77/4	0 07 52		116	0 10 50
ANTROLI	49	0 12 32		117	0 08 10
	47	0 00 20		118	0 02 70
	48	0 25 44	बैलगाड़ी का रास्ता	0 00 75	
	29	0 02 40		0 00 00	
	39	0 06 00		0 00 00	
	38	0 08 80		0 00 00	
	30	0 14 40		0 00 00	
	27	0 04 80		0 00 00	
	25/3	0 00 80		0 00 00	
	26/2	0 12 00		0 00 00	
	26/1	0 00 20		0 00 00	
	22	0 15 00		0 00 00	
	24/1	0 06 88		0 00 00	
	23	0 15 00		0 00 00	

[No. 12017/3/74-L&L/I]

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1974

का० अ० 3035.—पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकसभा में यह प्रावधान है कि गुजरात राज्य में जी० जी० एम० सौभासण से दूध सागर डेरी तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिलाई जानी चाहिए।

2. और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वावद अमूल्यनी में वर्णित भूमि में उपयोग का प्रधिकार स्थित करना आवश्यक है।

3. अतः अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का भर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की द्वारा 3 की उप-द्वारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आण्य प्राप्त द्वारा घोषित किया है।

4. बंधते कि उक्त भूमि में हिन्दूवास कोई व्यक्ति, उस भूमि के सीधे पाइप साइन विलाने के लिए प्राश्नेप संक्षम प्राधिकारी, नेतृ तथा प्राकृतिक रौप्य आयोग, निर्माण और देवखाल प्रभाग, मकासुपुरा रोड बरोदा-9 को इस प्रभिमूलना की नामिन से 21 विनों के भीतर कर सकेगा।

5. और ऐसा आशेप करने वाला हर व्यक्ति प्रिनिविट्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह आहता है कि उभको मुनदाई व्यक्तिशः हो या किसी विषि व्यवसायी की मार्फत ।

प्रतिसंषोधी

जी जी एस सोभामण से दूध मागर डेरी तक पाठ्य लाइन बिछाने हेतु ।

રાજ્ય : ગુજરાત	જિલ્લા : મૈદાના	તાલુકા : મૈદાના
ગાંચ	અનાક સંશોધા	હૈફટર કોન્ટ સેટી એ. માર ઇં આર એ
1	2	3
પૂનાસણ	126	0 05 70
	127	0 20 85

1	2	3
	116	0 04 95
	115	0 04 20
	114	0 06 00
	113	0 05 85
देवगढ़ा	96	0 08 40
	100	0 10 35
	101	0 01 20
	देवगढ़ी का रास्ता	0 00 75
	99	0 23 25
	106	0 12 00
	देवगढ़ी का रास्ता	0 00 60
	109	0 35 05
	112	0 03 60
	119	0 00 20
	116	0 10 50
	117	0 08 10
	118	0 02 70
	देवगढ़ी का रास्ता	0 00 75
	166	0 12 30
	देवगढ़ी का रास्ता	0 00 75
	158	0 00 25
	165	0 20 55
	160	0 10 80
	288	0 01 12
	178	0 00 10
सौभासण	84	0 12 75
	83	0 03 45
	82	0 11 25
	81	0 10 50
	देवगढ़ी का रास्ता	0 00 75
	65	0 11 30
	66	0 12 30
	67	0 03 75
	69	0 00 10
	68	0 10 65
	64	0 03 75
	39	0 05 55
	60	0 04 65
	44	0 00 50
	45	0 08 40
	46/1/ए	0 04 35
	46/1/वी	0 06 00
	43	0 00 15
	47	0 11 70
	देवगढ़ी का रास्ता	0 00 90
	31	0 22 20
	देवगढ़ी का रास्ता	0 04 50
	29	0 08 85
कुक्स	276	0 08 70
	283	0 39 60
	289	0 17 20

1	2	3	1	2	3
	290	0 08 10		347/4	0 01 35
	303	0 19 35		347/3	0 01 95
	301	0 12 45		347/2	0 05 10
	302	0 03 15		347/1	0 01 50
	296	0 09 45		362	0 01 50
	बैलगाड़ी का रास्ता	0 02 25		बैलगाड़ी का रास्ता	0 04 50
	295	0 05 25		261	0 00 60
हेड्डा हानुमन्त	38	0 25 65		262	0 20 25
	42	0 00 20		250	0 09 90
	47	0 12 70		249	0 06 60
	46	0 12 90		228/1	0 13 05
	45	0 00 32		229/5	0 07 80
	43	0 02 25		230/6	0 07 50
	44/2	0 23 55		230/5	0 08 10
	44/1	0 07 95		230/2	0 14 25
	बैलगाड़ी का रास्ता	0 00 30		230/1	0 00 20
	60	0 00 15		232	0 07 95
	62	0 25 50		बैलगाड़ी का रास्ता	0 00 75
	67	0 12 00		184	0 09 30
	66	0 01 50		185/2	0 11 40
	68	0 32 25		186	0 09 30
	69	0 00 30		188	0 11 40
	71	0 08 40		168	0 11 85
	147	0 11 55		167	0 06 30
	148/2	0 01 04		32/2	0 12 30
	बैलगाड़ी का रास्ता	0 01 05		बैलगाड़ी का रास्ता	0 00 30
	230	0 27 90		33/2	0 08 40
	बैलगाड़ी का रास्ता	0 01 05		51	0 00 30
	233	0 14 25		50	0 07 20
	234	0 00 80		61	0 09 30
	238	0 25 05		57	0 04 35
	आरी नदी	0 12 75		58	0 09 00
	मागलपुर	मर्वेश्वर संक्षया		59	0 00 15
	आरी नदी	0 12 75		146	0 04 95
	412	0 03 00		145	0 08 00
	440/2	0 06 90		144	0 00 85
	441	0 01 50		74	0 09 00
	439	0 23 10		75	0 00 60
	438/1	0 07 95		76	0 16 00
	427	0 00 15		77	0 02 00
	428/2	0 12 75		133	0 00 60
	432	0 03 75		132	0 15 60
	430/2	0 12 45		131	0 03 15
	430/1	0 12 00		बैलगाड़ी का रास्ता	0 01 20
	429	0 00 96		120	0 00 50
	बैलगाड़ी का रास्ता	0 01 50		121	0 19 80
	359	0 00 72		122	0 02 70
	361	0 10 95		114	0 05 85
	बैलगाड़ी का रास्ता	0 00 75		111	0 10 80
				110	0 01 20
				विमान पत्तन	0 20 55

1	2	3	1	2	3
મહસાના	1919	0 01 50	Hebuva	117	0 80 10
	1906	0 12 60		118	0 02 70
	1907	0 05 85		Cart track	0 00 75
	1908	0 15 60		166	0 12 30
	1909	0 08 40		Cart track	0 00 75
	1915	0 02 55		158	0 00 25
	1914	0 09 00		165	0 20 55
	1911	0 04 50		160	0 10 80
	1912	0 04 50		288	0 01 12
	1830	0 17 10		178	0 00 10
	1851	0 06 00	Sobhasan	84	0 12 75
				83	0 03 45
				82	0 11 25
				81	0 10 50
				Cart track	0 00 75
				65	0 11 30
				66	0 12 30
				67	0 03 75
				69	0 00 10
				68	0 10 65
				64	0 03 75
				39	0 05 55
				60	0 04 65
				44	0 00 50
				45	0 08 40
				46/1/A	0 04 35
				46/1/B	0 06 00
				43	0 00 15
				47	0 11 70
				Cart track	0 00 90
				31	0 22 20
				Cart track	0 04 50
				29	0 08 85
			Kukas	276	0 08 70
				283	0 39 60
				289	0 17 20
				290	0 08 10
				303	0 19 35
				301	0 12 45
				302	0 03 15
				296	0 09 45
				Cart track	0 02 25
				295	0 05 25
			Hedva Hanmant	38	0 25 65
				42	0 00 20
				47	0 12 70
				46	0 12 90
				45	0 00 32
				43	0 02 25
				44/2	0 23 55
				44/1	0 07 95
				Cart track	0 00 30
				60	0 00 15
				62	0 25 50
				67	0 12 00
				66	0 01 50
				68	0 32 25
				69	0 00 30
				71	0 08 40
				147	0 11 55

[Ex 12016/13/74 એલ એન્ડ એલ]

(સોન્નો પોંગુના, ઉપરાંશિબ)

New Delhi, the 7th November, 1974

S.O. 3035.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from G. G. S. Sobhasan to Dudh Sagar Dairy in Mehsana oil field Pipelines should be laid by the oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Laying Pipeline from GGS Sobhasan to Dudh Sagar Dairy
State:Gujarat District:Mehsana Taluka:Mehsana

Village	Block No.	Hec-tare	Area	Con-tare
1	2	3		
Punasan	126	0 05 70		
	127	0 20 85		
	116	0 04 95		
	115	0 04 20		
	114	0 06 00		
	113	0 05 85		
Hebuva	96	0 08 40		
	100	0 10 35		
	101	0 01 20		
	Cart track	0 00 75		
	99	0 23 25		
	106	0 12 00		
	Cart track	0 00 60		
	109	0 35 05		
	112	0 03 60		
	119	0 00 20		
	116	0 10 50		

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Hedya Hanmant—Contd	148/2	0	01	04		74	0	09	00
	Cart track	0	01	05		75	0	00	60
	230	0	27	90		76	0	16	00
	Cart track	0	01	05		77	0	02	00
	233	0	14	25		133	0	00	60
	234	0	00	80		132	0	15	60
	238	0	25	05		131	0	03	15
	Khari river	0	12	75		Cart track	0	01	20
	Survey No.					120	0	00	50
Nagalpur	Khari River	0	12	75		121	0	19	80
	442	0	03	00		122	0	02	70
	440/2	0	06	90		114	0	05	85
	441	0	01	50		111	0	10	80
	439	0	23	10		110	0	01	20
	438/1	0	07	95		Air port	0	20	55
	427	0	00	15	Mehsana	1919	0	01	50
	428/2	0	12	75		1906	0	12	60
	432	0	03	75		1907	0	05	85
	430/2	0	12	45		1908	0	15	60
	430/1	0	12	00		1909	0	08	40
	429	0	00	96		1915	0	02	55
	Cart track	0	01	50		1914	0	09	00
	359	0	00	72		1911	0	04	50
	361	0	10	95		1912	0	04	50
	Cart track	0	00	75		1830	0	17	10
	347/4	0	01	35		1851	0	06	00
	347/3	0	01	95					
	347/2	0	05	10					
	347/1	0	01	50					
	362	0	01	50					
	Cart track	0	04	50					
	261	0	00	60					
	262	0	20	26					
	250	0	09	90					
	249	0	06	60					
	228/1	0	13	05					
	229/5	0	07	80					
	230/6	0	07	50					
	230/5	0	08	10					
	230/2	0	14	25					
	230/1	0	00	20					
	232	0	07	95					
	Cart track	0	00	75					
	184	0	09	30					
	185/2	0	11	40					
	186	0	09	30					
	188	0	11	40					
	168	0	11	85					
	167	0	06	30					
	32/2	0	12	30					
	Cart track	0	00	30					
	33/2	0	08	40					
	51	0	00	30					
	50	0	07	20					
	61	0	09	30					
	57	0	04	35					
	58	0	09	00					
	59	0	00	15					
	146	0	04	95					
	145	0	08	00					
	144	0	00	85					

[No. 12016/13/74-L&L)

P. P. GUPTA, Deputy Secy.

नीवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1974

का० आ० 3036.—डाक कर्मकार (विनियोजन का विनियम) अधिनियम 1948 (1948 का 9) की धारा 5-क की उपधारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री के० के० उपल के स्थान पर श्री जे० सी० प्रगताल को बम्बई गोदी श्रम बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और उम्हें बोर्ड का प्रध्यक्ष मनोनीत करती है और भारत सरकार के भूत्पूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की प्रधिसूचना सं० आ० 3912 तारीख 20 नवम्बर, 1970 से और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, प्रार्थत—

(क) “केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य” शीर्ष के अलंकृत मद संघा० (1) के लिये निम्नलिखित मद रखे जायेगे प्रार्थत—

“(1) श्री जे० सी० प्रगताल, प्रध्यक्ष, बम्बई पत्तन ध्यास —प्रध्यक्ष”

(ख) पैरा 2 के लिए निम्नलिखित पैरा रखा जायेगा, प्रार्थत—

“(2) केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री जे० सी० प्रगताल को उक्त बोर्ड का प्रध्यक्ष मनोनीत करती है।”

[सं० 51/5/68-कार 11/पी एण्ड डी]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(Transport Wing)

New Delhi, the 31st October, 1974

S.O. 3036.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 5A of the Dock Workers Regulation of Employment Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri J. C. Agarwal to be a member of the Bombay Dock Labour Board, vice Shri K. K. Uppal and nominates him to be the Chairman of that Board and makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3912, dated the 20th November, 1970 namely :—

(a) under the heading "members representing the Central Government", for item (i), the following item shall be substituted, namely :—

"(1) Shri J. C. Agarwal, Chairman, Bombay Port Trust Chairman"

(b) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"(2) The Central Government hereby nominates Shri J. C. Agarwal as the Chairman of the said Board."

[No. 51/5/68-Fac. II/P&D]

का० आ० 3037.—कोचीन डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, उस उपधारा द्वारा यथापैक्षित, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनका उससे प्रभावित होना सम्भाष्य है और यह सूक्तना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व प्राप्त किए जाएं, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

स्कीम का प्रारूप

1.—इस स्कीम का नाम कोचीन डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1974 है।

2.—कोचीन डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में,—

(i) खण्ड 18 के अपेक्षण (i) की मद (ग) में, "60 वर्ष" अक्षेप और शब्द के स्थान पर "58 वर्ष" अक्षेप और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खण्ड 18-के परन्तुक में, "ऐसा कोई कर्मकार", शब्दों के पश्चात् "जिसने 21 जुलाई, 1972 से पूर्व सेवा में प्रवेश किया हो" शब्द और अक्षेप अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

[एस-70012/9/74-एस शी]

S.O. 3037.—The following draft of a Scheme further to amend the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period

so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This Scheme may be called the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1974.

2. In the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959—

- (i) in item (c) of sub-clause (1) of clause 18, for the figures and word "60 years" the figures and word "58 years" shall be substituted;
- (ii) in the proviso to clause 18A, after the words, "such a worker" the words, figures and letters "who had joined service prior to 21st July, 1972" shall be inserted.

[No. S-70012/9/74/LD]

का० आ० 3038.—यतः कलकत्ता डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में और संशोधन करने के लिए कलिप्य प्रारूप स्कीम, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (i) द्वारा यथापैक्षित भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, अपेक्षण (ii) तारीख 8 जून, 1974 के पृष्ठ 1499 पर भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1404, तारीख 27 मई, 1974 के अधीन प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उससे प्रभावित होना सम्भाष्य था, आक्षेप और सुझाव राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से वो मास की अवधि की समाप्ति तक आमंत्रित किए गए थे;

यतः उक्त राजपत्र जनता को 8 जून, 1974 को उपलब्ध करा दिया गया था;

प्रीर यतः केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप पर जनता की ओर से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

प्रतः यद्य, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारूप:—

- (1) इस स्कीम का नाम कलकत्ता डॉक (नियोजन का विनियमन) पांचवां संशोधन स्कीम, 1974 है।
- (2) यह राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कलकत्ता डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में, अनुसूची 1 में, पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थातः—

- (1) नौभरण कार्य, जिसमें नमक (कोयला नौभरण, कोयला बंकरिंग, यात्री-सामान और डॉक-कार्य से भिन्न) भी सम्मिलित है।

[सं० एस-70012/11/73-पी एप्लीकेशन]

S.O. 3038.—Whereas certain draft scheme further to amend the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at pages 1499-1500 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 8th June, 1974 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 1404 dated the 27th May, 1974 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette.

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 8th June, 1974;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme to amend the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, namely :—

1. Short title and commencement—(1) This Scheme may be called the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Fifth Amendment Scheme, 1974.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, in Schedule I, for paragraph (1), the following paragraph shall be substituted, namely :—

"(1) Stevedoring work, including salt, (other than coal stevedoring, coal bunkering, passenger baggages and mail work)."

[No. S-70012/11/73-P&D/LD]

नई विल्सी, 1 नवम्बर, 1974

का० आ० 3039.—डाक कर्मकार (नियोजक का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5 ए की उपधारा (3) और (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कांडला पतन न्यास के अध्यक्ष थी एन० पी० वापत की काडला डाक शम बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और उन्हें कप्तान थी० वी० सिंह के स्थान पर उक्त बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त करती है और भारत सरकार के शम, रोजगार तथा पुर्ववास मन्त्रालय (शम एवं रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० सा० आ० 3805, दिनांक 26 अक्टूबर, 1968 में निम्नलिखित और मंशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में

(1) "केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे सदस्य" शीर्ष के अन्तर्गत प्रविष्ट (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्ट रखी जाए; अर्थात् :—

"(i) श्री एन० पी० वापत, अध्यक्ष, कांडला पतन न्यास गांधी धाम",
(ii) वैरा 2 में "कप्तान ए० वी० मिह०" शब्द तथा अक्षर के स्थान पर "ए० वी० वापत" शब्द तथा अक्षर रखे जाएं।

[स० वी-17012/1/72-ए० डी]

New Delhi, the 1st November, 1974

S.O. 3039.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (4) of section 5A of the Dock Workers

(Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri N. P. Bapat, Chairman, Kandla Port Trust as a member of the Kandla Dock Labour Board and nominates him as the Chairman of the said Board vice Captain D. V. Singh and makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Dept. of Labour and Employment) No. S.O. 3805 dated the 25th October, 1968, namely :—

In the said notifications,

(i) Under the heading "Members representing the Central Government", for entry (i) the following shall be substituted namely :—

"(i) Shri N. P. Bapat, Chairman, Kandla Port Trust, Gandhidham",

(ii) In paragraph 2, for the words and letters "Capt. D. V. Singh" the words and letters "Shri N. P. Bapat" shall be substituted.

[No. V-17012/1/72-LD]

नई विल्सी, 1 नवम्बर, 1974

का० आ० 3040.—डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5-क की उपधारा (3) और (4) के साथ पहिल धारा 6-क की उपधारा (3) के अ० (च) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एम० पी० एम्ब्रोज, अध्यक्ष, मद्रास पतन न्यास को श्री आ० वाल-सुब्रह्मण्यम् की जगह अध्यक्ष मद्रास गोदी श्रम बोर्ड नियुक्त करते हैं और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 169 (ई) विनांक 25 फरवरी 1972 में और आगे निम्नलिखित सम्मोहन करती है, अर्थात् उक्त अधिसूचना में,—

(क) "केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि सदस्य" शीर्ष के अन्तर्गत मद (1) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्—
"(1) श्री एम० पी० एम्ब्रोज, अध्यक्ष, मद्रास पतन न्यास"

— अध्यक्ष

(ख) वैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित वैरा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"2. केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एम० पी० एम्ब्रोज, अध्यक्ष, मद्रास पतन न्यास को उक्त बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है।"

(स०वि-15012/1/73/पी०ए०डी०/ए०ए०डी०)

श्री० शक्तराजनगम, अवर सचिव

New Delhi, the 1st November, 1974

S.O. 3040.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 6B read with sub-section (3) and (4) of section 5A, of the Dock Workers (Re-

gulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri S. P. Ambrose, Chairman, Madras Port Trust as Chairman, Madras Dock Labour Board vice Shri R. Balasubramanian and makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Dev't. of Labour and Employment) No. S.O. 169(E), dated the 25th February, 1972, namely :—

In the said notification—

(a) under the heading "Members representing the Central Government" for item (1), the following item shall be substituted, namely :—

"(1) Shri S. P. Ambrose, Chairman, Madras Port Trust"—Chairman.

(b) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"(2) The Central Government hereby nominates Shri S. P. Ambrose, Chairman, Madras Port Trust, Madras as Chairman of the said Board."

[No. V-15012/1/73/P&D/LD]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1974

कांग्रेस 3041.—मरक्ष परिवहन नियम ग्राहितियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एन्डवारा भारत सरकार, सौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की ग्राहितियन का ० आ० सं० 255(६) दिनांक 2 मई, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त ग्राहितियन के मद (ix) में "सवस्य लोक सभा" शब्द हटा दिये जाय।

[सं० 15-टी ए जी (35)/73]

एन० ५० ए० नारायणन, अवर सचिव,

New Delhi, the 4th November, 1974

S.O. 3041.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) S. O. No. 255 (E), dated the 2nd May, 1973, namely :—

In item (ix) of the said notification, the words "Member, Lok Sabha" shall be omitted.

[No. 15-TAG(35)/73]

N. A. A. NARAYANAN, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 1974

कांग्रेस 3042.—ग्राहिति और प्रशासन सामग्री ग्राहितियम 1940 (1940 का 23) की धारा 21 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एन्डवारा (1) श्री गुणेन्द्र नाथ राय तथा (2) श्री शंकर गुप्ता ग्राहिति नियोजक केन्द्रीय ग्राहिति मानक मियंवण संगठन, पूर्वी जोन, कलकत्ता और (3) श्री हण्डजी महेश, ग्राहिति नियोजक, केन्द्रीय ग्राहिति मानक नियंवण संगठन उत्तरी जैन, गजियाबाद को उक्त ग्राहितियम के नियोजनों के लिए सम्बुद्ध भारत के लिए नियोजित करते हैं।

[मं० 11031/8/73-टी० एण्ड एम०एस०]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 9th October, 1974.

S.O. 3042.—In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) the Central Government hereby appoints (1) Shri Gunendra Nath Ray and (2) Shri Shankar Gupta, Drugs Inspectors, Central Drugs Standard Control Organisation, East Zone, Calcutta and (3) Shri Inderjit Sehgal, Drugs Inspector, Central Drugs Standard Control Organisation, North Zone, Ghaziabad, as Inspectors for the purposes of the said Act for the whole of India.

[No. 11031/8/73-D&MS]

कांग्रेस 3043.—संविधान के प्रत्यक्षेत्र 239 के खण्ड (i) के ग्रन्तसरण में राष्ट्रपति एतद्वारा नियोग देते हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्य ग्राम्यक प्रबलमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, दमन और दीवा, पांडिचेरी राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यक्षीन रहते हुए और ग्राम्यमी आवेदों तक प्रयोग संबंधित जेनरों के प्रबन्दर भीषण एवं प्रसाधन सामग्री ग्राहितियम 1940 (1940 का 23) की धारा 33अ०, 33इ०, 33च०, और 33ए० के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और उसके कार्यों का निर्वहन करेंगे।

[सं० 11035/34/74-टी० एण्ड एम० एस०]

सती नायर, अवर सचिव

S.O. 3043.—In pursuance of the clause (1) of article 239 of the constitution the President hereby directs that the Lieutenant Governor of Delhi and Chief Commissioner, the Andaman and Nicobar Islands, Goa, Daman and diu, Pandicherry shall subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of State Government under Section 33D, 33E, 33F and 33G of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), within their respective Union territories.

[No. 11035/34/74-D&MS]

MRS. SATHI NAIR, Under Secy.

हृषि मंत्रालय

(ज्ञात्य विभाग)

ग्राहिति

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 1974

कांग्रेस 3044.—केन्द्रीय सरकार, ग्राहिति वस्तु ग्राहितियम 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कल-उत्पाद ग्राहिति, 1955 में ग्राहिति संशोधन करने के लिए नियोजित ग्राहिति करती है, अर्थात् :—

1 इस प्रावेश का नाम फल-उत्पाद (संशोधन) प्रावेश, 1974 है।

2 फल उत्पाद प्रावेश, 1955 की वित्तीय अनुमति में, भाग 22 में,

(क) पैरा 2 और नदीन मार्गणी के स्थान पर, निम्नलिखित रक्त जायेगा, अर्थात् —

“(2) ऐसे कोलनार रजक, जो उपयोग में लाये जा सके—निम्नलिखित के सिवाय, किसी कोलनार रजक या उसके मिश्रण का उपयोग फल-उत्पादों में नहीं किया जायेगा —

रंग	सामान्य नाम	रंग प्रत्यक्ष	रसायन-रंग मणिका
(1956)			
लाल	पानसिंहो 4 प्रार	16255	पेंजो
	फारमोइसीन	14720	“
	फास्ट रेड ई	16045	“
	ऐमरेंट	16185	“
	ऐरीधोसीन	45430	जीथीन
पील	टैटारजीन	19140	पिराजीलोन
	मनसेट यंगो एफ सी एफ	15985	ऐज्जो
नीला	इंडिगो कार्मीन	73015	इंडिगोइल
	ब्रिलिएट ब्लू	42090	ट्रायरिलमेथेन
हरा	श्रीन एस	44090	ट्रायरिलमेथेन
	फास्ट श्रीन	42033	“
	एफ सी एफ		

(क) पैरा (3) में, अत में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात् — “केवल वही अनुक्रात कोलनार रंग, जो भारतीय मानक सत्त्वा प्रमानन के अधीन बेचे जाने हैं, फल उत्पादों के विनियोग में उपयोग में लाए जाएंगे”।

[मं० 9(4)/7-एफ०एन०बी० 4]
मार० एम० मरीन, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi 20th October, 1974

S O , 3044 —In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) the Central Government hereby makes the following order further to amend the Fruit Products Order 1955 namely—

1 This Order may be called the Fruit Products (Amendment) Order, 1974

2 In the Second Schedule to the Fruit Products Order, 1955, in Part XXII,

(a) for paragraph (2) and the Table thereunder, the following shall be substituted, namely—

(2) Coal tar dyes which may be used—No Coal tar dyes or a mixture thereof except the following shall be used in fruit products—

Colour	Common name	Colour Index	Chemical class
(1956)			
Red	Ponceau 4R Carmoisine Fast Red F Amaranth Erythrosine	16255 14720 16045 16185 45430	Azo “ “ “ Xanthene
Yellow	Tartarzine Sunset Yellow FCF	19140 15985	Pyrazolone Azo
Blue	Indigo Carmine Brilliant blue FCF	73015 42090	Indigoid Irrityl Methane
Green	Green S Fast Green FCF	44090 42033	-do- -do

(b) in paragraph (3), the following shall be added at the end, namely :

“only those permitted coal tar colours, which are sold under the Indian Standards Institution Certification Mark shall be used in the manufacture of fruit products”

[No 9(4)73-FNB IV]

R S SARIN, Under Secy

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 2nd November, 1974

S.O. 3045.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Hyderabad-I, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Post Office Kothagudem Collieries (Andhra Pradesh), and their workmen which was received by the Central Government on the 30th October, 1974

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

Industrial Dispute No 74 of 1971

BETWEEN

Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Collieries.

AND

The Management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Collieries

Appearances :

Sri M Komaraiah, General Secretary, S C Workers Union, for Workmen

Sri V Gopal Sastri, Asst Personnel Officer, S C Co Ltd, Kothagudem, for Management

AWARD

The Government of India in Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) through Notification No L/2112/25/71 LRII dated 22-10-1971 referred the industrial dispute between the Employers in relation to the Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem and their Workmen, under Section 10(1)(d) and Section 7A of the Industrial Disputes Act, 1947 (which would hereinafter be called the Act) for adjudication by the Tribunal on the following issue.

"Whether the action of the management of Singareni Collieries Company Limited in not granting Category-V wages to Sarvasri Sk. Masthan, Noorul Rahiman, M. Dharma Raj, T. Venkateswari and Sofi Welders, is justified, if not, to what relief are the said workmen entitled?"

2. The reference was registered as Industrial Dispute No. 74 of 1971 and notices were directed to the Workmen and the Management. On behalf of the Workmen a claims statement is filed by the General Secretary, Singareni Collieries Workers' Union, Kothagudem. It was inter alia alleged that as per the Wage Board Recommendations no Welders should get less than Category-V wages but the Management while implementing the recommendations gave new Category-IV wages to all the Welders in all the Divisions instead of new Category-V wages. Thus the five workmen mentioned in the reference are said to have been Category-IV wage instead of Category-V wages. These five workmen are said to be qualified Welders and are working independently on the jobs allotted to them either as Electrical Welders or in Gas Welding Section. It is reiterated that as per Appendix-V of the Wage Board Recommendations under Item Time Rated Categories/designations and job description no Welders should get less than Category-V wages. The minimum starting pay of Welders is said to have been shown at serial No. 17 of Category-V. These Welders are said to have been working independently and were so found doing when the Assistant Labour Commissioner, Vijayawada made a spot check in the presence of the Management. Thus the demand for Category-V wages to these five workmen was sought to be justified.

3. In the counter filed by the Management it is inter alia urged that the present dispute is untenable in the light of the reference in Industrial Dispute No. 30 of 1967 wherein the modifications and changes in the various categories were referred for adjudication in the light of the Wage Board Recommendations as well as the agreements contained in paras 3 to 7 of Chapter IX of the Report relating to Andhra Pradesh. It is urged that while evolving a uniform wage structure for Coal Industry, the Wage Board took note of some differences in job description and job nomenclature in Singareni Collieries and with a view to resolve the differences deputed a Sub-Committee which assisted the parties to arrive at an agreed categorisation in respect of some jobs including Tradesmen. The discussion and the Agreements reached therein are said to have been referred to in paras 3 to 7 of Chapter IX of the Wage Board's report. The Wage Board directed that the categorisation applicable to Singareni Collieries is subject to these Board agreements. The agreement reached in respect of Tradesmen and Artisans is that workers in Categories-IV and V should be allotted to new Category-4, workers in Categories-VI and VII shall be allotted new Category-5, and workers in Categories-VIII and IX shall be allotted new Category 6. The Welders are said to be covered by this Agreement. It is thus contended that the agreement cannot be reopened and a claim for higher category with regard to Welders cannot be made on the basis adopted for allotment of new Categories in Bengal and Bihar. Thus the placement of five workmen in New Category-IV is said to be strictly in conformity with the agreement. Thus the agreements which were taken note of by the Wage Board are said to be conclusive. In fact it is contended that even the reference in Industrial Dispute No. 30 of 1967 specifically refers to the modifications and changes in categorisation subject to these agreements. Thus the claim in I.D. No. 30 of 1967 is said to cover the Welders also. This reference is therefore said to be bad in law and would fore-stall the decision in I.D. No. 30 of 1967. The other contention is that Company is running heavy loss year after year and it is not possible to meet the new demands for higher categorisation. The job description and job nomenclature of Welders under the Coal Award and the Wage Board are said to be identical. The Coal Award placed Welders in Old Categories-VII and IX which are equivalent to new Categories-5 and 6. Under the Tradesmen agreement of 1961 when more number of mines were working at Kothagudem it was agreed to have one Master-Grade Welder, one Welder in old Category VIII (which is equivalent to new Category 6) and two in old Category VII (which is equivalent to new Category 5). Thus the requirement of the Management is said to be two Welders in new Category 6 and two Welders in new Category 5. As against this strength provided, there are said to be at present three Welders in new Category 6 and five Welders in new Category 5.

4. On behalf of the Workmen W.W. 1 to W.W. 4 were examined in oral evidence and Exs. W1 to W16 are marked in documentary evidence. In rebuttal M.W. 1 is examined and Exs. M1 to M4 are marked by way of documentary evidence.

5. During the enquiry the parties reported that this dispute along with various other demands were referred to the Hon'ble Minister for Labour of the Central Government for his decision. They sought time awaiting his decision. On 7-6-1974 a joint Memo is filed by the parties to the effect that an award in terms of the Settlement be passed. A copy of the decision of the Hon'ble Minister is also made available to the Tribunal. It is seen that a decision is given with regard to various categories and demands numbering 84 in all. The cases of Welders is said to be covered by item Nos. 13 and 43 of the said decision. A perusal of the Settlement would disclose that all the five workmen mentioned in the reference are given Category V with effect from 1st June, 1974. This Settlement is signed by the General Secretary of the Union which was espousing the cause of the five workmen. The Settlement has also been recorded on 16-9-1974. Incidentally the General Secretary of Tandur Coal Mines Labour Union who was also present reported no objection. Before accepting a Settlement as the basis of an award the Tribunal has to examine whether the terms of the Settlement are fair and reasonable. It can however be noted that the decision given by the Hon'ble Minister which covers matters that are the subject matter in I.D. No. 30 of 1967 is a comprehensive one. I need not even advert to the question of reasonableness or fairness of this Settlement for the obvious reason that the demand of the five workmen mentioned in the reference is substantially met by the Management. It cannot for a moment be said that the

Settlement is in any way prejudicial to the interest of the Workmen. It is true that there is a clause in the Settlement with regard to the liability of the workmen to be transferred to any Division as and where vacancies are available, but that clause cannot be said to be in any way against the interest of the workmen. Since the demand of the workmen is substantially met no question of the Settlement being reasonable or fair would arise in the circumstances. In this view of the matter the Settlement can be accepted as the basis of an award.

5. In the result, award is passed in terms of the Settlement. A copy of the Settlement be enclosed to this Award.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal this the 20th day of September, 1974.

Appendix of Evidence

Witness examined for Workmen.	Witness examined for Management.
W.W. 1 Shaik Mastan	M.W. 1 V. R. Sunder Rajan
W.W. 2 G. Papaiah	
W.W. 3 M. Dharmaraju	
W.W. 4 C. R. Dhanraj	

Documents exhibited for Workmen

- Ex. W1 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 3-1-1972.
- Ex. W2 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 1-4-1972.
- Ex. W3 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 6-4-1972.
- Ex. W4 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 16-4-1972.
- Ex. W5 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 12-4-1972.
- Ex. W6 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 15-4-1972.
- Ex. W7 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 21-4-1972.
- Ex. W8 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 22-4-1972.
- Ex. W9 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 26-4-1972.
- Ex. W10 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 27-4-1972.
- Ex. W11 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 3-5-1972.
- Ex. W12 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 11-5-1972.
- Ex. W13 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 25-5-1972.
- Ex. W14 Gate pass issued by the Management to Sri Shaik Mastan on 30-5-1972.
- Ex. W15 Work allocation register showing the work done by the Welders and carpenters during the period 27-5-1969 to 19-7-1967.
- Ex. W15(a) Marked portion showing the work done by Sri Laxmaiah in the 1st shift on 29-5-1969 at page 13 of the work allocation register i. e. Ex. W. 15.

Ex. W15(b) Marked portion showing the work done by Sri Mastan and Noorul Rehman in the 2nd shift on 29-5-1969 at page 13 of the work allocation register i.e. Ex. W. 15.

Ex. W15(c) Marked portion showing the work done by Sri Laxmaiah on 30-5-1969 at page 19 of the work allocation register i.e. Ex. W.15.

Ex. W15(d) Marked portion showing the work done by Sri Mastan in the 2nd shift on 30-5-1969 at page 19 of the work allocation register i.e. Ex. W.15.

Ex. W(e) Marked portion showing the work done by Sri Nurul Rehman on 30-5-1969 at page 19 of the work allocation register i.e. Ex. W. 15.

Ex. W15(f) Marked portion showing the work done by Sri Iyulu on 2-6-1969 at page 29 of the work allocation register i.e. Ex. W. 15.

Ex. W15(g) Marked portion showing the work done by Sri Mastan in 2nd shift on 3-6-1969 at page 29 of the work allocation register i.e. Ex. W. 15.

Ex. W15(h) Marked portion showing the work done by Sri Nurul Rahiman and Sri T. Venkateswar Rao on 3-5-1969 at page 35 of the work allocation register i.e. Ex. W. 15.

Ex. W15(i) Marked portion showing the work done by Sri Laxmaiah in the 2nd shift on 3-6-1969 at page 35 of the work allocation register i.e. Ex. W.15.

Ex. W15(j) Marked portion showing the work done by Sri Mastan on 3-6-1969 at page 35 of the work allocation register i.e. Ex. W. 15.

Ex. W16. Work allocation register showing the work done by the carpenters and welders etc., for the period 10-4-1969 to 24-5-1969.

Documents exhibited for Management

- Ex. M1 Copy of the Tradesmen agreement dt. 3-2-1961.
- Ex. M2 Copy of the Award of the Industrial Tribunal, Andhra Pradesh, Hyderabad in I.D. Nos. 38 & 48 of 1968 dt. 16-8-1969.

Ex. M3 Copy of the Award of the Industrial Tribunal, Andhra Pradesh, Hyderabad in I.D. No. 66/64 dt. 26-6-1967.

Ex. M4 Memoandum of Settlement arrived at between the Management of Singareni Collieries company Limited, Kothagudem and their workmen represented by the A. P. Colliery Mazdoor Sangh, Kothagudem in I.D. No. 17/66 dt. 6-10-1967.

Sd/-

INDUSTRIAL TRIBUNAL.

MEMORANDUM OF SETTLEMENT ARRIVED AT UNDER SECTION 18(1) OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT 1947 BETWEEN THE MANAGEMENT OF THE SINGARENI COLLIERIES COMPANY LIMITED AND THEIR WORKMEN REPRESENTED BY THE SINGARENI COLLIERIES WORKERS' UNION ON 7TH JUNE, 1974 AT KOTHAGUDEM.

Parties Present :

Representing Management : Representing Workmen :

(Singareni Collieries Company Limited.)	(Singareni Collieries Workers' Union).
1. Shri M. K. V. Subbaiah, Dy. General Manager.	Shri M. Komaraiah, General Secretary.
2. Shri N. Bhaskarachary, Chief Personnel Officer.	

SHORT RECITAL OF THE CASE

The demand of the Singareni Collieries Workers' Union for placing S/Shri Sk. Mastan, Noorul Rahiman, M Dharma Raj, T. Venkateswarlu and Soh, Welders of Cat IV, Main workshop, Kothagudem in Category V was referred for adjudication to the Industrial Tribunal (Central), Hyderabad and numbered as I.D. 74/71

While the Union in their claim statement relied on the categorisation of the workers under the Wage Board in Bengal and Bihar, the Management contended that the categorisation of Tradesmen which includes Welders was discussed before the Sub Committee of the Wage Board in February 1966 as per which it was agreed that the Tradesmen in old Categories IV and V will be placed in new Cat IV under the Wage Board and the workers will have no claim to reopen these issues that a particular category of workmen would get a higher category on the basis of allotment of new categories adopted in Bengal and Bihar. The evidence in this case on both sides has been concluded and arguments are yet to be heard for passing an Award. In the meantime, the Unions have raised the issue relating to categorisation of Welders etc., in general before the Union Labour Minister demanding that they should be paid not less than Cat. V and agreed to abide by his decisions.

The claim of the workmen in dispute has been reviewed in the light of the decision of the Union Labour Minister against Demand No. 13 relating to Tradesmen and Demand No. 43 relating to Welders, Mechanics and Armature Winders etc., and Tradesmen Agreement now in force

In accordance with the Tradesmen Agreement now in force, the strength of Welders in the Main Workshops is much in excess of the requirements. As against two Welders in Cat VI and two Welders in Cat V, the present strength is two Welders in Cat VI, five Welders in Cat V and four Welders in Cat IV. Thus, there are three surplus Welders in Cat V in addition to four Cat IV Welders involved in the present dispute. Having regard to the substantial number of surplus Welders on rolls, the Management pointed out that the claim of the workmen in dispute for placing them in Cat V can only be considered against vacancies that may arise in future.

The dispute has been discussed in all its aspects and without prejudice to the relative contentions in I.D. 74 of 71, the parties have agreed as under:—

Terms of Settlement

- (1) The Management has agreed as a special case to place S/Shri Sk. Mastan, Noorul Rahiman, M Dharma Raj, T. Venkateswarlu and Soh, Welders of Cat IV, Main Workshop, Kothagudem in Cat V with effect from 1st June, 1974
- (2) These workmen are liable to be transferred to any of the workshops in any Division as and where vacancies are liable
- (3) The parties have agreed to file this Settlement as a compromise and request the Tribunal to pass an Award accordingly
- (4) The Settlement will be implemented after Award in the dispute is passed by the Tribunal

Terms of Settlement

Representing Management	Representing Workmen
Sd/- (M K V Subbarao)	Sd/- (M Komariah)
Sd/- (N Bhaskarachary)	

Witnesses

1 Sd/- (V Gopala Sastry)
Asst Personnel Officer, C P O's office
S C Co Ltd, Kothagudem

2. Sd/- (P Satyanarayana)

Office Assistant, C P O's office,
S C Co Ltd, Kothagudem

Dated 7th June, 1974

Kothagudem Collieries

TRUE COPY

T NARSING RAO, Industrial Tribunal
[No. L 21012/25/71-LR II]
LALFAK ZUALA Dy. Secy

अम मत्रालय

प्रादेश

मई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1974

का० आ० 3046 —यन केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावधि अनुसूची में विनिष्ट विषयों के बारे में मेसर्स कान्टीनेन्टल कस्ट्रक्शन (प्राइवेट) लिमिटेड, विशाखापत्तनम के प्रबन्धतत्र से सम्बन्धित नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यन केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना चाहनी चाहती है,

अत यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी थी टी० नगरामिहू राव होंगे जिनका मुख्यालय हैदराबाद होगा और उक्त विवाद का उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूचि

यह मेसर्स कान्टीनेन्टल कस्ट्रक्शन (प्राइवेट) लिमिटेड, विशाखापत्तनम का मस्टर रोल कर्मकारों को वर्ष 1971 के लिए और दैनिक मजदूरी तथा मस्टर रोल कर्मकारों को वर्ष 1972 तथा 1973 के लिए बोनस न देना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो ये कर्मकार किस प्रकार के हफदार हैं?

[स० एन-34011/14/74 पी टी/गी एम टी]

ORDER

New Delhi, the 19th October, 1974

S O. 3046.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Continental Construction (Private) Limited, Visakhapatnam and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed,

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Narsing Rao shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether Messrs. Continental Construction (Private) Limited, Visakhapatnam are justified in denying payment of bonus to muster roll workers for the year 1971 and to duly rated and muster roll workers for the years 1972 and 1973? If not at what rate are these workmen entitled?

[No L-34011/14/74-PD/CMT]

New Delhi, the 7th November, 1974

S.O. 3047.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs International Construction Corporation, Karanja and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd October, 1974.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, BOMBAY.

Reference No. CIT-7 of 1971

Parties :—

Employers in relation to the management of M/s. International Construction Corporation, Karanja.

and

then workmen.

Appearances .

For the employers—Shri S. A. Sanzaghi, Advocate
For the workmen—Miss S. V. Navalkar, General Secretary

State.—Maharashtra Industry—Major Ports and Docks.
Bombay, dated 20th September, 1974

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation Department of Labour and Employment have in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by their Order No. I 290/11/33/71-LR-IV dated 22-10-1971 referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Messrs International Construction Corporation, Karanja and their workmen in respect of the matters specified in the following schedule.—

SCHEDULE

"Whether the workmen of Messrs. International Construction Corporation, Karanja Uran are entitled to any compensation for the strike period commencing from the 7th August, 1971? If so, with what details?"

2. Messrs. International Construction Corporation the employers in this reference had raised a preliminary objection challenging the validity and competence of the reference and jurisdiction of this Tribunal. My learned predecessors by his order dated 26th February 1973 had held that the work done by the employers was in relation to a major port and the dispute concerns an industry carried on by the Central Government and it concerned a major port and hence the Central Government was the appropriate Government to make the reference and this Tribunal had jurisdiction.

3. The United Labour Union representing the workmen by their statement of claim stated that the company employed more than 125 workmen in various categories; that the wages normally paid to the workmen on the 7th of each month were not paid for the month of July 1971 till August 11

1971 and consequently the workmen started their demonstration from 9-8-1971. The company it is contended put up a notice that non-payment period will be treated as lay-off and wages would be paid accordingly. It is submitted that during the demonstration wages for the period of July 1971 were paid but subsequent wages were not paid. It is further submitted that the workmen demanded full wages from 7th to 11th August 1971 and the matter was referred to the Assistant Labour Commissioner (Central), Bombay. But the management was adamant and the agitation continued. The workmen it is contended were prepared to resume work on completion of the conciliation proceedings, but the management refused to provide work. The strike therefore continued and according to the union their action was legal. The Union further contends that on 25-12-1971 the company issued notices to the workmen informing that their services were not required because the principal company M/s. Ivan Milutinovic Pim were not supplying raw materials and were not paying the company's dues. The company thus abruptly retrenched the workmen and the union's case is that it was illegal unjust and malafide. The workmen therefore claimed full wages from 1-8-1971 to 25th January 1972 and retrenchment compensation and notice pay. In a note at the end of the statement of claim it is submitted that the strike commenced after the 2nd shift on 10-8-1971 and ended on 1st shift on 10-11-1971.

4. The company by their written statement has contended that Messrs. Ivan Milutinovic Pim and Co. a company with an office in Yugoslavia and a site head office at Bombay whom they call as principal contractor was entrusted by the Government of India the work of construction of the new break water wharf at Karanja, Ujan (District Kolaba). It is submitted that the principal contractor provided stones and boulders from their quarry at Karanja to the sub-contractor, the employees herein, for the said job of breaking and crushing stones and finished materials to be supplied back to the principal contractor that under the terms of contract the principal contractor, has control and supervision for payment of wages etc. to the workmen of the sub-contractor as also security arrangements of entry into and exit from the place of work of the workmen of the sub-contractor. The company contends that the reference is not maintainable in law as the same is vague and uncertain as there was no strike on 7th August 1971. Without prejudice to the above it is submitted that the company is not a proper party as it is not responsible for payment of any dues of the workmen. Again without prejudice it is submitted that the statement of claim is not filed by the authorised person and the alleged industrial dispute is not raised by the workmen of the company. On the merits it is submitted that the alleged strike was illegal as according to the workmen the strike was caused due to the delay in payment of the monthly wages of the workmen. The strike was also in violation of an agreement dated 29-3-1971 wherein it was specified that the men would not go on strike without giving 15 days notice. According to the company payment was made to the workers on 7-8-1971 but on 9-8-1971 the workmen demonstrated that there was delay in payment and on 12-8-1971 they went on strike. The parties sought the intervention of the Labour Commissioner (Central) and as there was no settlement a failure report was submitted on 3-9-1971. Although the union was advised by the Conciliation Officer both orally and in writing to call off the strike his advice was not heeded and the conciliation ended in failure. The company by their notice dated 4-9-1971 called upon the workers to resume duty but the workmen did not respond. It is further submitted that in the meantime the principal contractor wrongfully terminated their agreement with the present company and as such the company had no alternative but to terminate the services of their workmen. The company has stated that there are only 23 workmen employed by them and not 125 as alleged by the union. They have denied that there was any delay in payment of wages as alleged; in fact because the principal contractor did not supply them with raw materials etc. the company had no option but to lay off certain workmen. The company has further denied the allegations of the union regarding non-payment of wages and announcement of lay off. It is submitted that the action of the workmen is not legal; in fact the employers by their letters dated 12th and 13th August 1971 called upon the workmen to resume duty as the strike was illegal under the agreement dated 29-3-1971. The company says that are always willing to employ the workmen as per agreement arrived at in conciliation but at times they were forced to lay off workmen as there was no raw material supplied by their principal contractor Messrs. Pim and Co.

5. In view of the pleadings of the parties the following issues arise for consideration :—

- (1) What were the number of workmen employed by International Construction Company?
- (2) What was the duration of the strike?
- (3) Whether the strike was legal and valid and if so, what is the compensation to be paid to the workmen?

After the order on the preliminary objection both the workmen and the employers examined one witness each. The workmen tendered in evidence exhibits W-1 to W-33 and the employees E-1 to E-16.

6. ISSUE No. 1.—It is stated by the workmen in their statement of claim that the International Construction Corporation employs more than 125 workmen in various categories. They have submitted a list of 89 workers. The employers on the other hand contend that there are only 23 workmen under them. In support of their claim that only 23 workmen are employed by them they have filed exhibits E-1 to E-5. It is deposed by EW-1 that in August 1971 there were 31 workmen employed by them including the Bombay office. Exhibits E-1 to E-3 are the muster rolls and exhibits E-4 and E-5 are the payment registers. The evidence placed on record does not bear out that there were 23 workmen employed by the International Construction Company. In the proceedings before the Conciliation Officer dated 26-8-1971 it is noted that the management stated that out of about 113 workmen 51 are ready to start the work and they are not attending the work because of fear of assault. In their letter dated 30-8-1971 addressed to the Assistant Labour Commissioner the employers had stated that 113 workmen were employed by the International Construction Corporation, M.J.V. Bhatt & Co., and Vasa and Co. It is stated by EW-1 that he was managing all the affairs of the I.C.C. and the other companies. M/s. Vasa & Co., and M/s. Bhatt & Co. were their sub-contractors and he was the partner of Vasa & Co., but not a partner of Bhatt & Co. Exhibit E-7 shows that EW-1 had signed the settlement on behalf of Vasa & Co. and M.J.V. Bhatt & Co. It is also clear from the materials placed on record that 113 workmen were employed by the International Construction Corporation and this issue is answered accordingly.

7. ISSUE No. 2.—The employers contend that there was no strike on 7th August but the strike commenced on 12-8-1971. It is deposed by EW-1 that on 7-8-1971 they made payments to all the hammermen as 8th was a Sunday-holiday and the mechanical staff was paid on 11-8-1971. On 12-8-1971 they received the raw material and the lay off ended but the workers did not report for duty and although the workers were asked to report for duty they continued their strike and the workers refused to work from 12-8-1971. It is stated in the letter of the United Labour Union addressed to the Assistant Labour Commissioner dated 13th August 1971 that from 9-8-1971 the workers sat down in front of their office for their salary and the management had put a notice on their notice board of the non-period as lay-off for their staff only. It appears from letter dated 27-8-1971 from the President, United Labour Union to the works Manager, Ivan Milutinovic Pim that since the payment for the month of July 1971 had not been paid on due date i.e. 7-8-1971 a section of their employees in protest to the late payment have stopped their duty on 9-8-1971 and in favour of their requisite justice all other employees joined them 11-8-1971 where as the employers in their letter dated 4-9-1971 (exhibit W-26) have adverted to their sympathetic and humanitarian attitude which they displayed to bring about a settlement and their agreement to pay the workers one hour per day wages for the strike period of 12-8-1971 to 31-8-1971. But from the oral and documentary evidence placed before me it can be concluded that the strike commenced on 9-8-1971. Now it has to be seen up to what period the strike continued. The International Construction Corporation by their letter Exhibit W-9 dated 7-12-1971 informed the Assistant Labour Commissioner that pursuant to their discussion with him on 2-12-1971 their workmen ended their illegal strike and reported on work on 7-12-1971 and they took them back on work on the same day. Similarly by exhibit W-10 dated 6-12-1971 the International Construction Corporation informed the Chief Engineer of M/s. Ivan Milutinovic Pim that they were pleased to inform them that their illegally striking workmen had agreed to resume their normal duties and hence they would be able to start their work on 7-12-1971. In the letter dated 17-11-1971 exhibit W-11 the Presi-

dent of the United Labour Union informed the Regional Labour Commissioner (Central) that all the workmen reported for duty on 10-11-1971. This fact is also borne out by the letter dated 8-11-1971 exhibit W-13 in which the General Secretary of the United Labour Union informed the Regional Labour Commissioner (Central) Bombay that the workmen reported for duty on the conclusion of the conciliation proceedings with the Assistant Labour Commissioner. It is testified by W-1 that on 2-12-1971 there was an agreement in the labour office by which the workers agreed to resume duties on 7-12-1971. Exhibit E-9 the memorandum of settlement shows that the management had already started the work with effect from 7-12-1971 and all the workmen were marked present in the muster roll. In view of this voluminous documentary and oral evidence it can safely be posited that the strike ended on 6-12-1971. The duration of the strike therefore is from 9-8-1971 to 6-12-1971.

8. It is contended by the learned Counsel on behalf of the workmen that according to the understanding reached between the union and the management they had to make payment to the workers on the 7th and 22nd of every month but the management failed to make the payment on the due dates. In the month of July they made the payment on the 10th and in the month of Aug. the payment was made on 11th. The employees had gone on strike on the 9th and the management laid off the workers on 10th and 11th August, 1971. This lay off by the employers was unjustified and illegal and the lay off was not in compliance with the statutory rules and regulations and they did not inform the Labour Commissioner about the lay-off. It is further pointed out that under exhibit E-7 the management had agreed not to declare lay-off lock-out without serving notice to that effect to the parties and authorities concerned in accordance with the procedure laid down by the appropriate statutes. But the validity of the lay-off or otherwise is not subject matter of reference before me and therefore no pronouncement on that subject is invited. The only question to be answered is whether the strike was legal.

9. ISSUE NO. 3.—In order to answer the issue reference is necessary to certain provisions of the Industrial Disputes Act. Under section 22 of the Industrial Disputes Act no person employed in a public utility service shall go on strike in breach of contract without giving to the employer notice of strike as hereinafter provided within six weeks before striking ; or within 14 days of giving such notice or before the expiry of the days of strike specified in any such notice as aforesaid; or during the pendency of any conciliation proceedings before a Conciliation Officer and seven days after the conclusion of such proceedings. Section 24 provides that a strike or lock-out shall be illegal if it is commenced or declared in contravention of section 22 or section 23 ; or it is continued in contravention of an order made under sub-section (3) of section 1 or sub-section (4-A) of section 10-A. The rest of the provisions need not be referred to as they are not relevant to our purpose. Under exhibit E-7 memorandum of settlement dated 29-3-1971 the union had agreed not to resort to direct action without serving 15 days notice to the management as prescribed under the existing rules and regulations to the effect. No notice of the strike was served on the employers either under exhibit E-7 or under section 22 of the Industrial Disputes Act which renders the strike by the employees to be illegal. There is another factor which renders the strike illegal. Admittedly conciliation proceedings were pending before the Conciliation Officer from 23-8-1971 on a request made by the workmen on 18-8-1971 and the conciliation proceedings continued till 1st September, 1971. This is borne out from the report of the Conciliation Officer. It is true that the strike had already commenced from 9-8-1971 and the conciliation proceedings had commenced on 23-8-1971. Section 24 of the Industrial Disputes Act clause (2) will not be attracted as this section will be applicable only where a strike or lock-out in pursuance of an industrial dispute had already commenced and was in existence at the time of the reference of the dispute to a Board, an Arbitrator, a Labour Court, Tribunal or National Tribunal and the continuance of the strike or lock-out shall not be deemed to be illegal. Here the reference is not to a Arbitrator or Industrial Tribunal but the dispute was referred to the Conciliation Officer. Therefore the continuance of the strike by the workmen after the Conciliation Officer was seized of the dispute i.e. from 23-8-1971 to 1st September, 1971 and during its pendency was certainly illegal and it comes within the mischief of clause (d) of section 22. Viewed in any context the conclusion is irresistible that the strike by the workmen from 9th August to 7th December, 1971 was illegal and invalid. This issue is answered accordingly.

As the strike is held to be illegal no question of awarding any compensation to the workmen arises and the reference is answered accordingly.

No order as to costs.

B. RAMLAL KISHEN, Presiding Officer.

[No. L-29011(33)/71-L.R. IV]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1974

का० आ० 3048.—यस केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स मेन्ट जोमेप्स मिशन हास्पिटल, अवन पोस्ट ऑफिस, किलोन जिला, केरल नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस भात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन से लागू किए जाने चाहिए ;

अम्. अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उआधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के मितम्बर के प्रथम दिन का प्रवृत्त हुई ममती जारी है।

[सं० एम० 35019(160)/73-पी०एफ० 2]

New Delhi, the 28th October, 1974

S.O. 3048.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs St. Joseph's Mission Hospital, Anchal Post Office, Quilon District, Kerala have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1973.

[No. S. 35019(160)/73-PF. II]

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 1974

का० आ० 3049.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री आर० पी० देवूपकर को उक्त अधिनियम और स्कीम और उसके अधीन विरचित किसी कुटुम्ब पेशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के सबूत में या किसी रेल कम्पनी, महा पतन, ज्ञान या तेज़ क्षेत्र या नियन्त्रित उत्तोग से सन्वन्धित किसी स्थापन के सबूत में या जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएँ हो, समूर्ण महाराष्ट्र राज्य के लिए नियोक्त नियुक्त करती है।

[सं० ए० 12016(3)/74-पी०एफ०-1]

New Delhi, the 30th October, 1974

S.O. 3049.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri R. P. Dewoolkar to be an Inspector for the whole of the State of Maharashtra for the purposes of the said Act, and the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A. 12016(3)/74-PF. I]

नई दिल्ली, नवीन्य 1 नवम्बर, 1974

का० आ० 3050.—कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3091 नारीश 5 मितम्बर, 1972 को अधिकार करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री ए० एम० मननाथन के स्थान पर श्री आर० एम० गोवी को, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उसके कर्तव्यों का नियंत्रण करते में सहायता देने के लिए, समूर्ण सम्युक्त प्रदेश राज्य के लिए प्रावेशिक अधिकार भविष्य नियुक्त करती है।

[सं० ए० 12016(8)/74-पी० एफ० 1(i)]

New Delhi, the 1st November, 1974

S.O. 3050.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3091, dated the 5th September, 1972, the Central Government hereby appoints Shri R. M. Gandhi as Regional Provident Fund Commissioner for the whole of the State of Madhya Pradesh to assist the Central Provident Fund Commissioner in the discharge of his duties, vice Shri A. S. Sattanathan.

[No. A-12016(8)/74-PF.I(i)]

का० आ० 3051.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेशन निधि अधिनियम, 1952 का (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3092 नारीश 5 मितम्बर, 1972 को प्रदिक्षित करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री आर० एम० गोवी को उक्त अधिनियम स्कीम और उसके अन्तर्निहित विरचित कुटुम्ब पेशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के सबूत में या किसी रेल कम्पनी, महापतन, ज्ञान या तेज़ क्षेत्र या नियन्त्रित उत्तोग में सम्बद्ध किसी स्थापन के सबूत में या किसी रेल स्थापन के सबूत में, जिसके एक से अधिक राज्यों में विभाग या शाखाएँ हो, समूर्ण महाराष्ट्र राज्य के लिए नियोक्त करती है।

[सं० ए० 12016(8)/74-पी० एफ० 1(ii)]

S.O. 3051.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3092, dated the 5th September 1972, the Central Government hereby appoints Shri R. M. Gandhi to be an Inspector for the whole of the State of Madhya Pradesh for the purposes of the said Act, the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A. 12016(8)/74-PF. I(ii)]

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1974

का० आ० 3052.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रबल मत्तियों का प्रयाग करने हुये केन्द्रीय सरकार एनद्वारा श्री एन० यिन्द्रेकटायन को उक्त अधिनियम और उसके अधीन विविध स्तीम और कुटुम्ब पेशन स्थीम के प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार के या उसके विवरणाद्वीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रूप कम्पनी महापलन, खान या तेज धोन या नियक्षित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या किसी देश स्थापन के संबंध में, जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग और शासाये हों, समूर्ध नमिनाइ राज्य और पांडितें संघीय क्षेत्र के लिये तिरोक्त नियूक करती है।

(स० ए० 12016(6)/74-पी० ए० 1)

प्रार० पी० नस्ला,
प्रबर मचिय

New Delhi, the 4th November, 1974

S.O. 3052.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri N. Thiuvenkatahan to be an Inspector for the whole of the State of Tamil Nadu and the Union territory of Pondicherry for the purposes of the said Act, and the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A. 12016(6)/74-PF. I]

R. P. NARULA, Under Secy

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1974

का० आ० 3053.—यह केन्द्रीय सरकार ने, यह गमाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित था, श्रीयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) में उपचार (vi) के परन्तु के उपचारों के अनुसरण में एक अधिसूचना भारत सरकार के अम मवालय की अधिसूचना संघा का० आ० 1141 तारीख 24 अप्रैल, 1974 द्वारा भारत सरकार टकसाल, अलीपुर, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 10 मई, 1974 से छ. मास की कालावधि के लिये शोक उपयोगी सेवा घोषित किया गया था,

और यह केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छ. मास की श्रीयोगी कालावधि के लिये बदाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब श्रीयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपचार (vi) के परन्तु के अनुसरण का प्रयाग करने हुये केन्द्रीय सरकार एनद्वारा उक्त सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 22 नवम्बर 1974 से छ. मास की और अवधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[का० स० 11025/18/74-ए० आर० 1]

New Delhi, the 1st November, 1974

S.O. 3053.—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so required, had declared by a notification made in pursuance of the provision of the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), being the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1191 dated the 30th April, 1974 service in any oilfield, to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 22nd May, 1974;

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said service to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 22nd November, 1974.

[F. No. S. 11025/18/74-LR. I]

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1974

का० आ० 3054.—यह केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित था, श्रीयोगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपचार (vi) के परन्तु के अनुसरण में एक अप्रियवृत्ति सरकार के अम मवालय की अविदूषा संघा का० आ० 1141 तारीख 24 अप्रैल, 1974 द्वारा भारत सरकार टकसाल, अलीपुर, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 10 मई, 1974 से छ. मास की कालावधि के लिये शोक उपयोगी सेवा घोषित किया गया था,

और यह केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छ. मास की श्रीयोगी कालावधि के लिये बदाया जाना अपेक्षित है,

अतः, अब श्रीयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपचार (vi) के परन्तु के अनुसरण का प्रयाग करने हुये केन्द्रीय सरकार एनद्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 10 नवम्बर, 1974 से छ. मास की और अवधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[का० स० 11025/17/74-ए० आर० 1]

ए० ए० ०८० महानामन, प्रबर मचिय

New Delhi, the 2nd November, 1974.

S.O. 3054.—Whereas the Central Government being satisfied that public interest so required, had declared by a notification made in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), being the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1141 dated the 24th April, 1974, the India Government Mint, Alipore, Calcutta, to be a public utility service for the purpose of the said Act for a period of six months from the 10th May, 1974,

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 10th November, 1974.

[F. No. S. 11025/17/74-I R. 1]

S. S. SAHARANAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1974

का० ३०५५.—जोनम संदाय प्रधिनियम, 1965 (1965 का 21) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर सभी पूर्व प्रधिसूचनाओं को अधिकान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार नीचे दी गई मारणी के स्तंभ (1) में विनिविष्ट अधिकारियों को, उसके संसम (2) में की तस्वीरी विविष्टियों में विनिविष्ट सीमाओं के भीतर, उन अधिनियम के प्रयोगों के नियमित नियुक्त करती है।

मारणी,

अधिकारी सीमाएं

(1) (2)

I. 1. मुख्य अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली।
2. उप मुख्य अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली।
3. प्रावेशिक अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली।
4. मुख्य अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय) का कल्याण-सालाहकार, नई दिल्ली।
5. महायक अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली।
6. अम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), नई दिल्ली।

सम्पूर्ण भारत।

II. 1. प्रावेशिक अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), मुम्बई।
2. मुम्बई क्षेत्र के सभी महायक अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय)।
3. मुम्बई क्षेत्र के सभी अम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)।

महाराष्ट्र राज्य और गोवा, दृष्टि और दीव तथा दादरा और नागर हवेली पंच गांव और दीव।

III. 1. प्रावेशिक अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), कलकत्ता।
2. कलकत्ता क्षेत्र के सभी महायक अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय)।
3. कलकत्ता क्षेत्र के सभी अम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)।

पश्चिमी बंगाल (बद्रीवान, बीरगम्बा बांकुरा और पुल्लिया के सिंचिल जिलों को छोड़ कर), अमम, मेघालय, सागानीड, मणिपुर और लिपुरा राज्य तथा ब्रह्मपुरान और निकोबार द्वीपमूह और मिजोराम, ग्राण्डिल प्रदेश संबंध राज्य क्षेत्र।

(1)	(2)
IV. 1. प्रावेशिक अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), महाराष्ट्र। 2. अम-प्रवर्तन के सभी महायक अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय)। 3. अम-प्रवर्तन के सभी अम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)।	नमिलनाई और कोरल राज्य तथा पांडिचेरी और लक्ष्यद्वीप संघ राज्यक्षेत्र तथा कर्नाटक, राज्य में बंगलादेश, कोलार मैसूर, माण्डवा, दुकर, कुर्ग, दक्षिण कनारा, हसन, चिकमगल, गिमोगा, चित्रवुर्ण और आंध्र प्रदेश में चित्तूर के सिंचिल जिले।
V. 1. प्रावेशिक अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), जबलपुर। 2. जबलपुर क्षेत्र के सभी सहायक अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय)। 3. जबलपुर क्षेत्र के सभी प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)। 4. जबलपुर क्षेत्र के सभी कनिष्ठ अम-नियोक्त (केन्द्रीय)।	मध्य प्रदेश राज्य
VI. 1. प्रावेशिक अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), कानपुर। 2. कानपुर क्षेत्र के सभी महायक अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय)। 3. कानपुर क्षेत्र के सभी प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)। 4. कानपुर क्षेत्र के सभी कनिष्ठ अम-नियोक्त (केन्द्रीय)।	उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्म-काशीमीर राज्य तथा दिल्ली और चण्डीगढ़ राज्य क्षेत्र।
VII. 1. प्रावेशिक अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), घनवाव। 2. घनवाव क्षेत्र के सभी महायक अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय)। 3. घनवाव क्षेत्र के सभी कनिष्ठ प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)। 4. घनवाव क्षेत्र के सभी कनिष्ठ अम-नियोक्त (केन्द्रीय)।	गिरावर राज्य
VIII. 1. प्रावेशिक अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), श्रीनगर। 2. हैवराबाद क्षेत्र के सभी सहायक अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय)। 3. हैवराबाद क्षेत्र के सभी कनिष्ठ प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)। 4. हैवराबाद क्षेत्र के सभी कनिष्ठ अम-नियोक्त (केन्द्रीय)।	कर्नाटक राज्य (बंगलादेश, कोलार मैसूर, माण्डवा, दुकर, कुर्ग, दक्षिण कनारा, हसन, चिकमगल, गिमोगा, चित्रवुर्ण के सिंचिल जिलों को छोड़ कर) और आंध्र प्रदेश (चित्तूर के सिंचिल जिले को छोड़कर)।
IX. 1. प्रावेशिक अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), अजमेर। 2. अजमेर क्षेत्र के सभी प्रावेशिक अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय)। 3. अजमेर क्षेत्र के सभी अम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)।	राजस्थान और गुजरात राज्य
X. 1. प्रावेशिक अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), आमनसोन। 2. आमनसोन क्षेत्र के सभी महायक अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय)। 3. आमनसोन क्षेत्र के सभी प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)। 4. आमनसोन क्षेत्र के सभी कनिष्ठ अम-नियोक्त (केन्द्रीय)।	पश्चिमी बंगाल राज्य में बद्रीवान, बीरगम्बा, बांकुरा और पुल्लिया जिले।
XI. 1. प्रावेशिक अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय), भुवनेश्वर। 2. भुवनेश्वर क्षेत्र के सभी महायक अम-प्रायुक्त (केन्द्रीय)। 3. भुवनेश्वर क्षेत्र के सभी अम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)।	उड़ीसा राज्य।

New Delhi, the 1st November, 1974

S. O. 3055.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 27 of the Payment of Bonus Act, 1965 (21 of 1965), and in supersession of all the previous notifications on the subject, the Central Government hereby appoints the officers specified in column (1) of the Table below, to be Inspectors for the purposes of the said Act within the limits specified in the corresponding entry in column (2) thereof:

TABLE

Officers	Limits	(1)	(2)	(1)	(2)
I.	1. Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi. 2. Deputy Chief Labour Commissioners (Central), New Delhi. 3. Regional labour Commissioners (Central), New Delhi. 4. Welfare Adviser to the Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi. 5. Assistant Labour Commissioners (Central), New Delhi. 6. Labour Enforcement Officers (Central), New Delhi.	Whole of India		VI.	1. Regional Labour Commissioner (Central), Kanpur. 2. All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Kanpur Region. 3. All Labour Enforcement Officers (Central) in the Kanpur Region. 4. All Junior Labour Inspectors (Central) in the Kanpur Region.
II.	1. Regional Labour Commissioner (Central), Bombay. 2. All Assistant Labour Commissioners (Central), in the Bombay Region. 3. All Labour Enforcement Officers (Central), in the Bombay Region.	The State of Maharashtra and the Union Territory of Goa, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.		VII.	1. Regional Labour Commissioner (Central), Dhanbad. 2. All Assistant Labour Commissioners (Central), in the Dhanbad Region. 3. All Labour Enforcement Officers (Central), in the Dhanbad Region. 4. All Junior Labour Inspectors (Central) in the Dhanbad Region.
III.	1. Regional Labour Commissioner (Central), Calcutta. 2. All Assistant Labour Commissioners (Central), in the Calcutta Region. 3. All Labour Enforcement Officers (Central), in Calcutta Region.	The States of West Bengal (excluding the Civil Districts of Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia) Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura and the Union Territories of A. Andaman, and Nicobar Islands, Mizoram and Arunachal Pradesh.		VIII.	1. Regional Labour Commissioner (Central), Hyderabad. 2. All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Hyderabad Region. 3. All Labour Enforcement Officers (Central) in the Hyderabad Region. 4. All Junior Labour Inspectors (Central) in the Hyderabad Region.
IV.	1. Regional Labour Commissioner (Central), Madras. 2. All Assistant Labour Commissioners (Central), in the Madras Region. 3. All Labour Enforcement Officers (Central) in the Madras Region.	The States of Tamil Nadu and Kerala and the Union Territories of Puducherry and Lakshadweep and the Civil Districts of Bangalore/Kolar/Mysore/Mandyra/Tumkur/Coorg/South Kanara/Hasan/Chickmagalur/Shimoga/Chitradurg in the State of Mysore and Chittoor in the State of Andhra Pradesh		IX.	1. Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer. 2. All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Ajmer Region. 3. All Labour Enforcement Officers (Central) in the Ajmer Region.
V.	1. Regional Labour Commissioner (Central), Jabalpur. 2. All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Jabalpur Region. 3. All Labour Enforcement Officers (Central) in the Jabalpur Region. 4. All Junior Labour Inspectors (Central) in the Jabalpur Region.	The State of Madhya Pradesh.		X.	1. Regional Labour Commissioner (Central), Asansol. 2. All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Asansol Region. 3. All Labour Enforcement Officers (Central) in the Asansol Region. 4. All Junior Labour Inspectors (Central) in the Asansol Region.
				XI.	1. Regional Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar. 2. All Assistant Labour Commissioners (Central), in the Bhubaneswar Region. 3. All Labour Enforcement Officers (Central) in the Bhubaneswar Region.
					The Districts of Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia in the State of West Bengal.
					The State of Orissa.

[No. S-33012/6/74-WB]

J.R. BAGCHI, Under Secy.

नई विश्वी, 4 नवम्बर, 1974

S. O. 3056.—कर्मचारी राज्य वीमा प्रधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त पत्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार के अम और पुनर्वाप संतालय (अम और रोजगार विभाग)

की अधिसूचना सं. 3222, तारीख 6 नवम्बर, 1973 के क्रम में, केन्द्रीय सरकार हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिंपरी, पूना-18 को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 9 अक्टूबर, 1974 से 8 अक्टूबर, 1975 तक, जिसमें यह दिन भी समिलित है, एक वर्ष की और अधिनियम के लिये छूट देती है।

[का० सं. 38014/55/73-प्र० आई०]

टी० ए० मूल्यांकन, अथर सचिव

New Delhi, the 4th November, 1974

S.O. 3056.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S. O. 3222 dated the 6th November, 1973 the Central Government hereby exempts Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri, Poona-18 from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 9th October, 1974 upto and inclusive of the 8th October, 1975.

[S-38014/55/73-HI]

T. S. KRISHNAMURTHI, Under Secy.

पूत्र और पुनर्वास मंत्रालय
(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, विनाक 30 प्रगत्य, 1974

का० आ० 3057.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 की 44) की धारा 34 की उपधारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के तकालीन क्रम और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) की अधिसूचना संख्या 2 (8) विशेष सेल/69-एग०एस०-4 दिनांक 15 अक्टूबर, 1973 का आंशिक संघोषन करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियों सचिव, महाराष्ट्र सरकार, राजस्व एवं वन विभाग के द्वारा भी अपने कार्यों के अन्वयावास या पूल के अन्तर्गत आने वाली भूमि तथा सम्पन्नियों के संबंध में महाराष्ट्र राज्य में प्रयोग की जा सकेगी।

[संख्या 2(8)/विशेष सेल/69-एस०एस०-4]

दीना। नाथ प्रसाद जा०, अव० सचिव

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION
(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 30th August, 1974

S.O. 3057.—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) and in partial modification of the notification No 2(8) Spl. Cell/69-SSIV dated the 15th October, 1973 of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Rehabilitation), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under section 33 of the said Act shall be exercisable also by the Secretary to the Government of Maharashtra, Revenue and Forests Department, in addition to his own duties in respect of the lands and properties within that State and forming part of the 'Compensation Pool'.

[No. 2(8)/Spl. Cell/69-SS-IV]

D. N. ASIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1974

का० आ० 3058.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर एवं पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 की 44) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निर्देश देती है कि उक्त प्राधिनियम की धारा 24 की उपधारा (4) तथा धारा 33 के अन्तर्गत प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियों पुनर्वास विभाग द्वारा निर्देशक, श्रीमती कुमुम प्रसाद द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी।

[संख्या 60011(24)/74-(1)/प्रशासन-1]
न० ब० सुन्दररामन, सचिव सचिव

New Delhi, the 8th October, 1974

S.O. 3058.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under sub-section (4) of section 24 and section 33 of the said Act shall be exercisable also by Shrimati Kusum Prasad, Director in the Department of Rehabilitation.

[No. 60011(24)/74-(i)/Admin. I]
N. V. SUNDRA RAMAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1974

का० आ० 3059.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की 44 की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त इसके द्वारा उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग कर रहे तथा गुजरात सरकार के राजस्व विभाग में कार्य कर रहे संयुक्त सचिव को उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं के अन्तर्गत उक्त मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को सीधी गई शक्तियों में से प्रयोग की जा सकती है ; अर्थात्—

(क) धारा 20 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खरीद की वकाया राशि के सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र आरी करना ;

(ख) धारा 30 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में आदेश आरी करना जिनसे भूमि के लगात की असूल करने योग्य कोई बकाया राशि हो ; और

(ग) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा व्यापार दिग्दान के लिए धारा 35, की उपधारा (2) द्वारा अवेक्षित शिकायते करना ।

[संख्या 1(6)/72-विशेष सेल/एस० एस०-4]
न० ब० सुन्दररामन, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त

ORDER

New Delhi, the 29th October, 1974

S.O. 3059.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 34 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Chief Settlement Commissioner hereby delegates to the Joint Secretary to the Government of Gujarat in the Revenue Department and exercising the powers of the Deputy Chief Settlement Commissioner, the powers conferred on the said Chief Settlement Commissioner under the following sections of the said Act, namely :—

(a) issuing a certificate under sub-section (3) of section 20 in respect of amount of purchase money remaining unpaid ;

(b) making an order under sub-section (2) of section 30, in respect of persons from whom any sum is recoverable as arrears of land revenue ; and

(c) making complaints as required by sub-section (2) of section 35 for enabling a Court to take cognisance of an offence punishable under the said Act.

[No. 1(6)/72-Spl. Cell/SS-IV]
N V SUNDRA RAMAN, Chief Settlement Commissioner

